

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 1974/चैत्र 15, 1896

No. 8] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 1974/CHAITRA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

(रक्षा मंत्रालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1974

का० नि० आ० 9-ई.—नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1-ई०, तारीख 5 जनवरी, 1966 के साथ प्रकाशित नौसेना (वेतन और भत्ते) विनियम, 1966 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन विनियमों का नाम नौसेना (वेतन और भत्ते) संशोधन, विनियम, 1974 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 15 का संशोधन.—नौसेना (वेतन और भत्ते) विनियम, 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियमों कहा गया है) में, विनियम 15 में, उप-विनियम (3) में, अंत में, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जायगा, अर्थात्:—

“टिप्पण.—जिस कार्यकारी सब-लेफ्टिनेण्ट (विशेष कार्य) (परिवीक्षाधर्जन) को, परिवीक्षा अधि को संतोषप्रद रूप से पूरा कर लेने पर और सब-लेफ्टिनेण्ट (विशेष कार्य) के पद पर प्रोन्नति के लिए हर प्रकार से उचित माना जाने पर, स्थिरीकृत कांडर में रिक्ति के उपलब्ध न होने के कारण पुष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे कार्यकारी सब-लेफ्टिनेण्ट (विशेष कार्य) (अस्थायी) के रूप में पदाभिहित किया जायगा और वह परिशिष्ट 6 में दया अधिवर्धित बतनमान में वेतन-वृद्धियों का हकदार होगा।”

3. अध्याय 4 के उप-शीर्षक का संशोधन.— उक्त विनियमों के अध्याय 4 में, “प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता” उप-शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जायगा, अर्थात्:— “प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता “प्रतिकरात्मक (स्थानीय) भत्ता और पर्वतीय (प्रतिकरात्मक) भत्ता।

4. विनियम 22 का प्रतिस्थापन.— उक्त विनियमों के विनियम 22 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“22. तटीय अनुज्ञेयता—तट पर सेवा करने वाले आफिसर उन सभी नगरों और परिक्षेत्रों में जहां ये भत्ते ऐसे सिविलियन सरकारी सेवकों को अनुज्ञेय हैं जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन में से वेतन दिया जाता है, प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता, प्रतिकरात्मक (स्थानीय) भत्ता और पर्वतीय (प्रतिकरात्मक) भत्ता, उन्हीं दरों और उन्हीं शर्तों के अधीन जो पश्चात् कथित को समय-समय पर लागू हों, प्राप्त करने के हकदार होंगे।”

5. विनियम 23 का संशोधन :— उक्त विनियमों के विनियम 23 में,

- (1) उप-विनियम (1) में, ‘भत्ता’ शब्द के स्थान पर ‘भत्ते’ शब्द रखा जाएगा ;
- (2) उप-विनियम (2) में, “प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “विनियम 22 में निर्दिष्ट भत्ते” शब्द और अंक रखे जाएंगे।)

6. विनियम 24 का संशोधन.— उक्त विनियमों के विनियम 24 में,—

- (1) उपविनियम (1) में, “प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “विनियम 22 में निर्दिष्ट भत्ते” शब्द रखे जाएंगे ;
- (2) उप विनियम (2) में, “प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “भत्तों” शब्द रखा जाएगा।

7. विनियम 25 का संशोधन.— उक्त विनियमों के विनियम 25 में,

- (1) उपविनियम (i) में, (i) “प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता, प्रतिकरात्मक (स्थानीय) भत्ता और पर्वतीय (प्रतिकरात्मक) भत्ता” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में, “दो मास” शब्दों के स्थान पर, “चार मास” शब्द रखे जाएंगे।

(2) उपविनियम (2) और (3) में, जहां कहीं “भत्ता” शब्द आए उसके स्थान पर, “भत्ते” शब्द रखा जाएगा।

8. विनियम 26 और 28 का संशोधन.— उक्त विनियमों के विनियम 26 और 28 में, जहां कहीं “भत्ता” शब्द आए उसके स्थान पर, “भत्ते” शब्द रखा जाएगा।

9. विनियम 27 का लोप.— उक्त विनियमों के विनियम 27 का लोप कर दिया जाएगा।

10. विनियम 29 का संशोधन.— उक्त विनियमों के विनियम 29 में, “प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता” शब्दों और कोष्ठों के स्थान पर, “भत्ते शब्द रखा जाएगा।

11. विनियम 38 का संशोधन.— उक्त विनियमों के विनियम 38 में,—

“विवाहित आफिसर 135 रु० विघ्न भत्ता लेने के हकदार होंगे” शब्द, संक्षेपाक्षर और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, संक्षेपाक्षर और अंक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“विवाहित और अविवाहित आफिसर क्रमशः 150 रु० और 50 रु० विघ्न भत्ता लेने के हकदार होंगे”।

12. विनियम 40 का संशोधन.— उक्त विनियमों के विनियम 40 में, उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

“(3) विघ्न भत्ता उस दशा में पूर्ण दर पर संदत्त किया जाएगा जब कुटुम्बों को अन्य कुटुम्ब आस्थान पर जाना हो या ऐसे आफिसरों की दशा में, जिनके कुटुम्ब, कुटुम्ब-आस्थान के सुविधा क्षेत्र होने के कारण, सुविधा-क्षेत्र में अन्यत्र स्थित अपने गृहों को चले जाते हैं इस बात के अधीन रहते हुये कि उस आफिसर द्वारा उस आस्थान में का कुटुम्ब-आवास खाली कर दिया गया हो और जहां कुटुम्बों को, कुटुम्ब-आस्थान के रूप में घोषित सुविधा-क्षेत्र में किसी आस्थान पर जाना हो वहां विघ्न भत्ता दो-तिहाई की दर पर संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—विघ्न भत्ते की अनुश्रेयता सरकारी खर्चे पर कुटुम्ब के गमनागमन पर निर्भर नहीं होगी।”

13. विनियम 43 का संशोधन.— उक्त विनियमों के विनियम 43 में,—

(1) “400 रु०” अभिव्यक्ति के स्थान पर, “600 रु०” अभिव्यक्ति रखी जाएगी;

(2) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण.—सभी विवाहित आफिसर, जिनका स्थानान्तरण विदेश से भारत में किया गया हो, 600 रु० का विधन भत्ता लेने के हकदार होंगे यदि उनके कुटुम्ब सरकारी खर्चे पर उनके साथ भारत आए हों।”

14. विनियम 45 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 45 में, उप-विनियम (2) में,—

“400 रु०” अभिव्यक्ति के स्थान पर, “600 रु०” अभिव्यक्ति रखी जाएगी।

15. विनियम 46 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 46 में, अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

‘स्पष्टीकरण.—कुटुम्ब के गमनागमन संबंधी शर्तें और आयु से संबंधित निवन्धन अविवाहित आफिसरों को लागू नहीं होंगे।’

16. नये विनियम 48 का अन्तःस्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 48 के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्षक और विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“गोताखोर प्रतिधारण फीस”

48. क—अनुज्ञेयता.—गोताखोर प्रतिधारण फीस, निम्नलिखित दरों पर और विनियम 149 के उपविनियम (1) से (3) में नौसेनिकों के लिये अधिकृत शर्तों के अधीन “जहाजी गोताखोर” और “गहरे गोताखोर” प्रवर्ग के अर्हित आफिसरों को, जैसा कि प्रत्येक के सामने दर्शित किया गया है, अनुज्ञेय होगी:—

आफिसर (साधारण और विशेष कर्तव्य सूची)

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (i) जहाजी गोताखोर | 40 रु० प्रति मास। |
| (ii) गहरे गोताखोर | 75 रु० प्रति मास। |

17. विनियम 49 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 49 में, सारणी के अन्त में, निम्नलिखित मर्दे जोड़ी जाएंगी:—

(ग) अन्त

- | | | |
|-------------------|---|-----|
| (i) वाइस एडमिरल | फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन-चीफ | 300 |
| (ii) रियर एडमिरल | फ्लैग आफिसर कमांडिंग पश्चिमी फ्लीट | 300 |
| (iii) रियर एडमिरल | फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ/फ्लैग आफिसर कमांडिंग नौसेना क्षेत्र | 200 |
| (iv) कमोडोर | कमोडोर कमांडिंग/इन-चार्ज नौसेना क्षेत्र | 100 |

18. विनियम 52 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 52 में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु देश प्रवास भत्ता समुद्र, वायु या भूमि मार्ग द्वारा यात्रा की अवधि के दौरान विदेश जाने वाले या विदेश से लौटने वाले आफिसरों को अनुज्ञप्त नहीं होगा।”

19. विनियम 53 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 53 में के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण.—यह भत्ता भारत के बाहर दैनिक भत्ता या विदेशी भत्ता प्राप्त करने वाले आफिसरों को अनुज्ञेय नहीं होगा।”

20. विनियम 56 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 56 में,—

(1) उप-विनियम (1) में, “75 रु०” अभिव्यक्ति के स्थान पर, “100 रु०” अभिव्यक्ति रखी जाएगी :

(2) उप विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अन्तः स्थापित किया जायगा अर्थात्:—

“ (4) ऐसे मामलों में जहाँ तीरमतिक आफिसरों के शर्तों को, उनकी अंशेष्टि में भाग लेने के लिये निकट संबंधियों के आने तक, शवशाला में रखना आवश्यक हो जाना है वहाँ उपगत शवशाला खर्चों की, तीन दिन की अधिकतम अवधि तक 35 रु० प्रतिदिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहने हुए, प्रतिपूर्ति की जाएगी।”

21. विनियम 58 और 59 का प्रतिस्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 58 और 59 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“58 अनुज्ञेयता (1)—अतिरिक्त धन उन आफिसरों को, जिनके अन्तर्गत रिकार्ड पारटियों से संबंधित आफिसर भी हैं, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित दरों पर और शर्तों के अधीन देय होगा।

(2) अतिरिक्त धन उस समस्त अवधि के लिये भी जिसके दौरान आफिसर, छुट्टी, बीमारी, अस्थायी ड्यूटी और फिर से फिटिंग करने या मरम्मत करने की ऐसी अवधि को छोड़कर जिसमें आफिसरों से नट पर रहना अपेक्षित है, सम्पूर्ण जहाज पर रहा हो अनुज्ञेय होगा।

स्पष्टीकरण.—किसी मास में आठ दिन या अधिक दिनों के लिये अतिरिक्त धन के अनुज्ञान के लिये अर्हित आफिसरों को विहित मासिक दर अनुज्ञान की जाएगी। किन्तु जो कम अवधि के लिए अर्हित हों, वे उस मास के लिये अतिरिक्त धन लेने के हकदार नहीं होंगे।

59. बरें.—इतिरिक्त धन की दरें वे होंगी जो नीचे दी गई हैं:—

रैंक	मासिक दर	
	पूर्ण दर	आधी दर
लेफ्टिनेण्ट और उससे ऊपर	42 रु०	21 रु०
सब-लेफ्टिनेण्ट और उसके नीचे	30 रु०	15 रु० 1/2

22. विनियम 60 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 60 में,—

(1) उप विनियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(ड०) पन्डुलियां—इतिरिक्त धन निम्नलिखित भारतीय नौसेनिक पन्डुलियों के फलक पर सेवा करने वाले आफिसरों को भी पूर्ण बरें पर देय होगा, अर्थात्:—
फलवाड़ी, खंडेरी, बारज और कुरसुरा।”

(2) उपविनियम (2) में, “फ्लोट सुरंग अपमाजक” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

“राजपूत, रणजीत, राणा, गोदावरी, गोमती, गंगा, कुठार, कृपाण, त्रिशूल, तलवार, ब्रह्मपुत्र, व्यास, वेतवा, कृष्णा, तीर, कावेरी, शक्ति, मगर, घड़ियाल, गुलधर, सतलुज, यमुना, इवेस्टीगेटर, कमोरता, कदगत, किलतन, कवरत्ती, और कदाल।”

23. विनियम 61 से 65 का लोप. —उक्त विनियमों के विनियम 61 से 65 लुप्त कर दिए जाएंगे।

24. विनियम 69 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 69 में, उप—विनियम (1) में, “1000 रु०” अभिव्यक्ति के स्थान पर, “1400 रु०” अभिव्यक्ति रखी जाएगी।

25. विनियम 71 का संशोधन. —उक्त विनियमों के विनियम 71 में, “1,000 रु०” अभिव्यक्ति के स्थान पर, “1,200 रु०” अभिव्यक्ति रखी जाएगी।

26. विनियम 87 का प्रतिस्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 87 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“87. बरें—अर्हता वेतन या अनुदान की विभिन्न दरें निम्न प्रकार हैं:—

- | | |
|--|------------------|
| (i) अर्हता वेतन की उच्चतर दर . . . | 100 रु० प्रतिमास |
| (ii) अर्हता वेतन की निम्नतर दर . . . | 70 रु० प्रतिमास |
| (iii) अर्हता अनुदान की उच्चतर दर . . . | 2,400 रु० |
| (iv) अर्हता अनुदान की निम्नतर दर . . . | 1,600 रु०।” |

27. विनियम 88 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 88 में, उन-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) किसी ऐसे अफसर को, जो दो वर्ष के भीतर अर्हता अनुदान को निम्नतर दर लेते हुए, ऐसी अर्हता प्राप्त कर लेता है जो उसे अर्हता वेतन की उच्चतर दर लेने का हकदार बना देती है, अर्हता अनुदान लेने के पश्चात् दो वर्ष की समाप्ति तक अर्हता वेतन की उच्चतर और निम्नतर दर के बीच का अन्तर लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । तत्पश्चात् उसे अर्हता वेतन की उच्चतर दर लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।” ।

28. नये विनियम 92—क का अस्तः स्थापन. —उक्त विनियमों के विनियम 92 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शुद्धक और विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“प्रयत्नकरण भत्ता

92—क. पात्रता (1). भारतीय नौपैतिक पोतों के फनक पर सेवा करने वाले भी विवाहित आफिसरों को, जब पोत बेस पत्तन से दूर हों, तब, 70 रु० प्रति मास प्रयत्नकरण भत्ता प्राप्त होगा । जब पोत बेस पत्तन से दूर हों तब आफिसरों को आकस्मिक छुट्टी का उपयोग करने पर, किन्तु किसी अन्य छुट्टी पर नहीं, यह भत्ता अनुज्ञेय होगा ।

(2) प्रयत्नकरण भत्ता दैनिक भत्ते के अनतिरिक्त अनुज्ञेय नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण 1.—इस भत्ते के प्रयोजनार्थ “विवाहित आफिसर” शब्द आफिसर परिभाषा वही होगी जो विनियम 47 में अधिकृति है ।

स्पष्टीकरण 2.—उक्त भत्ते की गणना, एक मास से कम की अवधियों के लिए आनुपातिक आधार पर की जाएगी, किन्तु वह 12 घंटे से कम की किसी अवधि के लिए बेस पत्तन से पोत की अनुपस्थिति के लिये अनुज्ञेय नहीं होगा । ऐसी अवधि की गणना बेस पत्तन से पोत के जाने के समय से बेस पत्तन पर उसके लौटने या आने तक की जाएगी ।” ।

29. विनियम 94 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 94 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

“आफिसरों का प्रवर्ग	सर्वेक्षण भत्ता		सर्वेक्षण बाउंड्री प्रति मास रूपए में
	प्रति मास रूपए में	मास	रूपए में
1	2	3	
चतुर्थ श्रेणी सहायक सर्वेक्षक	50	850	अनुज्ञेय अवधि के दौरान प्राप्त किया गया सर्वेक्षण भत्ता ।

1	2	3
तृतीय श्रेणी सहायक सर्वेक्षक .	60	950 ऋण अंतर्वर्तित अवधि के दौरान प्राप्त किया गया सर्वेक्षण भत्ता ।
द्वितीय श्रेणी सहायक सर्वेक्षक .	85	1,350 ऋण अंतर्वर्तित अवधि के दौरान प्राप्त किया गया सर्वेक्षण भत्ता ।
प्रथम श्रेणी सहायक सर्वेक्षक .	100	1,800 ऋण अंतर्वर्तित अवधि के दौरान प्राप्त किया गया सर्वेक्षण भत्ता ।
प्रधार		
लेफ्टिनेंट कमांडर	100	1,800 ऋण अंतर्वर्तित अवधि के दौरान प्राप्त किया गया सर्वेक्षण भत्ता ।
कप्तान	कछ नहीं	1,800 ”

30. नये विनियम 100 का प्रतिस्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 100 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“100. दर—आफिसरों को अनुज्ञेय उड़ान बाउंड्री की दरें वे होंगी जो जो नीचे दी गई हैं:—

(i) सब-लेफ्टिनेंट से कमांडर — . . . प्रतिवर्ष रुपए में
4200 ।

(ii) कप्तान और उस से ऊपर 3000 । ” ।

31. नये विनियम 101 का प्रतिस्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 101 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“101. बीमा पालिसी विनियम—क्षेत्र की अपेक्षा—

- (i) विमानन ब्रांच के ऐसे किसी आफिसर से जो 16 दिसम्बर, 1967 या उसके पश्चात् पाइलट या संप्रेक्षक के रूप में अर्हित हो गया हो, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह जीवन बीमा निगम से, बन्दोबस्ती बीमा पालिसी/पालिमियां, या अनुकूलतः संपरिवर्तनीय जीवन बीमा पालिसी / पालिमियां, जो विमानन जोखिम को भी अन्तर्विष्ट करें, बन्दोबस्ती पालिसी में निश्चित संपरिवर्तन सहित, कम से कम 20 वर्ष की अवधि के लिए ले, और चालू रखे, बीमाकृत राशि 25, 000 रु० से कम न हो और प्रथम 20 वर्ष के लिए देय औसत मासिक प्रीमियम 150 रु० से कम न हो । उसकी आयुक्त सेवा की प्रथम 20 वर्ष के लिये उड़ान बाउंड्री के लिये उसकी

पात्रता इस अपेक्षा की पूर्ति के अधीन होगी। आफिसर द्वारा या उसके माता पिता/संरक्षक द्वारा आफिसर या कैडेट के रूप में प्रशिक्षण के दौरान (जिनके अन्तर्गत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कैडेट के रूप में की अधि भी हैं) उसके पक्ष में ली गई जीवन बीमा पालिसी, जो उपरिवर्णित अपेक्षाएं पूरी करती हों, इस प्रयोजन के लिये भी प्रतिग्राह्य होगी। उपरोक्त अपेक्षा की पूर्ति, यदि पालिसी प्रारम्भिक रूप में ली गई हो या यदि वह पहले ही ले ली गई हो तो जब आफिसर उड़ान बाउंडी के लिये पात्र हो जाता है इस प्रयोजन के लिये नौसेना मुख्यालय द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित और प्रमाणित की जाएगी। उसके पश्चात् विहित प्राधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यह सत्यापित और प्रमाणित करेगा कि पालिसी चालू और प्रवृत्तगम रहित रही है। जैसे ही और जब उन पालिसियों में से कोई पालिसी परिपक्व हो जाए, वह आफिसर 150 रु० प्रतिमास और चालू पालिसी के मासिक प्रीमियम के बीच के अन्तर का, यदि कोई हो, जो नियमों के अधीन देय अभिदाय की अनिवार्य न्यूनतम दर से अधिक है, डी० एस० ओ० पी० निधि में अभिदाय करेगा।

- (2) विमानन ब्रांच के ऐसे किसी आफिसर से जिसने दिसम्बर, 1959 को या उसके पश्चात्, किन्तु 16 दिसम्बर, 1967 से पूर्व कमीशन प्राप्त किया हो यह अपेक्षा की जाएगी कि वह जीवन बीमा निगम से ऐसी अतिरिक्त बन्दोबस्ती बीमा पालिसी या अनुकृतपत्र: संपरिवर्तनीय जीवन बीमा पालिसी जो विमानन जोखिम को भी अन्तर्विष्ट करें, बन्दोबस्ती पालिसी में निश्चित संपरिवर्तन सहित, ले और चाल रखे, वह तथा जीवन बीमा निगम से उसके द्वारा पहले ही ले ली गई ऐसी पालिसियों और/या डाक जीवन बीमा, विमानन ब्रांच में कमीशन प्राप्त करने की तारीख से कम से कम 20 वर्ष के अवसान तक उसके लिये 25,000 रु० का हो जाएगा और सभी पालिसियों के लिये देय कुल औसत प्रीमियम या प्रीमियम 150 रु० प्रति मास या अधिक होगा। अतः जैसे ही और जब उन पालिसियों में से कोई पालिसी परिपक्व हो जाए, वह आफिसर 150 रु० प्रतिमास और चालू पालिसी पालिसियों के मासिक प्रीमियम के बीच के अन्तर का, यदि कोई हो, जो नियमों के अधीन देय अभिदाय को अनिवार्य न्यूनतम दर से अधिक है, डी० एस० ओ० पी० निधि में अभिदाय करेगा।
- (3) ऐसा कोई आफिसर जो 1 दिसम्बर, 1959 के पूर्व की किसी तारीख से विमानन ब्रांच में सेवा कर रहा है, डी० एस० ओ० पी० निधि में इन नियमों के अधीन विहित अभिदाय की अनिवार्य न्यूनतम दर के अतिरिक्त उस राशि का अभिदाय करेगा यदि वह बन्दोबस्ती पालिसी में निश्चित संपरिवर्तन सहित बन्दोबस्ती बीमा या संपरिवर्तनीय जीवन बीमा पालिसी/पालिसियों के लिये (भारतीय जीवन बीमा निगम तथा डाक जीवन बीमा निधि में) उसके द्वारा संदत्त बीमा प्रीमियम में जोड़ दिया जाये तो वह 150 रु० प्रतिमास के योग के बराबर हो जायेगा।
- (4) नियमित एयरक्रू आफिसर से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह डी० एस० ओ० पी० निधि में, प्रसामान्य नियमों के अधीन देय अभिदाय की अनिवार्य न्यूनतम दर के अतिरिक्त, 150 रु० प्रतिमास और भारतीय जीवन बीमा निगम और/या डाक जीवन बीमा निधि में, बन्दोबस्ती

पालिसी में निश्चित संपरिवर्तन सहित, बन्दोबस्ती बीमा पालिसी/पालिसियां या संपरिवर्तनीय जीवन बीमा पालिसी/पालिसियां चालू रखने के लिए अपने द्वारा संदत्त प्रीमियम की रकम के बीज के अंतर का अभिदाय करे।”

32. विनियम 105 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 105 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) भत्ता पनडुब्बी वेतन के अतिरिक्त अनुज्ञेय नहीं होगा ।”।

33. नये विनियम 105-क का अन्तःस्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 105 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शर्षक और विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“पनडुब्बी वेतन

105.-क—अनुज्ञेयता और दरें—(1) पनडुब्बी वेतन, पनडुब्बी में सेवा के लिए अर्हित और पार्ट कू या स्पेयर कू के रूप में नियुक्त आफिसरों को भी जो पनडुब्बी सेवा के लिए या ऐसी नियुक्तियां धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित हैं जो उनसे उन के सामान्य कृत्यों के भाग के रूप में पनडुब्बी में समय-समय पर समुद्र में जाने के लिए अपेक्षा करती हैं, निम्नलिखित दरों पर अनुज्ञेय होगा, अर्थात् :—

रैंक	रकम प्रतिमा
कप्तान	225 रु०
कमाण्डर	225 रु०
लेफ्टिनेंट कमाण्डर	225 रु०
लेफ्टिनेंट	225 रु०
सब-लेफ्टिनेंट	200 रु०

(2) पनडुब्बी वेतन सभी प्रयोजनों के लिए वेतन समझा जाएगा ।

(3) पनडुब्बी वेतन पनडुब्बी भत्ते के अतिरिक्त अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(4) पनडुब्बी वेतन तब अनुज्ञेय नहीं रह जाएगा जब कोई आफिसर—

(क) पनडुब्बी में सेवा के लिए तीन मास से अधिक की अवधि के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य रहता है;

(ख) पनडुब्बी सेवा के लिए दक्षता का अपेक्षित स्तर बनाए रखने में असफल रहता है जो नौसेनाध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाए ।

(ग) किसी केन्द्रीय सेवा में की नियुक्ति को स्थानान्तरित कर दिया जाता है ।”

34. नए विनियम 122-क का अन्तःस्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 122 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“122-क. सेवा-निवृत्ति पर्यन्त छुट्टी.—आफिसरों, सेवा-निवृत्ति पर्यन्त छुट्टी के लिए (i) विनियम 122 में दर्शित अवधि या (ii) पूरे बेतन और भत्तों सहित चार मास की छुट्टी के लिए विकल्प करने के पात्र होंगे, जिसके अन्तर्गत उम्र वर्ष के लिए शोध्य वार्षिक छुट्टी भी होगी जिस में वे सेवा-निवृत्ति पर्यन्त छुट्टी पर जाते हैं। यदि वार्षिक छुट्टी या उस के किसी भाग का वर्ष के पूर्व में ही उपयोग कर लिया जाता है तो तदनुसार सेवा-निवृत्ति पर्यन्त छुट्टी कम कर दी जाएगी।”

35. विनियम 125 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 125 में ग्रुप ‘ख’ में “सिक बर्थ पंचिब” शब्दों के स्थान पर, “चिविस्सीय सहायक” शब्द रखे जाएंगे।

36. विनियम 133 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 133 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) यदि किसी नौसैनिक के संबंध में दण्ड न्यायालय द्वारा विचारण किया गया हो और उसे सिद्धवोध ठहराया गया हो तो वह उस अवधि के दौरान जिसमें उसे दण्डादेश के भाग के रूप में सिविल शासन द्वारा निरुद्ध किया गया है प्रत्येक दिन या दिन के किसी भाग के लिए एक दिन का बेतन सम्पूहृत करे। वह साधारण नियम के रूप में, उसके विचारण के लम्बित रहने के दौरान अभिरक्षा में बिताए गए समय के लिए उसी रीति से बेतन भी सम्पूहृत करेगा।”

37. नए विनियम 134-क का अन्तःस्थापन.—उक्त विनियमों के अध्याय 7 के अन्तर्गत, निम्नलिखित उपशीर्षक और विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“बाल शिक्षा भत्ता

(1) 134. क. पश्चात् उन नौसैनिकों को छोड़कर जो विदेश में राजनयिक मिशनों में सेवा कर रहे हैं जिसे नौसैनिक जिन्होंने तीन वर्ष से अन्यून सेवा की हो और जिनका बेतन (जिसके अन्तर्गत बेतन वृद्धि, महंगाई बेतन, अच्छा आचरण बेतन, कार्यकारी भत्ता, उड़ान बाउंटी और अनुश्रेय पेंशन के घटक भी हैं) 459 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है, विनियम 134 ख और 134ग में विहित दरों पर और शर्तों के अधीन बाल शिक्षा भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे; 460 रुपये और 509 रुपये प्रतिमास के बीच बेतन लेने वाले नौसैनिक जो ऐसे उपांतिक समायोजन के लिए हकदार हैं जैसा कि विनियम 134ख के नीचे के उद्घाटन में दर्शित किया गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी विभाग का कार्यालय में की गई सभी सेवा, बाल शिक्षा भत्ता की पात्रता के लिए तीन वर्ष की सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जा सकेगी :

परन्तु पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों की दशा में, सेवानिवृत्ति के पूर्व की गई सेवा उक्त प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी।

- (3) नियमित सेवा के लिए बुलाए गए रिजर्व वाले (मनिक) भत्ते के लिए पात्र होंगे यदि उन्होंने रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून सेवा की हो। यदि कोई नौसैनिक किसी वर्ष के मध्य में रिजर्व में स्थानान्तरित किया जाता है तो वह उस वर्ष का भत्ता लेने के लिए पात्र होगा जिसमें वह रिजर्व में स्थानान्तरित किया जाता है, यदि वह अन्य शर्तें पूरी करता हो।

स्पष्टीकरण.—उपरिनिर्दिष्ट भत्ता ऐसे विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक की शिक्षा के लिए सीमित है जो शिक्षा विभाग या शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता-प्राप्त हो, जिनकी अधिकारिता के भीतर वह विद्यालय स्थित है। प्राथमिक कक्षाओं के अन्तर्गत किडरगार्टन और शिशु कक्षाएं नहीं आती हैं।

(4) भत्ता निम्नलिखित की बाबत भी अनुज्ञेय होगा—

- (क) प्राग-विश्वविद्यालय कक्षाओं या इंटरमीडिएट महाविद्यालय की प्रथम वर्षीय कक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चे : परन्तु यह तब जब कि उन्होंने माध्यमिक, किन्तु ऊपर वर्णित परिभाषित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा नहीं, उत्तीर्ण कर लिया हो;
- (ख) जूनियर तकनीकी विद्यालयों में, जिनके अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और व्यावसायिक विद्यालय भी हैं, अध्ययन करने वाले बच्चे;
- (ग) ऐसे बच्चे जिन्होंने माध्यमिक (किन्तु उच्चतर माध्यमिक नहीं) या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् पालीटेक्नीक डिप्लोमा महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया हो। किन्तु भत्ता ऐसे महाविद्यालय की प्रथम वर्षीय कक्षा के दौरान ही अनुज्ञेय होगा।

134. **ख. भत्ते की दरें.**—(1) विनियम 134क में निर्दिष्ट भत्ता, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि किसी नौसैनिक को किसी एक समय पर अनुज्ञेय कुल भत्ता 50 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होगा, निम्नलिखित दरों पर अनुज्ञेय होगा, अर्थात् :—

- (क) प्राथमिक कक्षाएं (कक्षा I से V) 10 रुपये प्रति बच्चा;
- (ख) माध्यमिक कक्षाएं (V से X) 15 रुपये प्रति बच्चा;
- (ग) उच्चतर माध्यमिक कक्षा (कक्षा XI) 15 रुपये प्रति बच्चा;

(2) ऐसे किसी नौसैनिक की दशा में जो 460 रुपये और 509 रुपये प्रतिमास के बीच वेतन ले रहे हैं, सभी बच्चों की बाबत अधिकतम भत्ता 459 रुपये धन अनुज्ञेय दरों पर बाल शिक्षा भत्ता और उनके वेतन के बीच के अन्तर में अधिक नहीं होगा जसा कि नीचे दिए गए कक्ष उदाहरण में उपदिशत किया गया है —

उदाहरण.—यदि “क” 470 रुपये वेतन लेता है और उसके ऊपर ऐसे दायित्व हैं जो उस को (यदि उसका वेतन 459 रुपये होता है तो) 30 रुपये भत्ते के लिए हकदार बनाते तो उसे 459 रुपये धन 30 रुपये और 470 रुपये के बीच का अन्तर अर्थात् 19 रुपये प्रतिमास दिया जाएगा।

134-ग. शर्तें (1) बाल शिक्षा भत्ते का अनुदान निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन होगा, अर्थात् :—

- (क) बच्चा उस आस्थान से अलग किसी विद्यालय में पढ़ रहा हो और रह रहा हो जिस पर नौसैनिक तैनात है। या रह रहा है।

उदाहरण—‘क’ का दिल्ली में मुख्यालय हो और वह गाजियाबाद में रह रहा हो। भत्ता उस दशा में अनुज्ञेय नहीं होगा जब उसके बच्चे या तो दिल्ली या गाजियाबाद के किसी विद्यालय में पढ़ रहे हों।

(ख) बच्चा पांच वर्ष और 18 वर्ष की आयु-सीमा के बीच हो;

टिप्पण 1.—भत्ता उस मास के ठीक बाद के मास से आरम्भ होगा जिसमें बच्चा पांच वर्ष की आयु प्राप्त करता है वह उस शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर बन्द हो जाएगा जिसमें बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

टिप्पण 2.—यदि कोई बच्चा किसी मास के बीच में विद्यालय में प्रविष्ट कराया जाता है या उससे हटा लिया जाता है तो भत्ता अन्य शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन रहने हुए सम्पूर्ण मास के लिए अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण 3.—किसी नौसैनिक की शैक्षणिक वर्ष के मध्य में मृत्यु, सेवा निवृत्ति, उन्मोचन या निर्मुक्ति पर, भत्ता शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक हो अनुज्ञेय होगा यदि अन्य विहित शर्तें भी पूरी कर दी गई हों। ऐसे उन्मोचित या निर्मुक्त किए गए नौसैनिक की दशा में ऊपर विहित की गई शर्तें पूरी करनी होंगी।

टिप्पण 4.—ऐसा नौसैनिक जो पहले लापता घोषित कर दिया गया हो और तत्पश्चात् मृत घोषित कर दिया गया हो, उस शैक्षणिक वर्ष के लिए भत्ता लेने का पात्र होगा जसमें वह पहले लापता घोषित किया गया हो। ऐसा कोई नौसैनिक जो पहले लापता रिपोर्ट किया गया हो किन्तु जो तत्पश्चात् पुनः कार्य-ग्रहण कर लेता है, युद्ध बंदियों की तरह ही भत्ता लेने का पात्र होगा परन्तु यह तब जब कि वेतन और भत्ते की बकाया इस विषय से संबंधित विद्यमान नियमों के अधीन उसको स्वीकृत कर दी गई हो।

टिप्पण 5.—जहाँ कोई नौसैनिक अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में सेवा से पदभ्युत कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो वहाँ भत्ता अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

टिप्पण 6.—भत्ता अवकाश की अवधि के दौरान भी अनुज्ञेय होगा यद्यपि बच्चे अवकाश के दौरान अपने माता पिता के साथ रह रहे हों परन्तु यह तब जब कि उनके नाम रजिस्टर में दर्ज हों।

टिप्पण 7.—ऐसे नौसैनिक की दशा में जो किसी मास के अन्त में बदली किये गये हों और उनकी किसी कार्य ग्रहण के समय का उपभोग करने के पश्चात् ठीक बाद के मास में नये पोंत या स्थापन में रिपोर्ट करनी हो भत्ता बन्द कर दिया जायेगा या उस मास के ठीक बाद के मासों में आरम्भ से अनुज्ञात किया जायेगा जिसमें नौसैनिकों की बदली की गई हो :

(ग) बच्चे जिनके अन्तर्गत सौतेली सन्तान और धरतक संतान (जहाँ दत्तक ग्रहण व्यक्ति की वैयक्तिक विधि के अधीन मान्य हो) भी हैं व नौसैनिक की धर्मज सन्तान हो और वे नौसैनिक पर पूर्ण रूप से आश्रित हों।

(घ) किसी नौसैनिक की पत्नी जो सरकारी सेवा में हो, सिविलियन सरकारी कर्मचारी को लागू नियमों के अधीन बाल शिक्षा भत्ता न ले रही हो ;

(क) बच्चे नेपाल, भूटान या सिक्किम में स्थित विद्यालयों को छोड़कर किसी दूसरे देश में अध्ययन न कर रहे हों।

टिप्पण 8:—यदि पति और पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हों और अलग-अलग स्थानों पर तैनात हों तो भत्ता अनुशेष नहीं होगा यदि बच्चे उस स्थान पर रह रहे हों और या अध्ययन कर रहे हों जहां माता या पिता में से कोई कार्य कर रहा हो और/या रह रहा हो।

38. विनियम 135 का प्रतिस्थापन.—उक्त विनियमों के अध्याय 7 में, उपशीर्षक “प्रति-करात्मक भत्ता” और विनियम 135 के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्षक XXX और विनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“कार्यकारी भत्ता

135. पत्रता (1) अवैतनिक आयोग धारण करने वाले आफिसरों से भिन्न उपयुक्त मास्टर मुख्य पेटी आफिसर I और II को जब वे कमान मुख्य और नौसैनिक मुख्यालय से भिन्न पोतों और स्थापनों में आफिसरों की रिक्तियों पर, जब कभी वे साधारण और विशेष कर्तव्य सूची दोनों में आफिसरों की कमी के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हुई है किन्तु छुट्टी अस्थाई कर्तव्य या शिक्षणक्रम द्वारा हुई रिक्तियों के कारण नहीं, नियुक्त किया जाए निम्नलिखित दरों पर कार्यकारी भत्ता तब दिया जाएगा, अर्थात् :—

रु० प्रतिमास

(क) मास्टर मुख्य पेटी आफिसर I जब लेफ्टिनेंट कमान्डर की रिक्ति पर कार्य कर रहे हों 100

(ख) मास्टर मुख्य पेटी आफिसर I और II, जब वे लेफ्टिनेंट या उपलेफ्टिनेंट की रिक्ति पर कार्य कर रहे हों 75

(2) किन्तु किसी आफिसर की रिक्ति पर मास्टर मुख्य पेटी आफिसर II की नियुक्ति निम्नलिखित और शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :—

(क) उसने मास्टर मुख्य पेटी आफिसर II की हैसियत में तीन वर्ष सेवा की हो ;

(ख) उस शाखा का मास्टर मुख्य पेटी आफिसर I उस पोत या स्थापन में का न हो ;

(ग) वह उप-लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट की रिक्ति पर ही कार्य करेगा।

(3) ऐसी नियुक्तियां प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से की जाएंगी। आफिसरों के स्थान पर नियुक्त किए गए मास्टर मुख्य पेटी आफिसर I और II के स्थान पर कोई भी परणामिक अभिवर्धन नहीं किए जाएंगे।

(4) रैंक और के साथ-साथ ऐसी नियुक्ति जिसमें स्थानापन्न व्यवस्था की गई हो मास्टर मुख्य पेटी आफिसर I और II को कार्यकारी भत्ते की समुचित दर मंजूर करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। इस प्रयोजन के

लिए, लेफ्टिनेंट कमांडर के मंजूर कांडर की गणना प्रत्येक शाखा में लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और उप-लेफ्टिनेंट के कुल मंजूर कांडर के 25 प्रतिशत या ऐसे अन्य प्रतिशत के रूप में की जाएगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाए ।

प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता

प्रतिकरात्मक (स्थानीय) भत्ता

और पर्वतीय (प्रतिकरात्मक) भत्ता

135क. **तृतीय अनुज्ञेयता**.—बायों को छोड़ कर ऐसे नौ-सैनिकों को, जो उन स्थानों पर तटीय सेवा कर रहे हों जहां प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता, प्रतिकरात्मक (स्थानीय) भत्ता और पर्वतीय (प्रतिकरात्मक) भत्ता ऐसे अराजपत्रित सिविलियन सरकारी सेवकों को अनुज्ञेय हों जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलनों से बेतन दिया जाता है, सिविलियनों को लागू शर्तों के अधीन ऐसे भत्ते दिए जाएंगे, किन्तु पश्चात्पूर्वी समय-समय पर अनुज्ञेय दरों का अस्सी प्रतिशत (जिसके अन्तर्गत न्यूनतम और अधिकतम भी हैं) दिया जाएगा ।”

39. **विनियम 136 का संशोधन**.—उक्त विनियमों के विनियम 136 में,—

(i) उप-विनियम (1 में, “विनियम 135” पद के स्थान पर, “विनियम 135क” पद रखा जाएगा;

(ii) उप-विनियम (2) में, “प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “प्रतिकरात्मक (नगर भत्ता प्रतिकरात्मक (स्थानीय) भत्ता और पर्वतीय (प्रतिकरात्मक) भत्ता” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

40. **विनियम 137 का संशोधन**.—उक्त विनियमों के विनियम 137 में, खण्ड (ग) में, अन्त में आए, “और” शब्द का लोप कर दिया जाएगा और खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) कार्यकारी भत्ता, और ”

41. **विनियम 138 का संशोधन**.— उक्त विनियमों के विनियम 138 में,—

(i) उप- विनियम (3) के अन्त में आए स्पष्टीकरण में, “इस भत्ते” शब्दों के स्थान पर, “इन भत्तों” शब्द रक्के जाएंगे;

(ii) उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(4) यदि कोई टुकड़ी उसके मूल स्थापन या उसके मूल पोत के बेस पत्तन से भिन्न किसी आस्थान पर तैनात की गई हो तो उस टुकड़ी को बदली किए गए व्यक्ति स्थाई कर्तव्य पर समझे जाएंगे और उनको उनकी नियुक्ति की तारीख से उस आस्थान के प्रतिकरात्मक भत्ते दिए जाएंगे जिस पर वह टुकड़ी तैनात की गई है :

परन्तु मूल स्थान या मूल पोत के बेस पत्तन से भिन्न किसी आस्थान पर किसी टुकड़ी में अस्थाई कर्तव्य पर सेवा करने वाले व्यक्तियों को उस आस्थान पर उप-विनियम (3) के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञेय भत्ते दिए जाएंगे ।” ।

42. विनियम 142 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 142 में,—

- (1) उप-विनियम (2) में, “9 रुपए” और “7 रुपए” पदों के स्थान पर, क्रमशः “12 रुपए” और “10 रुपए” पद रखा जाएगा;
- (2) उप-विनियम (3) में “10 रुपए” और “8 रुपए” पदों के स्थान पर, क्रमशः “15 रुपये” और “12 रुपए” पद रख जाएगा।

43. विनियम 145 का प्रतिस्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 145 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“145. अनुज्ञेयता और वरों.—(1) नौ-सैनिकों और शिक्षकों का (बायों को छोड़कर) महंगाई भत्ता, दरों का 30 प्रतिशत और सिविलियन सरकारी सेवकों को लागू शर्तों के अधीन दिया जाएगा जो समर्थ-समय पर सरकारी आदेशों में उनके लिए विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन प्रत्येक नौ- सैनिक को अनुज्ञेय महंगाई भत्ते की रकम लगभग रुपए में पूर्णांकित की जाएगी।”।

44. विनियम 146 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 146 में, खण्ड (iii) में अन्त में आग “और” शब्द का लोप कर दिया जाएगा और खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) कार्यकारी भत्ता; और”

45. विनियम 148 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 148 में,—

- (1) उपविनियम (1) में विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

“महंगाई	जल का दबाव के नीचे रहने के समय के अनुसार दर	
पैन्टम	मीटर	पैस प्रति मिनट
(क) 20 तक	36.58	8
(ख) 20 से 30	36.58 से 54.86	13
(ग) 30 से 40	54.86 से 73.15	18
(घ) 40 से 50	73.15 से 91.44	25
(ङ) 50 से 60	91.44 से 109.73	32
(च) 60 से 75	109.73 से 137.16	45
(छ) 75 से 100	137.16 से 182.88	60 1”।

(2) उप-विनियम (II) का लोप कर दिया जाएगा।

46. नए विनियम 148 का अन्तःस्थापन—उक्त विनियमों के विनियम 148 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशर्पक और विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

“निमज्जन-भत्ता

148 क. अनुशेषता और दरें—(1) निकासी गोताखोरों के प्राधिकृत काडर के नीचे सैनिक अपने अपने प्रवर्ग के समुचित वर्ग में सम्बन्धित निमज्जन-भत्ता लेने के निम्न प्रकार हकदार होंगे, अर्थात्—

	रुपए प्रतिमास
निकासी गोताखोर प्रथम वर्ग	70
निकासी गोताखोर द्वितीय वर्ग	60
निकासी गोताखोर तृतीय वर्ग	50

(2) निकासी गोताखोर, विनियम 148 के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट दरों का बुगना गोता धन लेने के हकदार होंगे ।”

47. विनियम 149 का संशोधन—उक्त विनियमों के विनियम 149 में,—

(i) उप-विनियम (1) में खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्—

“(ii) जहाजी गोताखोर 35 रुपए प्रति मास
(iii) गहरे गोताखोर 60 रुपए प्रति मास ।”

(2) उप-विनियम (4) का लोप कर दिया जाएगा ।

48. विनियम 151 का संशोधन—उक्त विनियमों के विनियम 151 में,

(1) उप-विनियम (i) में, “1320 रुपये” पद के स्थान पर, “2100 रुपए” पद रखा जाएगा ;

(2) उप-विनियम (i) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा—अर्थात् :

“(क) वह संदाय इस शर्त के अधीन होगा कि वायु-कर्मिंदल सामान्य नियमों के अधीन देय अभिदाय को अनिवार्य न्यूनतम दर में अतिरिक्त, 75 रुपए और बन्दोबस्ती बीमा पालिसी/पालिसियों या बन्दोबस्ती (भारतीय जीवन बीमा निगम/डाक जीवन बीमा निधि), को जो विमानन जोखिम को भी अन्तर्विष्ट करे, चालू रखने के लिए उसके द्वारा संदत्त प्रीमियम की मासिक रकम के बीच क अन्तर ए०एफ०पी०पी० निधि में मासिक अभिदाय करे । ए०एफ०पी०पी० निधि में ऐसा अतिरिक्त अभिदाय उस मास के अगले मास के वेतन से आरम्भ होगा जिसमें वह उड़ान बाउण्टी के लिए अर्हित हो ।”

(3) उप-विनियम (2) में, खंड (ग) में, “1320 रुपए” पद के स्थान पर, “2100 रुपए ” पद रखा जाएगा ।

49. विनियम 152 का संशोधन—उक्त विनियमों के विनियम 152 में,—

(1) उप-विनियम (2) में, “55 रुपए” पद के स्थान पर “100 रुपए” पद रखा जाएगा ;

(2) उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(4) ऐसे मामलों में जहाँ नौ-सैनिकों के शवों की उनकी अन्तयेष्टि में भाग लेने के लिए, निकट सम्बन्धियों के आने तक, शव शाला में रखना आवश्यक हो जाता है, वहाँ उपगत शवशाला स्वच्छ की, तीन दिन की अधिकतम अवधि तक 35 रुपए प्रति दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, प्रतिपूर्ति की जाएगी ।” ।

50. विनियम 153 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 153 में, —

(1) “नौसैनिकों को” शब्दों के पश्चात्, “(मास्टर मुख्य पेटी आफिसर I और II को छोड़कर)” शब्द और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(2) विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्—

	रुपए प्रतिमास
“एक बिल्ला के लिए	5
दो बिल्लों के लिए	10
तीन बिल्लों के लिए	15

51. विनियम 154 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 154 में,—

(1) उप-विनियम (1) में, सारणी में,—

(i) मद (फ) के सामने “2.50” अंकों के स्थान कूपर, “8.75” अंक रखे जाएंगे ; और

(ii) मद (ख) के सामने, “2.00” अंकों के स्थान पर, “7.00” अंक रखे जाएंगे ।

(2) उप-विनियम (2) में,—

(i) “2 रुपए” पद के स्थान पर, “7 रुपए” पद रखा जाएगा ।

(ii) “छुट्टी बिना अनुपस्थिति के दौरान ” शब्दों के स्थान पर, “छुट्टी बिना अनुपस्थिति या असेवा निवृत्ति या सेवान्मुक्ति पूर्वन्त छुट्टी के दौरान” शब्द रखे जाएंगे ।

52. विनियम 155 का प्रतिस्थापन—उक्त विनियम के विनियम 155 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्—

“155. अनुज्ञेयता और बरें—(1) अतिरिक्त धन, उन नौ-सैनिकों को जिनके अन्तर्गत वे नौ-सैनिक भी हैं जो रिफार्ड पार्टियों से सम्बन्ध रखते हैं, विनियम 58 के उप-विनियम (2) और विनियम 60 में विहित शर्तों के अधीन देय होगा ;

(2) अतिरिक्त धन की दरें वे होंगी जो नीचे दी गई हैं, अर्थात्—

नौ-सैनिक	मासिक दरें	
	पूर्ण दरें	आधी वरें
(1)	(2)	(3)
मास्टर मुख्य पेटी आफिसर I और II	34 रुपये	17 रुपये
मुख्य पेटी आफिसर	29 रुपए	14.50 रुपए
पेटी आफिसर	24 रुपए	12 रुपए
मुख्य /ताविक (और तालिक II	19 रुपए	9.50 रुपए
बाय	14 रुपए	7 रुपए

स्पष्टीकरण—किसी मामले में 10 दिन या अधिक दिनों के लिए अतिरिक्त धनअनुदान के लिये अर्हित नौ-सैनिक को विहित मासिक दरें अनुशात की जाएंगी किन्तु जो कम अवधि के लिए अर्हित हों, वे उस मास के लिए अतिरिक्त धन क लेने के हकदार नहीं होंगे ।” ।

53. विनियम 157 का लोप—उक्त विनियमों के विनियम 157 का लोप कर दिया जाएगा ।

54. नए विनियम 157 क का अन्तःस्थापन.— उक्त विनियमों के विनियम 157 के के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्षक और विनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“हास्टल सहायकी

157-क शर्तें—ऐसे नौ-सैनिकों को जिन्होंने एक वर्ष से अन्यून सेवा की हो और जिनका वेतन, जिसके अन्तर्गत रैंक या नियुक्ति वेतन और सदाचार वेतन भी है, 349 रुपए प्रतिमास से अधिक न हो, ऐसे केन्द्रीय सिविल सरकारी सेवकों की बाबत जिनको वेतन रक्षा सेवा प्राक्कलनों में से दिया जाता है, सरकारी आदेशों में समय-समय पर अधिसूचित दरों पर और शर्तों के अधीन हास्टल सहायकी दी जाएगी और जो निम्नलिखित शर्तों के पूरे किए जाने के अधीन भी होंगे, अर्थात्—

(1) हास्टल सहायकी नौ-सैनिकों को उनके उन बच्चों की बाबत अनुज्ञेय होगी जो केन्द्रीय विद्यालय स्कीम के अधीन आवासिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हों ।

(2) ऐसे नौ-सैनिकों की दशा में जिनकी पत्नियां केन्द्रीय सरकारी सेवक हैं हास्टल सहायकी उनमें से केवल एक की बाबत अनुज्ञेय होगी किन्तु यदि उनमें अधिक से किसी का वेतन 349 रुपए प्रतिमास से अधिक हो तो वह अनुज्ञेय नहीं होगी ।

- (3) हास्टल सहायकी कर्तव्य करने समय या छुट्टी के समय जिसके अन्तर्गत सेवा निवृत्ति पर्यन्त छुट्टी भी है, अनुज्ञेय होगी किन्तु वह मृत सेवा-निवृत्ति या सेवान्मुक्त नौ-सैनिकों को अनुज्ञात नहीं की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की शैक्षणिक वर्ष के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह सेवानिवृत्त हो जाता है या सेवान्मुक्त कर दिया जाता है तो हास्टल सहायकी उस शैक्षणिक वर्ष के अन्त तक अनुज्ञेय होगी। वह नौ-सैनिक कार्यवाही के रूप में सेवा से हटाए जाने की दशा में अनुज्ञेय नहीं होगी।

टिप्पण—बेतन जिसके प्रति निर्देश से हास्टल सहायकी दी जाएगी, जब कोई व्यक्ति छुट्टी पर हो, वह बेतन होगा जो उसके छुट्टी पर जाने के समय उसे अनुज्ञेय हो।

- (4) बच्चा उस आस्थान से दूर किसी विद्यालय में पढ़ रहा हो जहां पर कोई व्यक्ति तैनात है और/या रह रहा है।
- (5) हास्टल सहायकी शैक्षणिक मत्र के दौरान हास्टल के खाने के खर्चों के लिए हो अनुज्ञेय है और वह आवास, विद्युत् और जल प्रभारों की बाधत अनुज्ञेय नहीं होगी।
- (6) हास्टल सहायकी नौ-सैनिक की ऐसी धर्मज संतान जिसके अन्तर्गत सौतेली-संतान और दत्तक संतान (जहां दत्तक ग्रहण किसी व्यक्ति की वैयक्तिक विधि के अधीन मान्य हो) भी हैं, को ही अनुज्ञेय है जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों।
- (7) हास्टल सहायकी उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए अनुज्ञेय है और वह एक ही कक्षा में दो शैक्षणिक वर्षों से अधिक के लिए संचालित नहीं की जाएगी।
- (8) हास्टल सहायकी किसी एक समय पर तीन ही बच्चों की बाधत अनुज्ञेय है।
- (9) हास्टल सहायकी किसी ऐसे बच्चे की बाधत अनुज्ञेय नहीं है जिसको कोई छात्रवृत्ति मिलती है। यदि बच्चे को प्रस्थापित की गई छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं की गई हो तो यह अनुज्ञात की जा सकेगी।
- (10) हास्टल सहायकी विदेश में मिशन में सेवा करने वाले ऐसे नौ-सैनिकों को अनुज्ञेय नहीं होगी जिनको भारतीय विदेश सेवा नियमों से संबंधित नियमों और विनियमों विषयक पुस्तिका के अधीन शैक्षिक सहायता दी जाती है।
- (11) हास्टल सहायकी ऐसे बच्चों की बाधत अनुज्ञेय नहीं होगी जिनके लिए बाल शिक्षा भत्ता लिया जाता है। ऐसे बच्चों की कुल संख्या जिनके लिए हास्टल सहायकी और बाल शिक्षा भत्ता लिया जाता है कुल मिलाकर चार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (12) ऐसे व्यक्ति जो 349 रुपए से अधिक बेतन ले रहे हों, 349 रुपए लेने वाले किसी व्यक्ति को हास्टल अनुज्ञेय सहायकी की रकम के बराबर हास्टल सहायकी लेने के हकदार होंगे जिसमें से उतनी रकम कम कर दी जाएगी जितना कि उनका बेतन 349 रुपए से अधिक हो।

55. विनियम 158 और 159 का लोप.—उप-शीर्षक “जिजर बियर और बर्फ भत्ता” और उक्त विनियमों के विनियम 158 और 159 का लोप कर दिया जाएगा।

56. विनियम 162 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 162 में,—

- (1) खण्ड (क) के पश्चात्, उपशीर्षक “उच्चतर दर” अन्तःस्थापित किया जाएगा;
- (2) खण्ड (ख) के पश्चात् “उच्चतर दर” उप-शीर्षक का लोप कर दिया जाएगा;
- (3) खण्ड (घ) में (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—
 “(घ) जब वे छुट्टी में रेल या सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हों;
 (ङ) जब वे कर्तव्य के समय रेल या सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हों;

टिप्पण.—रेल गाड़ियों के देरी में चलने और/या उनमें भीड़-भाड़ के कारण हुई अनवक्षित देरी को दूर करने के लिए नौ-सैनिकों के छोटे दलों (अर्थात् ऐसे नौ-सैनिक जो एक स्थान से दूसरे स्थान को बदली के समय बैच में जा रहे हों या नौ-सैनिकों का ऐसा दल जो अनुरक्षक ड्यूटी पर जा रहा हो) को, जिन्हें यात्रा की अवधि के लिए मुफ्त राशन के बदले में राशन भत्ता दिया गया हो, उसके अतिरिक्त राशन धन का रिजर्व निम्नलिखित मापमानों पर अग्रिम दिया जाएगा, अर्थात् :—

- (i) 18 घण्टे से अधिक किन्तु 24 घण्टे में अनधिक एक दिन का अग्रिम राशन यात्रा के लिए जिसके दौरान रेल गाड़ियों धन।
की कोई बदली न हो गई हो।
- (ii) उपरोक्त (i) जैसी किसी यात्रा के लिए जिसमें दो दिन का अग्रिम राशन रेल गाड़ी बदली गई हो। धन।
- (iii) 24 और 48 घण्टे के बीच की किसी यात्रा के तीन दिन का अग्रिम राशन लिए जिसमें एक या अधिक बदली की धन।
गई हो।
- (iv) 48 घण्टे और 72 घण्टे के बीच की किसी चार दिन का अग्रिम राशन यात्रा के लिए जिसमें एक या अधिक बदली धन।
की गई हो।
- (v) 72 घण्टे से अधिक की यात्राओं के लिए जिनमें पांच दिन का अग्रिम राशन एक या अधिक बदली की गई हो। धन।
- (च) (जब वे किसी ऐसे आस्थान पर संचलन नियंत्रण ड्यूटी पर नियोजित हों जहां वे जलपान-गृह में अपना भोजन करने के लिए बाध्य हों);
- (छ) जब से किसी ऐसे अन्य स्थान पर अस्थायी (1) वास्तविक खर्च, जिसमें डाक-ड्यूटी पर निरुद्ध किए गए हों या बंगला, आदि की बाधत कैम्पों में उपस्थित हों जहां राशनों का प्रभार, यदि कोई हों, सम्मिलित है जो व्यक्ति के कमान सरकार द्वारा प्रदाय नहीं किया जा आफिसर द्वारा प्रमाणित सकता। किए गए हों किन्तु अधिक से अधिक उस विशेष दर के अधीन जो समय-समय पर अधिमूर्चित की जाए।

- (2) 10 दिन से अधिक की अवधियों की बाबत दावे समीपस्थ नौ-सेना स्थापन के कमान आफिसर द्वारा प्रति-हस्ता-क्षरित किए जाएंगे।

टिप्पण 1. प्रति व्यक्ति प्रति दिन पूर्ण दर पर राशन भत्ते का अग्रिम ऐसे नौसैनिकों को अनुज्ञेय होगा जो किसी अन्य स्थान पर अस्थायी इयूटी पर प्रत्याशित दिनों के के लिये निरुद्ध किए गए हों जिनके लिये उन्हें किसी अन्य स्थान पर निरुद्ध किया जाना सम्भाव्य हो।

टिप्पण 2. उपरोक्त राशन भत्ता भारतीय नौसेना के प्रोवीनौ सैनिकों को अनुज्ञेय नहीं होगा जब उन्हें उनके पोत या स्थापन से विभिन्न स्थान पर अव्यवस्थाओं से सम्बन्धित पुलिस इयूटी के समय उनके द्वारा सेवा में उपगत किए गए जब खर्च में से संदाय किया गया हो ;

- (ज) जब वे कूरियर इयूटी पर नियोजित हों ;
 (झ) जब वे गुप्त उपस्कर इयूटी पर हों ;
 (ञ) जब रोगी अम्बुलेंस कान्वाय या साधारण रेल गाड़ी द्वारा यात्रा करें परन्तु जिन्हें मुफ्त राशन न दिए गए हों ;
 (ट) जब क्षय रोग के रोगी और भाग्य इलाज के लिए एक सैनिक अस्पताल से दूसरे चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर उनको सेवा के लिये अशक्त ठहरा दिये जाने के पश्चात् यात्रा करें परन्तु जिन्हें मुफ्त राशन न दिए गए हों ;
 (ठ) जब वे इयूटी पर हों—उपरोक्त खण्ड (क) में दी गई निम्नतर वर पर ;

टिप्पण 1. छुट्टी राशन भत्ता छुट्टी पर जाने से पहले ही पूर्णतया ले लिया जा जाएगा।

टिप्पण 2. छुट्टी के वस्तुतः को किसी मंजूर अवधि के लिए शोध्य राशन भत्ता नौसैनिक के इयूटी आस्थान पर लौटने पर उसके द्वारा लिया जाएगा।

- (ड) जब वे मुख्य भूमि और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच नौ-सैनिक पोतों से विभिन्न पोतों पर इयूटी के समय यात्रा कर रहे हों और जब उन्हें भाग्य व्यय और खुराक देने में समर्थ न हो तथा नौबहन कम्पनियों यात्रा टिकटें जिनमें खुराक भी सम्मिलित हो जारी न करती हों।
- नौबहन कम्पनी द्वारा समुद्र यात्रा की अवधि के दौरान खुराक की बाबत उपगत और प्रभावित अवास्तविक खर्च जो नौसैनिक के कमान आफिसर द्वारा प्रमाणित किए गए हों जो इस उपबन्ध के अधीन होंगे कि कोई भी नौसैनिक भत्ता या आहार भत्ता उसके अतिरिक्त अनुज्ञेय नहीं होगा”।

57. विनियम 167 का लोप.—उक्त विनियमों के विनियम 167 का लोप कर दिया जायेगा।

58. नए विनियम 172क और 172ख का अस्त:स्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 172 के पश्चात् “राशन भत्ता” उपशीर्षक के नीचे, निम्नलिखित विनियम अन्त:स्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

“172-क. पेंशन भोगियों या सेवान्मुक्त नौ-सैनिकों को किसी पुनः सर्वेक्षण चिकित्सा बोर्ड के समक्ष हाजिर होने के लिए राशन भत्ता :—

पेंशन भोगी सेवान्मुख नौसैनिक, जब वे अपनी ऐसी निश्चितता के पुनः निर्धारण के लिए किसी पुनः सर्वेक्षण चिकित्सा बोर्ड के समक्ष हाजिर हो रहे हों जिसके बारे में यह समझा जाता है कि वह नौ-सैनिक सेवा से अभिसम्बन्धनीय है या गुह्यतर हुई है, ऐसे अस्थान पर जहां चिकित्सा बोर्ड का आयोजन किया गया हो उनके निरुद्ध किये जाने की अवधि के लिए मुफ्त राशन या वो रुपये प्रति दिन की दर से भत्ते के लिये हकदार होंगे।

172-ख. पेंशन भोगियों या सेवान्मुक्त नौ-सैनिकों को कतिपय वशाओं में अस्पताल आवधि में हाजिर होने के लिए राशन भत्ता:—ऐसे पेंशनभोगियों या सेवान्मुक्त नौ-सैनिक, जिनकी निःशक्तता के बारे में यह समझा गया हो कि वह नौ-सैनिक सेवा से अभिसम्बन्धनीय है या उससे गुह्यतर हुई है, कृत्रिम अंगों की मरम्मत या उनके नवीकरण के लिए अस्पतालों या केन्द्रों में हाजिर होने के समय अस्पतालों या केन्द्रों में उनके निरुद्ध किये जाने की अवधि के लिये मुफ्त राशन या उसके बदले में भत्ते के हकदार होंगे।”।

59. विनियम 174 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 174 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

प्रवर्ग	रुपये प्रति वर्ष
तृतीय वर्ग सर्वेक्षण अभिलेखक	240
द्वितीय वर्ग-सर्वेक्षण अभिलेखक	330
प्रथम वर्ग सर्वेक्षण अभिलेखक	
(पैटी आफिसर और उसके निम्न)	390
प्रथम वर्ग सर्वेक्षण अभिलेखक	
(मुख्य पैटी आफिसर)	450
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर II	510
मास्टर-मुख्य पैटी आफिसर I	570”।

60. विनियम 176 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 176 में उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) भत्ता, पनडुब्बी बेतन के अतिरिक्त अनुसूच्य नहीं होगा।”

61. नए विनियम 176 का अन्तः स्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 176 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्षक और विनियम अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

“पनडुब्बी वेतन

176क. अनुज्ञेयता और वरें—(1) पनडुब्बी वेतन, पनडुब्बी में सेवा करने के लिये अर्हित नौसैनिकों को जो पार्ट वर्मीदल या अतिरिक्त कर्मीदल के रूप में नियुक्त किए गए हों निम्नलिखित दरों पर अनुज्ञेय होगा। यह उन नौ-सैनिकों को भी अनुज्ञेय होगा जो पनडुब्बी सेवा के लिए अन्यथा अर्हित हों और जो ऐसी नियुक्तियां धारण करत हों जिनमें उनसे उनके सामान कर्त्तव्य के भाग के रूप में यह अपेक्षित हो कि वे समय-समय पर पनडुब्बी में समुद्र में जायें :—

नौ-सैनिक	प्रति मास रकम की दर
	र०
मास्टर मुख्य पैट्री आफिसर I और II	150
चीफ पैट्री आफिसर	125
पैट्री आफिसर	100
मुख्य नाविक	90
नाविक I	75
नाविक II	65

(2) पनडुब्बी वेतन सभी प्रयोजनों के लिये वेतन माना जाएगा।

(3) पनडुब्बी वेतन, पनडुब्बी भत्ते के अतिरिक्त अनुज्ञेय नहीं होगा।

(4) पनडुब्बी वेतन तब अनुज्ञेय नहीं होगा जब कोई नौ-सैनिक—

(क) पनडुब्बियों में सेवा के लिये तीन मास से अधिक की अवधि तक चिकित्साकीय रूप से अयोग्य रहेगा ;

(ख) पनडुब्बी सेवा की बाबत नौसेनाध्यक्ष द्वारा यथा अवधारित दक्षता का अपेक्षित स्तर बनाये रख ने में असफल रहेगा ;

(ग) साधारण सेवा नियुक्ति में स्थान्तरित कर दिये जायें ।”

62. नए विनियम 177 क का अन्तःस्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 177 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्षक और विनियम अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

निर्वाह-भत्ता

177-क.—पेंशन भोगियों सेवान्मुक्त नौ-सैनिकों और मृत नौ-सैनिकों के सम्बन्धियों को निर्वाह भत्ता—निर्वाह भत्ता नौसैनिकों (सेवारत/सेवान्मुक्त पेंशन भोगियों) या

मृत नौसैनिकों के सम्बन्धियों को निम्नलिखित दरों और विनिर्दिष्ट अवसरों पर अनुदत्त किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) पेंशन भोगी या सेवोन्मुक्त नौसैनिक जब वे अपनी ऐसी निश्चितता के पुनर्निर्धारण के लिये किसी प.न.सर्वेक्षण या चिकित्सा बोर्ड के समक्ष हाजिर हो रहे हों जिसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह नौसैनिक सेवा से अभिसम्बन्धनीय है या उससे गुस्तर हुई है :—

(i) ऐसे आस्थानों पर जहाँ चिकित्सा बोर्ड का आयोजन किया गया हो उनके विरुद्ध किए जाने की अवधि के लिए ।

विनियम 172-क के अधीन मुफ्त राशन या उनके बदले में भत्ता ।

(ii) उनके गृह और ऐसे आस्थानों जहाँ चिकित्सा बोर्ड का आयोजन किया गया हो और ऐसे अस्थानों जहाँ चिकित्सा बोर्ड का आयोजन किया गया हो और उनके गृह के बीच अभिवहन की अवधि के लिए ।

दो रुपए प्रति दिन ।

(ख) ऐसे पेंशन भोगी या सेवोन्मुक्त नौसैनिक जिनको निश्चितता के बारे में यह समझा जाता है कि वह नौसैनिक सेवा से अभिसंबन्धनीय है या उससे गुस्तर हुई है, कृत्रिम अंगों की मरम्मत या नवीकरण के लिए अस्पतालों या केन्द्रों में हाजिर होने के लिए :—

(i) अस्पतालों या केन्द्रों में उनके निरुद्ध किए जाने की अवधि के लिए

विनियम 172-ख के अधीन मुफ्त राशन या उनके बदले में भत्ता ।

(ii) उनके गृह और अस्पतालों या केन्द्रों से और को अभिवहन की अवधि के लिए निर्वाह भत्ता

दो रुपए प्रति दिन ।

(ग) (i) तमगों और अलंकरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए सिविल पदाधिकारियों द्वारा आयोजित किए गए मानभिक्षेक समारोहों में हाजिर होने के लिए निर्भोचित नौसैनिकों को निर्वाह भत्ता

अभिवहन और ठहरने की अवधि के लिए दो रुपए प्रति दिन ।

(ii) तमगों और अलंकरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए सिविल पदाधिकारियों द्वारा आयोजित किए गए मानभिक्षेक समारोहों में हाजिर होने वाले मृत सैनिक के एक संबंधी को निर्वाह भत्ता

टिप्पण.—खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) और (ii) की बावत भत्ते का अनुदान अधिक से अधिक पांच दिन तक निर्बन्धित होगा । यदि व्यक्ति उस आस्थान पर रहते हैं जहाँ ऐसा प्रस्तुतीकरण किया गया हो तो भत्ता अनुश्रुय नहीं होगा ।”

63. विनियम 178 का संशोधन. —उक्त विनियमों के विनियम 178 में,—

(1) उप-विनियम (1) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) युनिट प्रमाणपत्र भत्ता —

(i) निम्नतर दर—25 रुपये प्रति मास ।

(ii) उच्चतर दर—50 रुपये प्रति मास ।

(ख) चार्ज प्रमाणपत्र भत्ता —

(i) निम्नतर दर 50 रुपये प्रति मास ।

(ii) उच्चतर दर 75 रुपये प्रति मास ।

(iii) विशेष दर 90 रुपये प्रति मास ”।

(2) उप-विनियम (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) विशेष भत्ता 15 वर्ष से आगे पुनः नियुक्ति की अवधियों के लिए अनुज्ञेय होगा परन्तु यह तब जब कि उच्चतर दर दो वर्ष की अवधि तक ली गई हो ।” ।

64. नए विनियम 178 का अन्तः स्थापन. —उक्त विनियमों के विनियम 178 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और विनियम अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“महाने के साबुन के बरतने में रोकड़ भत्ता

178क ऐसे नौ-सैनिकों (जिनके अन्तर्गत बाँय और शिशु भी हैं) को, जो स्नान के प्रयोजनों के लिए महाने का साबुन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है किन्तु उन्हें वह वस्तु के रूप में नहीं दिया जाता है, उसके बरतने में 87 पैसे प्रति मास की दर से रोकड़ भत्ता दिया जाएगा ।” ।

65. विनियम 187 का प्रतिस्थापन. —उक्त विनियमों के विनियम 187 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक और विनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“आफिसरों के लिए आर्थिक-प्रशिक्षण-फीस”

187. प्रतिधारण फीस :—निम्नलिखित प्रवर्ग के आफिसरों को निम्नलिखित दरों पर प्रतिधारण फीस अनुशात की जाएगी, अर्थात् :—

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) अल्पकालिक अनुशात-आफिसर :—प्रत्येक ऐसे वर्ष के लिए जिसमें वे अपनी-अपनी-अवधि-संबिधा की समाप्ति पर आपात सूची में रखे गए हों | } दो सौ २० प्रति वर्ष; |
| (2) भारतीय-नौ-सैनिक रिजर्व-भारतीय नौसैनिक बालि-डियर रिजर्व आफिसर :—
रिजर्व बालि के प्रत्येक वर्ष के लिए | |
| | } चार सौ रुपये प्रति वर्ष । |

पलीट रिजर्व सैनिकों के लिए प्रतिधारण फीस

187-क. प्रविधायन कोष—पहली प्रवर्गों के पलीट रिजर्व सैनिक ऐसी जो समय-समय पर निकाले गए सरकारी आदेशों में यथाअधिकधित शर्तों के अधीन 20 रुपये प्रति मास प्रतिधारण फीस के हकदार होंगे।”।

66. नए विनियमों 191 क का अन्तःस्थापन—उक्त विनियमों के विनियम 191 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“191-क. मौद्रिक इनाम.—(1) नौसेना के गोरखा आयुक्त आफिसरों और नेपाली अधिवास के नौसैनिकों को, जिन्हें शौर्य अलंकरण दिए गए हों, ऐसे एक मुश्त विशेष मौद्रिक इनाम दिए जाएंगे जो नीचे विनिर्दिष्ट किए गए हैं, अर्थात् :—

(क) परमवीर चक्र	10,000 रु०
(ख) महावीर चक्र	7,500 रु०
(ग) वीर चक्र	3,000 रु०

(2) समगा के कुण्डे के नीचे लगाई जाने वाली चांदी की पट्टी वाला इनाम उसके प्राप्ति कर्ता करने वाल को और इनाम का हकदार नहीं बनाएगा।

(3) मृत्युपरान्त इनाम पाने वाले और ऐसे इनाम पाने वाला की दशा में जिनकी इनाम प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो गई हो, उनके वारिसों को निम्नलिखित क्रम में एक मुश्त मौद्रिक इनाम संदत्त किया जाएगा, अर्थात् :—

- (i) मृतक की विधवा;
- (ii) वंशज की पुरुष परंपरा में मृतक का पुरुष पारंपरिक वंशज;
- (iii) मृतक की अविवाहित पुत्रियां;
- (iv) मृतक के माता-पिता।”।

67. विनियम 194 से 197 का संशोधन—उक्त विनियमों के विनियम 194, 195, 196 और 197 में, जहाँ कहीं “माटक” शब्द आया हो उसके स्थान पर, “अनुज्ञप्ति फीस” शब्द रखे जाएंगे।

68. विनियम 201 का संशोधन—उक्त विनियमों के विनियम 201 में, सारणी में, पहले स्तम्भ में “मुख्य पैट्री आफिसर” शब्दों और दूसरे और तीसरे स्तम्भ में उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पूर्व, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

	सामान्य	विशेष
“मास्टर मुख्य पैट्री आफिसर 1 और।”	48.00	61.00।”

69. विनियम 204 का संशोधन—उक्त विनियमों के विनियम 204 में, जहाँ कहीं “मुख्य पैट्री आफिसरों” शब्द आए हों उनके पहले, “मास्टर मुख्य पैट्री आफिसरों और” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

70. विनियम 208 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 208 में, खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में, “मुख्य पैट्री आफिसर” शब्दों के पहले, “मास्टर मुख्य पैट्री आफिसर और ” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

71. विनियम 225 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 225 में खण्ड (क) में, अन्त में निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“यदि किसी मास का प्रथम दिन (भले ही वह रविवार हो) सार्वजनिक अवकाश दिन हो तो नौसैनिकों के वेतन और भत्तों का संवितरण, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपने-अपने स्वविवेकानुसार अवकाश दिन के पूर्व के अन्तिम कार्य दिवस पर प्राधिकृत किया जा सकेगा । यदि किसी मास के प्रथम दो दिन के दौरान पौन कार्यालयों और खजाने बैंक के लिए एक जैसा कार्य दिवस पर न हो तो प्रशासनिक प्राधिकारी पूर्व मास के अन्तिम कार्य के दिन को वेतन और भत्तों का संवितरण प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु यद्यपि अप्रैल का प्रथम दिन सार्वजनिक छुट्टी का दिन हो तो भी वेतन और भत्तों का पूर्वोक्त संवितरण मार्च में प्राधिकृत नहीं किया जाएगा ।” ।

72. विनियम 232 का संशोधन.— उक्त विनियमों के विनियम 232 में, तृतीय परन्तु में, “परन्तु यह और भी कि 14 वर्ष की अवधि तक “शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और” “सम्पदा अनुशासनों के मूल्य [जिसमें खण्ड (क) और (ख) भी सम्मिलित हैं] शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और भी कि 1 जनवरी, 1966 से प्रारम्भ होने वाली 10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक, अधिक दे दिए गए वेतन और भत्तों उधारों या अन्य लोक-वृणों के अधि-निर्गमन की कोई भी वसूली, निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय जिन में ऐसी वसूली सम्पदाओं या सम्पदा के हिताधिकारी से की जाएगी, मृत आफिसर को सम्पदाओं के अधिणोप में से की जाएगी :—

- (i) यदि मृत आफिसर ने अपने पीछे एक विधवा और एक या अधिक संतान छोड़ी हों या वह कोई ऐसा विधुर था जिसकी बी या अधिक संतान हो और जिसके पास पच्चीस हजार रुपये से अधिक मूल्य की कुल आस्तियां हों; या
- (ii) यदि मृत आफिसर ने अपने पीछे संतान रहित एक विधवा छोड़ी हो या वह कोई ऐसा विधुर था जिसके केवल एक संतान हो और जिसके पास बीस हजार रुपये से अधिक मूल्य की कुल आस्तियां हों; या
- (iii) यदि मृत आफिसर आश्रितों सहित अविवाहित था जिसके पास पन्द्रह हजार रुपये से अधिक मूल्य की कुल आस्तियां हों; या
- (iv) यदि मृत आफिसर अविवाहित था और उसके पीछे कोई भी आश्रित न रहा हो चाहे सम्पदा का मूल्य कुछ भी हो; परन्तु के अधीन रहते हुए की वसूली के शुद्ध मूल्य और उपरोक्त खण्ड (i), (ii) और (iii) में बताई गई अधिकतम सीमा के बीच के अन्तर की सीमा तक ही की जाएगी ।” ।

73. विनियम 233 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 233 में, उप-विनियम (1) में, “दो रुपए” और “चार रुपए” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “पांच रुपए” और “दस रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

74. विनियम 236 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 236 में,—

(1) उप-विनियम (1) में, विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण 1.—किमी सवारी के ऋय के लिए उधार वित्त-मंत्रालय (रक्षा) की सहमति के बिना तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक इसी प्रयोजन के लिए पहले अनु-दत्त किए गए उधार की बाबत बकाया अतिशेष और साथ ही उस पर व्याज पूर्णतया प्रति संदत्त नहीं कर दिया जाता ।

स्पष्टीकरण 2.—ऐसे आफिसरों को जिनका अस्थाई कर्तव्य पर, शिक्षण क्रम के लिए, छुट्टी प्रतिनिधित्व या प्रशिक्षण आदि के लिए विदेश जाना या भेजा जाना संभाव्य है, ही किमी भी परिस्थिति में मोटरकारों के ऋय के लिए उधार मंजूर नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 3.—पंक्तिगत तैयारी में सेवा करने वाले आफिसर मोटरकारों के ऋय के लिए उधार लेने के हकदार नहीं होंगे ।”

(2) उप-विनियम (4) में, अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

स्पष्टीकरण I.—“वास्तविक कीमत” से, आफिसर द्वारा कार की लागत के रूप में संदत्त कीमत और ऐसी मशीनों की कीमत अभिप्रेत है जो कार के साथ आवश्यक रूप से खरीदी जाएंगी, (या दूसरे शब्दों में जिनके ऋय करने के विषय में क्रेता को कोई छूट न हो, जैसे फालतू पहिया टायर और ट्यूब) किन्तु जहाँ कतिपय ऐसे उप-साधन (जैसे कार में रेडियो, प्लास्टिक कवर) ऋय किए गए हों जो आवश्यक नहीं हैं और जिन्हें ग्राहक स्पष्टता से ऋय करना है, वहाँ “वास्तविक कीमत” में उनकी लागत सम्मिलित नहीं होगी । बीमा और रजिस्ट्रीकरण प्रभार भी “वास्तविक कीमत” में सम्मिलित नहीं होंगे चूँकि वे मोटरगाड़ी को चलाने के लिए उपगत किए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण II.—“वास्तविक कीमत” में, प्रथम ऋय की दशा में, निम्नलिखित मर्चे भी सम्मिलित होंगे :—

(क) ऋय के समय सम्पृक्त आफिसर के कर्तव्य स्थान तक सवारी का परिवहन व्यय, बाहे परिवहन का प्रबन्ध धितरकों द्वारा किया गया हो या स्वयं आफिसर द्वारा ;

(ख) वस्तुतः संदत्त चुंगी ।” ।

75. विनियम 237 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 237 में,—

(1) उप-विनियम (1) में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

“जिसको अनुज्ञेय है	मंजूरी प्राधिकारी	अनुज्ञेय रकम
(1)	(2)	(3)
(क) (i) नौसेनाध्यक्ष (ii) विदेशस्थ भारतीय मिशन में सेवा करने वाले आफिसर	भारत सरकार	(i) 16,000 रु० या 16 मास का वेतन या कार की प्रत्या- शित कीमत, इन में से जो भी न्यूनतम हों;
(ख) फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी-सेना कमान फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौ-सेना/कमान । फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण नौसेना क्षेत्र सभी नौसैनिक आफिसर (नौसेनाध्यक्ष से भिन्न)।	नौसेनाध्यक्ष	(ii) यूनाइटेड किंगडम आदि देशों से और उन देशों से जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ-साथ अपनी करेंसी का अवमूल्यन कर दिया हो, मोटरकारों के क्रय करने वाले आफिसरों के लिए अधिकतम सीमा तेरह हजार पांच सौ रुपये (13,500 रु०); (iii) उन देशों से जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ-साथ अपनी करेंसी का अवमूल्यन न किया हो, कारों के क्रय करने की दशा में अधिकतम सीमा पन्द्रह हजार सात सौ पचास रुपये (15,750 रु०)
(ग) तट पर सेवा करने वाले सभी नौसैनिक आफिसर जो फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ पश्चिमी नौसेना कमान के अधीन हों ।	फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान ।	
(घ) तट पर सेवा करने वाले सभी नौसैनिक आफिसर जो फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान के अधीन हों ।	फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान ।	

(1)	(2)	(3)
(ङ) तट पर सेवा करने वाले सभी नौसैनिक आफिसर जो फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना क्षेत्र के अधीन हों	फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना क्षेत्र ।	
(च) इंस्ट्रक्शनल स्टाफ एण्ड स्टूडेंट आफिसर, रक्षा सेवा, स्टाफ कालेज, बेलिंग्टन ।	कमांडेंट, रक्षा सेवा, स्टाफ कालेज, बेलिंग्टन।	
(छ) स्टाफ एण्ड स्टूडेंट आफिसर, जिन्हें बेतन रक्षा सेवा प्राक्कलनों, राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली से दिया जाता है ।	कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली ।	
(ज) सभी नौसैनिक अधिकारी जो नौसेना परियोजना, विशाखापत्तनम में सेवा कर रहे हों ।	सहानिदेशक, नौसेना परियोजना, विशाखापत्तनम।” ।	

(2) उप-विनियम (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) उपविनियम (1) की सारणी की मद (क) (ii) में निर्दिष्ट आफिसरों की उधार की मंजूरी इस शर्त के अधीन की जाएगी कि किसी आफिसर द्वारा उधार के लिए आवेदन विदेशस्थ आस्थान पर उसके पहुंचने के 12 मास के भीतर कर दिया गया हो ।” ।

76. विनियम 239 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 239 में, उप-विनियम (4), (5) और (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“मंजूरी प्राधिकारी करार और बंधकपत्र (जिनके नमूने परिशिष्ट 11ख, 11ग और 11ज में दिए गए हैं) के खाली प्रारूप आफिसर को भेजेगा ।

(5) आफिसर पोत या स्थापन के कमान आफिसर या अथवा अन्य समरूप प्राधिकारी की उपस्थिति में करार के प्ररूप को भरेगा और वह उसे और साथ ही ऐसे प्रमाणपत्र को जो परिशिष्ट 11 में दर्शाया गया है और उधार लेने से संबंध अपने दावे को उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने ऐसा उधार मंजूर किया हो । करार का प्ररूप और दावा मंजूरी प्राधिकारी द्वारा रखा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुम्बई को

केवल तब ही भेजा जाएगा जब उसे आफिसर से ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाएगा जो परिशिष्ट 11ड में दर्शाया गया है ।

(6) आफिसर बंधकपत्र (परिशिष्ट 11ग देखें) उधार लेने की तारीख से एक मास के भीतर, पोत या स्थापन के कमान-आफिसर या अन्य समरूप प्राधिकारी और दूसरे आफिसर की उपस्थिति में, भरेगा, जिसमें गाड़ी भारत के राष्ट्रपति को उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में आडमान रखी गई हो और वह नकदी रसीद के साथ-साथ उसे तथा सवारी के क्रय से सम्बद्ध बिल को ऐसी छान-बीन के लिए रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुम्बई को भेजेगा कि उधार का उपयोग सवारी के क्रय के लिए विहित अधि के भीतर किया गया है और विनियम 239 (4) में यथा परिभाषित "वास्तविक कीमत" उधार की रकम से कम नहीं है । नकदी रसीद और बिल, पोत या स्थापन के कमान आफिसर की मार्फत उधार लेने वाले को लौटा दिए जाएंगे ।

(7) नौसेना मुख्यालयों और अन्तर-सेवा संगठनों में सेवा करने वाले आफिसरों के सम्बन्ध में कमान आफिसर, भारतीय नौसैनिक पोत-इण्डिया, ऐसे सभी हेस्तावेज रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) मुम्बई को भेजेगा । ” ।

77. **विनियम 240 का संशोधन.**—उक्त विनियमों के विनियम 240 के उ विनियम (2) में “और एक मास के समय की परिसीमा का सभी दशाओं में कड़ाई के साथ अनुसरण किया जाएगी शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायेंगे अर्थात् :—

“और गाड़ी उसके क्रय की तारीख से पूरी तरह ब्रीभाकृत रखी जानी चाहिये जैसा कि पश्चातवर्ती विनियमों में विहित किया गया है । विहित एक मास की समय की परिसीमा का सभी दशाओं में कड़ाई के साथ अनुसरण किया जाना चाहिये । यह पुरानी गाड़ियों की दशा में भी लागू होगा ।” ।

79. **विनियम 241 का संशोधन.**—उक्त विनियमों के विनियम 241 में—(1) प-विनियम (3) में परन्तुक के खण्ड (क) में “50 रु०” पद के स्थान पर “250 रु०” पद रखी जाएगी ; (2) उपविनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रख जायेंगे अर्थात् :—

“(4) बीमा पालिसियों में परिशिष्ट 11ड में विनिर्दिष्ट प्ररूपों पर पृष्ठांकित किया जाएगा । सवारी के क्रय के पश्चात् रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुम्बई, उधार लेने वाले आफिसर से परिशिष्ट 11ड में विहित प्ररूप में एक पत्र जो उस बीमा कम्पनी को सम्बोधित किया गया हो जिसके साथ सवारी बीमाकृत है, प्राप्त करेगा जिसमें यह अधिसूचित किया गया हो कि सरकार ली गई बीमा पालिसियों में हितवद्ध है । वह स्वयं उस पत्र को बीमा कम्पनी को अशेषित करेगा और उसको अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करेगा । वार्षिक आधार पर किए जाने वाले बीमा की दशा में, यह प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष जब तक दोहराई जाएगी जब तक कि उधार सरकार को पूरी तरह प्रति-संदत्त न कर दिये जायें । ऐसे मामलों में, जहाँ बीमा कम्पनी प्रत्येक वर्ष नई पालिसी जारी नहीं करती हो और मूल पालिसी, जिसमें परिशिष्ट 11ड में के खण्ड पहले से मौजूब हों, नवीकृत कराई गई हो, वहाँ रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुम्बई यह सुनिश्चित करेगा कि मूल पालिसी कम्पनी द्वारा नवीकृत की गई है और परिशिष्ट

11४ में के मुसंगत खण्ड मूल पानिमी में पहले से ही मौजूद है और गाड़ी की बीमा उधार की बकाया रकम और उस पर ब्याज की रकम से अनूतन रकम के लिए कराया गया है ।

- (5) बंधक-पत्र के निष्पादन की बाबत उपबन्धों का अनुपालन न करते और इस विनियम में यथावर्णित गाड़ी का बीमा न कराने की दशा में उधार लेने वाला आफिम उधार दी गई सम्पूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज तुरन्त वापस करेगा जब तक कि उसके प्रतिकूल सही और पर्याप्त कारण दर्शित न किए गए हों और सक्षम प्राधिकारी लिखित विनिर्दिष्ट आदेश जारी करके ऊपर विहित शर्तों में से किसी को पूरा किए जाने को मुत्तवी नहीं कर देता इस प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी वह होगा जो इस उधार की मंजूरी के लिये सक्षम है ।”

79. विनियम 242 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 242 में,—

- (1) उप-नियम (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम रखे जायेंगे, अर्थात् :—

“(1) कोई आफिसर जब तक कि वह उधार की रकम और साथ ही ऐसी रकम पर ब्याज पूर्णतः प्रति-संदत्त नहीं कर देता, किसी मोटरकार का, मंजूरी प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञेय के बिना विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा ।”

- (2) यदि कोई आफिसर दूसरे किसी ऐसे आफिसर को मोटरकार का अन्तरण करने की अनुज्ञा मांगता है, जिसको अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मोटरकार का प्रयोग करना चाहिये तो मंजूरीप्राधिकारी पश्चात्पूर्ति को कार से संलग्न दायित्व के अन्तरण की अनुज्ञा दे सकेगा, परन्तु यह तब जब कि अन्तरिती यह घोषणा अभिलिखित करे कि उससे इसबात की जानकारी है कि उसको अन्तरित की गई मोटर कार बंधक-पत्र के अधीन है और वह उसके निबंधनों और उपबन्धों से आबद्ध है । गाड़ी के विक्रय के लिये आवेदन मंजूरी प्राधिकारी को उचित माध्यम से अग्रेषित किया जाएगा ।”

- (2) उप-विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) ऐसे आफिसर को जिसे नई कार के क्रय के लिए अपनी पुरानी कार के विक्रय की अनुज्ञा दी गई हो नया उधार मंजूर नहीं किया जाएगा । नया उधार तब ही मंजूर किया जाएगा जब पहली कार के उधार का बकाया अनिशेष और साथ ही उस पर ब्याज पूर्णतः प्रतिसंदत्त कर दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण 1.—कोई ऐसा आफिसर, जिससे सरकारी उधार में से क्रय की गई अपनी कार का विक्रय करने की मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा दी गई हो, विक्रय करने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र मंजूरी प्राधिकारी और रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुम्बई, को विक्रय की तारीख की सूचना देगा ।

स्पष्टीकरण 2.—ऐसी मोटरगाड़ी के लिए बंधक-पत्र का नमूना परिशिष्ट 11अ में दिया गया है जो पुरानी गाड़ी के विक्रय आगमों से, पश्चात्पूर्ति गाड़ी के क्रय के लिये सरकार द्वारा पहले मंजूर किए गए उधार की रकम और उस पर ब्याज का, विनियम 242 के उपविनियम (2) की अपेक्षानुसार प्रतिसंदाय किए जाने से पूर्व पश्चात्पूर्ति गाड़ी के विक्रय

आगमों से ऋण की गई हो। नया बन्धक-पत्र उस समय देय रकम के लिये होगा, न कि मूल रूप से उधार दी गई रकम के लिये।”

80. विनियम 243 का शोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 243 में,—

(1) उप विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) मोटरकार से सम्बद्ध उधार की वसूली निम्न प्रकार की जाएगी :—

(क) उन आफिसरों से जो स्थायी आयोग धारण किए हुए हैं.—उधार दी गई रकम का 1/80 भाग, परन्तु ऐसे आफिसर से, जो, यथास्थिति पांच या छः वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला है उधार की वसूली उसके द्वारा उधार लेने के पश्चात् पहली बार वेतन दिये जाने से उतनी किश्तों में की जाएगी जितनी में उधार और उस व्ययज की वसूली उसकी सेवा-निवृत्ति के पूर्व अन्तिम वेतन के दिये जाने के समय तक पूरी हो जाए।

(ख) ऐसे आफिसरों से जो अस्थायी आयोग धारण किए हुए हैं.—तीन वर्ष के भीतर या उनकी नियुक्ति की समाप्ति के पूर्व, इनमें से जो भी पहले हो।”।

(2) उप-विनियम (4) में, अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“इस तथ्य पर भी विचार किया जाएगा कि क्या अन्य रीति से रकम की वसूली कराना सम्भव या उपयुक्त है।” ;

(3) उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

“(5क) किसी ऐसे आफिसर की दशा में, जो उसके त्वांदाय के लिए विहित की गई अधिकतम अवधि के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाला है, यदि उसकी प्रोन्नति या अधिष्ठायी रैंक की मंजूरी या दूसरी अवधि की मंजूरी, आदि के परिणाम-स्वरूप सेवा-निवृत्ति की तारीख, उधार की मंजूरी के पश्चात् बदल दी गई हो तो मंजूरी प्राधिकारी, विनियम, 243 के उप-विनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किश्तों की संख्या में वृद्धि कर सकेगा। उस दशा में वह आफिसर एक ऐसा अनुपूरक बंधक निष्पादित करेगा जो परिशिष्ट 11ट में विहित किया गया है।

(5ख) ऐसे आफिसर को, जो किसी मोटरकार के ऋण के लिये भारत में उसके द्वारा लिए गए किसी उधार के पूरी तरह प्रति-संचित कर दिए जाने के पूर्व भारत से बाहर 12 मास से अधिक की अवधि के लिये प्रति-नियुक्ति पर भेज दिया जाता है या विदेशस्थ पद पर अन्तरित कर दिया जाता है, उसके विकल्प पर शेष किश्तें भारत में रुपये में प्रति-संदत्त करने के लिये मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा दी जा सकेगी। ऐसे आफिसर को उस रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) मूम्बई के पक्ष में प्रत्येक मास के 15वें दिन तक ऐसी देय रकम बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने का इन्तजाम करना चाहिए जिसकी बही में प्रश्नगत उधार के लेखे रखे गये हों। इस प्रभाव का एक लिखित वचनबध्द आफिसर से और उस कार्यालय से जिससे वह विदेश में संलग्न है अभिप्राप्त किया जाएगा।

यदि ड्राफ्ट रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुम्बई को सामान्य पूर्व प्राप्त न हो तो उससे सम्पुक्त प्रशासनिक आफिसर को और विदेशस्थ उस कार्यालय को जहाँ आफिसर कार्य कर रहा है आगे को आवश्यक कार्यवाही के लिए मामले की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिये। सम्पुक्त आफिसर द्वारा नियत तारीख तक बैंक ड्राफ्ट का भेजा जाना व्यक्तिगत माना जाएगा और उसे साधारण वित्तीय नियम, 1963 के नियम 161 के निबंधनों पर चक्रवृद्धि व्याज को शास्तिक दर संवत् करने के लिए बांधी बनाएगा बांधी। भारत में आफिसर के लौटने पर, वसूल से अप्रप्त कोई रकम, रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुम्बई द्वारा मासिक वेतन बिलों में से पहले की तरह ही काटी जाएगी।”

(4) उप-विनियम (6) में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) व्याज की शास्तिक दर व्याज की चक्रवृद्धि दर होगी और उसे पश्चात्पूर्ति अवधि के लिये व्याज की भांवी धर की संगणना के प्रयोजनार्थ मासिक अन्तरालों पर मूल धन में जोड़ दिया जाएगा।”।

81. विनियम 244 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 244 में, खण्ड 4 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(छ) वह तारीख जिसको स्थायी नियुक्ति में का कोई आफिसर सेवा-निवृत्त होने वाला है या वह तारीख जिसको अस्थायी आयोग धारण करने वाले आफिसरों की विद्यमान नियुक्ति समाप्त हो।

(ज) आफिसर से इस बात का प्रमाणपत्र कि उसे स्थानान्तरण के आदेश नहीं मिले हुये हैं या उसका अस्थायी कर्तव्य शिक्षण/क्रम या छुट्टी पर विदेश जाना सम्भाव्य है।”।

82. विनियम 248 का प्रतिस्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 248 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“248—मंजूरी प्राधिकारी और अनुज्ञेय उधार की रकम.—आफिसर जिन को मोटर साइकिल खरीदने के लिये उधार अनुज्ञेय हैं, मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी और ऐसे उधारों की भात्ता नीचे की सारणी में दी गई हैं।

सारणी

जिसको अनुज्ञेय है	मंजूरी प्राधिकारी	अनुज्ञेय रकम
(क) नौसेना मुख्यालयों में सेवा करने वाले (नौसेनाध्यक्ष से भिन्न) सभी नौसैनिक आफिसर।	नौसेनाध्यक्ष	3,000 रुपये तक या 10 मास का वेतन या मोटर-साइकिल की प्रत्याशित कीमत इन में से जो भी कम हो।

जिसको अनुज्ञेय है	मंजूरी प्राधिकारी	अनुज्ञेय रकम
(ख) नौसैनिक मुख्यालयों से बाहर तट-स्थित नौसेना स्थापनों में सेवा करने वाले सभी नौसैनिक आफिसर ।	(i) फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान, मुम्बई । (ii) फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान, विशाखा-पत्तनम । (iii) फ्लैग आफिसर, कमांडिंग, दक्षिणी नौसेना क्षेत्र, कोचीन, यथा-स्थिति ।	—यथोक्त—
(ग) जल पर की नियुक्तियों पर सेवा करने वाले नौसैनिक आफिसर ।	(i) फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान, मुम्बई । (ii) फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम । (iii) फ्लैग आफिसर, कमांडिंग, दक्षिणी नौसेना क्षेत्र, कोचीन : यथास्थिति ।	
(घ) इंस्ट्रक्शनल स्टाफ एण्ड स्टुडेंट आफिसर, रक्षा सेवा स्टाफ कालेज, वेलिंग्टन ।	कमांडेंट, रक्षा सेवा स्टाफ कालेज, वेलिंग्टन ।	
(ङ) स्टाफ एण्ड स्टुडेंट आफिसर, जिन्हें वेतन रक्षा प्राक्कलनों, राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली से दिया जाता है ।	कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली ।”	

83. विनियम 249 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 249 में, “48 किशों” श्रृंखलाओं और शब्दों के स्थान पर, “60 किशों” श्रृंखलाओं और शब्द रखे जाएंगे ।

84. विनियम 251 का प्रतिस्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 251 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“251. पात्रता.—आइसकिल खरीदने के लिये उधार सभी निरन्तर सेवा वाले नौसैनिकों को अनुदान किया जाएगा ।”

85. **विनियम 253 का संशोधन**—उक्त विनियमों के विनियम 253 में, विद्यमान खण्ड (क) से (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) भारतीय नौसैनिक पोत “इण्डिया” पर सेवा करने वाले नौसैनिकों की दशा में, नौसेनाध्यक्ष या ऐसा आफिसर जिसको उसने अपनी शक्तियों प्रत्यायोजित कर दी हों ।

(ख) फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान, मुम्बई ।

(ग) फ्लैग आफिसर कमांडिंग, पश्चिमी फ्लोट ।

(घ) फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम ।

(ङ) फ्लैग आफिसर कमांडिंग, दक्षिणी नौसेना क्षेत्र, कोचीन ।

(च) भारसाधक नौसैनिक आफिसर, गोवा ।” ।

86. **विनियम 251 का संशोधन**—उक्त विनियमों के विनियम 254 में, उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5-क) नकदी रसीद और साथ ही खरीदी गई सवारी के व्यौरे सम्पूत प्राधिकारी को उधार लेने से एक मास के भीतर भेजे जाएंगे । यदि नकदी रसीद नियत एक मास की अवधि के भीतर नहीं भेजी गई हो तो उधार की पूरी रकम और साथ ही एक मास के लिए उस पर व्याज तुरन्त वापस करना होगा ।” ।

87. **नए विनियम 257 का अन्तःस्थापन**—उक्त विनियमों के विनियम 257 के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्षक और विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“असाधारण प्रचण्डता की बाढ़, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा प्रभावित नौसैनिक को अग्रिम वेतन

257-क. **अग्रिम वेतन**—नियमित नियुक्ति पर के सभी नौसैनिकों, जब भी वे असाधारण प्रचण्डता की बाढ़, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित हुए हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन सुविधाओं के दिए जाने के लिए अर्हता के रूप में घोषित की गई हैं, तीन मास तक का वेतन (जिसके अन्तर्गत भत्ता नहीं है किन्तु जिसके अन्तर्गत रैंक नियुक्ति वेतन और सदाचरण वेतन, जहां कहीं लागू हो, आते हैं) या 500 रु०, इन में से जो भी कम हो प्रत्येक ऐसी घटना की दशा में बिना व्याज अग्रिम तोचे दिनिदिष्ट शर्तों के अधीन दिया जा सकेगा :—

(i) अग्रिम, कमान आफिसर या प्रशासनिक प्रधान द्वारा उन व्यक्तियों को ही मंजूर किए जाएंगे जो प्राकृतिक विपत्ति से प्रभावित हुए हैं ।

(ii) अग्रिम की रकम बारह मासिक किश्तों से अतिरिक्त किश्तों में वसूल की जा सकेगी जो अग्रिम लेने के पश्चात् दूसरी बार दिए जाने वाले वेतन से प्रारम्भ होगी । ऐसी दशा में, जिसमें किसी व्यक्ति के 12 मास तक सेवा में रहने की संभावना न हो वहां, मंजूरी प्राधिकारी यह निदेश देगा कि अग्रिम प्रभावी सेवा की प्रत्यक्ष अवधि के दौरान प्रति-मंदत कर दिया जाए । जहां वसूली 12 मास से कम की अवधि में की जानी हो वहां मंजूरी प्राधिकारी उस रकम से कम रकम जो अन्यथा अनुमेय हो, अपने विवेकानुसार अनुमान कर सकेगा ताकि अग्रिम लेने वाले को वसूली के कारण असम्भ्यक असुविधा न हो ।

- (iii) यदि उसी प्रयोजन के लिए रिया गया पूर्ववर्ती अग्रिम असमायोजित रह गया हो तो उस मद्धे द्वितीय अग्रिम सामान्यतः मंजूर नहीं किया जाएगा। किन्तु यदि द्वितीय अग्रिम का अनुदत्त किया जाना आवश्यक हो तो द्वितीय अग्रिम और प्रथम अग्रिम के बकाया अतिशेष की मात्रा ऊपर विहित सीमा से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अग्रिम केवल उन व्यक्तियों को ही अनुदत्त किया जाएगा जिन्होंने ऐसे सरकारी आदेशों के निष्काते जाने से तीन मास के भीतर सहायता के लिए आवेदन किया हो, जिनमें कोई प्राकृतिक विपत्ति उक्त अग्रिम के अनुदत्त किए जाने के लिए अर्हता के रूप में घोषित की गई हो।

नौसैनिकों, बाँयों और शिक्षुओं को महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसर पर अग्रिम वेतन

257.—ख—पात्रता अग्रिम लेना, शर्तें, वसूली आदि:—(1) नियमित नियुक्ति के सभी नौसैनिकों, बाँयों और शिक्षुओं को महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसर पर अग्रिम वेतन अनुदत्त किया जा सकेगा।

(2) अग्रिम की रकम सौ रुपये या एक मास का वेतन (जिसके अन्तर्गत सदाचरण वेतन कार्यकारी भत्ता और मंहगाई वेतन भी आते हैं) इन में से जो भी कम हो, होगी।

(3) (क) अग्रिम सम्पूक्त उत्सव से पहले लिया जाएगा। यह केवल उन्हीं को अनुज्ञेय होगा जो अग्रिम लेने के समय, कर्तव्य पर हों और जिनके आई० आर० एल० एज ने उनके नामे अतिशेष न हों।

(ख) यद्यपि कोई उत्सव उस वर्ष में दो बार पड़ता हो तो भी, अग्रिम, किसी पोत या स्थापन में सेवा करने वाले प्रत्येक समुदाय के सदस्यों के लिए किसी कलेंडर वर्ष में केवल एक अवसर पर अनुज्ञेय होगा। यह केवल तब ही मंजूर किया जाएगा जब किसी पूर्व अवसर पर मंजूर किया गया उत्सव अग्रिम पूर्णतः वसूल किया जा चुका हो।

(4) अग्रिम, पांच बराबर मासिक किश्तों से अतिरिक्त किश्तों में वसूल किया जाएगा, जो अगले मास के नियमित सहाय से प्रारम्भ होंगी। प्रत्येक किश्त की रकम निकटतम रूप्यों में पूर्णांकित की जाएगी, और अतिशेष अन्तिम किश्त में वसूल किया जाएगा।

(5) पोत या स्थापन का कमान आफिसर ऐसे अवसरों पर अग्रिम वेतन अनुदत्त करने के लिए प्राधिकृत होगा। वह ऐसे नौसैनिकों को जो नियमित नियुक्ति पर सेवा नहीं कर रहे हों और जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा जिनका अग्रिम के समायोजन तक सेवा में बना रहना सम्भाव्य है, ऐसे अग्रिम अपने विवेकानुसार मंजूर करेगा।

(6) प्रत्येक समुदाय के लिए ऐसा अवसर पोत और स्थापनों के कमान आफिसरों द्वारा नियत किया जाएगा। किन्तु एक किसी समुदाय के लिए एक से अधिक अवसर नियत किए जा सकेंगे यदि उनकी राय में पोत या स्थापन की स्टाफ संरचना को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना वांछनीय हो। गणतन्त्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस अग्रिम वेतन के प्रयोजन के लिए उत्सव के अवसर माने जा सकेंगे।”।

88. विनियम 259 और 260 का लोप.—उक्त विनियमों के उपशीर्षक और विनियम 259 और 260 का लोप कर दिया जाएगा।

89. विनियम 261 का संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 261 में,—

(1) इसके ऊपर के उपशीर्षक “भाटक” शब्द के स्थान पर, “अनुज्ञप्ति फीस” शब्द रखे जाएंगे।

(2) “भाटक” शब्दों के स्थान पर, “अनुज्ञप्ति फीस”, शब्द रखे जाएंगे।

90. नए अध्याय 13 और नये विनियम 266-272 का अन्तःस्थापन.—उक्त विनियमों के विनियम 265 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय और विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“अध्याय 13

ऐसे मास्टर मुख्य पेट्टी आफिसरों के वेतन और भत्ते जिनको विशेष कर्त्तव्य सूची में अवैतनिक आयोग अनुवृत्त किया गया है

विषय	विनियम सं०
वेतन की दरें	266
प्रतिकरात्मक भत्ता	267
मंहगाई भत्ता	268
परिधान भत्ता	269
छुट्टी भत्ता	270
अन्य भत्ते	271
अग्रिम वेतन	272

266. वेतन के दरें.—अवैतनिक आयुक्त आफिसरों को निम्नलिखित दरों पर वेतन दिया जाएगा, अर्थात् :—

अवैतनिक सब-लेफ्टीनेंट (विशेष कर्त्तव्य) 470 रु०

अवैतनिक लेफ्टीनेंट (विशेष कर्त्तव्य) 570 रु०

267. प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता.—अवैतनिक आयुक्त आफिसर प्रतिकरात्मक नगर भत्ता ऐसे आस्थानों पर जहां यह नौसैनिकों को अनुज्ञेय हो, सिविलियनों को समसमय पर अनुज्ञेय पूर्ण दरों पर, प्राप्त करने के हकदार होंगे

268. मंहगाई भत्ता.—अवैतनिक आयुक्त आफिसर, ऐसे सिविलियन । जिन्हें वेतन रक्षा सेवा प्राक्कलनों से दिया जाता है सिविलियन सरकारी सेवाओं को समय-समय पर लागू दरों पर और शर्तों के अधीन, मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे

269. **परिधान भत्ता**.—सक्रिय सूची में के किसी अवैतनिक आयुक्त आफिसर को परिधान भत्ता एसी किट जिसे रखना उससे अपेक्षित हो की वास्तविक लागत के बराबर किन्तु अधिकतम 720 रु० अनुदत्त किया जाएगा; परन्तु यह तब जब कि ऐसे क्रम के समर्थन में वाउचर पेश किए गए हों और उसके कमान आफिसर ने यह प्रमाणित किया हो कि किट उपयुक्त है और उसके अनदेशों के अधीन क्रय की गई थी।
270. **छुट्टी भत्ता**.—अवैतनिक आयुक्त आफिसर छुट्टी भत्तों की बाबत नौसैनिकों को लागू होने वाले विनियमों द्वारा शासित होंगे।
271. **ग्रन्थ भत्ते**.—अवैतनिक आयुक्त आफिसर नौसैनिकों को अनुज्ञय किन्हीं ग्रन्थ सुविधाओं या उनके बदले में भत्तों, जैसे मुफ्त राशन (सिवाय उसके जहाँ आयुक्त आफिसरों को जल पर सेवा करते समय वैसी ही परिस्थितियों में अनुज्ञय हों), मुफ्त कपड़े किट संधारण भत्ते सफाई भत्ते, केश कर्तन/केश सफाई और धुलाई भत्ते, के हकदार नहीं होंगे।
272. **अग्रिम वेतन**.—अग्रिम वेतन के प्रयोजन के लिए अवैतनिक आयुक्त आफिसर, नौसेना के आयुक्त आफिसरों को लागू नियमों द्वारा शासित होंगे।”
91. **परिशिष्ट 1 का संशोधन**.—उक्त विनियमों के परिशिष्ट 1 में, नियम (1) में,—
- (i) खण्ड (क) में “भत्ते आदि” शब्दों के स्थान पर, “प्रीविलिजसबंदी भत्ता और ऐसे ग्रन्थ भत्ते” गड़द रखे जाएंगे;
- (ii) खण्ड (ग) में-उपखण्ड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “(iii) पनडुब्बी भत्ता।”
92. **परिशिष्ट 4 का संशोधन**.—उक्त विनियमों के परिशिष्ट 4 में,—
- (1) मद (i) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “टिप्पण :—कमांडर के रैंक, जो प्राधिकृत नियुक्तियों के खिलाफ धारित नहीं हैं, में ऐसे कालवेतनमान द्वारा अधिष्ठायी तौर पर प्रोन्नत किए गए आफिसर 1460 रु० प्रतिमास नियत वेतन लेंगे :
- परन्तु यदि ऐसे आफिसर, कमांडर (चयनात्मक) द्वारा धारणीय रिक्तियों में कार्य करने के लिए किसी एक समय पर छः मास से अधिक अवधि के लिए नियुक्त किए गए हों तो वे पश्चात्तवी को अनुज्ञेय वेतन लेंगे।”
- (2) मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित पद रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “(ii) कप्तान (कार्यकारी या अधिष्ठायी)—

1550-1610-1670-1730-1850-1950-2050-2150 रु०।”

93. परिशिष्ट 6 का संशोधन.—उक्त विनियमों के परिशिष्ट 6 में सारणी के स्तम्भ 1 में “कार्यकारी सब-लेफ्टीनेंट (विशेष कर्तव्य)” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात् :—

“कार्यकारी सब-लेफ्टीनेंट (विशेष कर्तव्य) जब वह परीक्षाधीन हो/अस्थायी हो।”।

94. परिशिष्ट 8 का संशोधन.—उक्त विनियमों के परिशिष्ट 8 में,—

(i) खण्ड 1 में,—

(क) शीर्षक में “75 रु० प्रति मास” पद के स्थान पर “100 रु० प्रति मास” पद रखा जाएगा;

(ख) उप-शीर्षक “कार्यपालक आफिसर” के नीचे मद 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“3. दूर टारपीडो पनडुब्बी-शोध पाठ्यक्रम (टी ए एस)।

4. दूर नौचालन और निदेश पाठ्यक्रम (एनडी)।”।

(ग) उप-शीर्षक “विद्युत आफिसर” के नीचे भिन्न ५ के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“9क. उच्च आर्टिसेन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम यूनाइटेड किंगडम।”।

(घ) “शिक्षक आफिसर” उप-शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 13 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

“13क. नौचालन और निदेश पाठ्यक्रम (एनडी)।

13ख. दूर संचार पाठ्यक्रम (सी)।”।

(ङ) उप-शीर्षक “नेवल विमानन आफिसर” के नीचे मद 1 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“16क. अहित नौचालन शिक्षक प्रवर्ग क और क. 2”।

(च) प्रविष्टि 24 में मद ग के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(य) दूर संचार इंजीनियर संस्था (भारत) यदि उस संस्था द्वारा आयोजित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्राप्त की हो। (इंजीनियरी शाखा और सिविल इंजीनियरी निदेशालय के आफिसरों से भिन्न आफिसरों के लिए);

(ऊ) इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो इंजीनियर संस्था, लंडन (केवल विद्युत शाखा के आफिसरों के लिए)।”।

(ii) खण्ड 2 में,—

(क) शीर्षक में “50 रु० प्रति मास” पद के स्थान पर “70 रु० प्रति मास” पद रखा जाएगा;

(ख) उप-शीर्षक “नेवल विमानन आफिसर” के नीचे मद 2 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“2क. नौचालन शिक्षक प्रवर्ग ‘ख’ ।”

(ग) प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“9. इंजीनियर संस्था (भारत) से सह सदस्यता परीक्षा के भाग ‘क’ और ‘ख’ उत्तीर्ण या ऐसी कोई इंजीनियरी की उपाधी या अर्हता जिसे इंजीनियर संस्था (भारत) अपनी सह सदस्यता परीक्षा के भाग ‘क’ और ‘ख’ से छूट देने के लिए मान्यता देती है ।

9क. दूर संचार इंजीनियर संस्था (भारत) से स्नातक सदस्यता परीक्षा में उत्तीर्ण (इंजीनियरी शाखा और सिविल इंजीनियरी निदेशालय के आफिसरों से भिन्न आफिसरों के लिए) ।”;

(घ) मद 13 के ऊपर के उप-शीर्षक “शिक्षक आफिसर” के स्थान पर उप-शीर्षक “शिक्षा आफिसर” रखा जाएगा;

(iii) खण्ड 3 के शीर्षक में “1800 रु०” पद के स्थान पर “2400 रु०” पद रखा जाएगा;

(iv) खण्ड 4 के शीर्षक में “1200 रु०” पद के स्थान पर “1600 रु०” पद रखा जाएगा ।

95. परिशिष्ट 9 का संशोधन.— उक्त विनियमों के परिशिष्ट 9 में,—

(i) शीर्षक “ग्रुप ‘क’ ” के नीचे सारणी में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“मास्टर मुख्य परिशिल्पी II मास्टर मुख्य मेकैनिशियन II 277-18-307

मास्टर मुख्य परिशिल्पी I मास्टर मुख्य मेकैनिशियन I 317-10-347.” ।

(ii) शीर्षक “ग्रुप ‘ख’ (मैट्रिकुलेट प्रविष्टि)” के नीचे सारणी में,—

(क) पहले स्तम्भ में “सिक बर्थ परिवारक” शब्दों के स्थान पर “चिकित्सीय सहायक” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे और तीसरे स्तम्भों के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“मास्टर मुख्य पैंटी आफिसर II 190-10-210

मास्टर मुख्य पैंटी आफिसर I 220-10-250 ।” ।

(ग) अन्त में निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“टिप्पण :—नीचे दी गई विशेषज्ञ अर्हताओं में से किसी के अर्जित कर लेने पर चिकित्सीय सहायकों का दर्जा वेतन के प्रयोजन के लिए ग्रुप ‘ख’ से नेवल विमानन नौसैनिकों के तत्स्थानी प्रवर्गों को अनुज्ञेय वेतन की दरों में बढ़ा दिया जाएगा :—

नाम और विशेषज्ञ अर्हता पाठ्यक्रम

वर्ग

1. उन्नत परिचर्या]

1 और 2

2. चिकित्सीय स्टोर

1 और 2

3. प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीकी	1 और 2
4. शस्त्रकर्म गृह तकनीकी	1 और 2
5. रेडियोग्राफी (एक्सरे) सहायक और/या तकनीकी	1 और 2
6. विशेष रोग	1 और 2
7. भौतिक चिकित्सा	1 और 2
8. स्वास्थ्य विज्ञान	1 और 2
9. मनोविकार विज्ञान परिचर्या	1 और 2
10. दंत शस्त्रकर्म गृह सहायक	1 और 2
11. रक्तधान सहायक	1 और 2
12. औषधवितरक	1 और 2
13. दन्त तकनीकी और/या दंत स्वास्थ्य-विज्ञानी	1 और 2 ।”

(iii) शीर्षक “ग्रुप ‘ग’ ” के नीचे, सारणी में, दूसरे और तीसरे स्तम्भ के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

“मास्टर मुख्य पैटी आफिसर II	190-10-210
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर I	220-10-250 1”1

(iv) शीर्षक “नेवल विमानन नौसैनिक” के नीचे, प्रविष्टि (ख) के नीचे, सारणी में, दूसरे और तीसरे स्तम्भों के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

“मास्टर मुख्य पैटी आफिसर II	252-10-282
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर I	292-20-322 1”1

96. परिशिष्ट 11-ख का संशोधन.—उक्त विनियमों के परिशिष्ट 11-ख में, प्ररूप के पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2. जिसके साक्ष्य स्वरूप उधार लेने वाले ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....
.....मंत्रालय/कार्यालय में
श्री..... (पदाभिधान)
.....ने इस पर
अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं”।

97. उक्त विनियमों के परिशिष्ट 11—छ के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

“परिशिष्ट II ज

(विनियम 239 देखें)

मोटरगाड़ी खरीदने के लिए उधार लेते समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप (इसका प्रयोग तब ही किया जाएगा जब खरीद, विनियम 239 के अनुसार उधार प्राप्त करने के पूर्व प्राइवेट उधार लेकर की गई हो, अन्य दशाओं में परिशिष्ट 11ख का प्रयोग किया जाएगा)।

एक पक्षकार के रूप में..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उधार लेने वाला” कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि होंगे) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राष्ट्रपति” कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी होंगे) के बीच एक हजार नौ सौ..... के/की..... के..... दिन किया गया करार।

यतः उधार लेने वाले ने इसके नीचे लिखी अनुसूची में वर्णित मोटरगाड़ी (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त मोटरगाड़ी” कहा गया है) खरीद ली है वह उसे खरीदने के लिए सहमत हो गया है।

और यतः उधार लेने वाले ने नौसेना (बेतन और भत्ते) विनियम, 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त विनियमों” कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन भी होंगे) के उप-बन्धों के अधीन मोटरगाड़ी खरीदने के लिए..... रु० के उधार देने के लिए राष्ट्रपति को आवेदन किया है।

और यतः राष्ट्रपति इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट निबन्धनों और शर्तों पर उधार लेने वाले को उक्त रकम उधार देने के लिए सहमत हो गए हैं।

अतः अब इसके पक्षकारों के बीच इसके द्वारा यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाले को राष्ट्रपति द्वारा संदत्त की गई..... रु० की राशि (जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाला इसके द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत करता है) के प्रतिपत्तस्वरूप, उधार लेने वाला राष्ट्रपति के साथ इसके द्वारा यह करार करता है कि वह (1) उक्त विनियमों के अनुसार संगणित व्याज सहित उक्त रकम का राष्ट्रपति को प्रतिसंदाय अपने बेतन में से मासिक कटौतियों द्वारा करेगा, जैसा कि उक्त विनियमों में उपबन्धित है, और ऐसी कटौतियाँ करने के लिए राष्ट्रपति को इसके द्वारा प्राधिकृत करता है और (2) इस विलेख की तारीख एक मास के भीतर उक्त उधार की पूरी रकम उक्त मोटरगाड़ी खरीदने के लिए प्राइवेट पार्टी/..... बैंक से उसके द्वारा लिए गए उधार के प्रतिसंदाय में व्यय करेगा या यदि वी गई वास्तविक कीमत या लिया गया प्राइवेट उधार, उधार की रकम से कम हो तो उस अन्तर का राष्ट्रपति को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा, और (3) उक्त मोटरगाड़ी को, उधार लेने वाले को पूर्वोक्त रूप से उधार वी गई रकम और व्याज के लिए प्रतिभुति के रूप में राष्ट्रपति के पक्ष में आबमान रखने के लिए उक्त विनियमों द्वारा उपबन्धित प्ररूप में वस्तावेज निष्पादित करेगा, और अस्ततः इसके द्वारा यह करार घोषित किया जाता है कि यदि मोटरगाड़ी उक्त विलेख की तारीख से एक मास में भीतर पूर्वोक्त रूप में खरीदी नहीं जाती है और आबमान नहीं रखी जाती है या यदि उधार लेने वाला उक्त मोटरगाड़ी के खरीदने के अभिव्यक्त प्रयोजन के लिए प्राइवेट पार्टी/..... बैंक से उसके द्वारा

लिए गए। उधार की रकम का इस बिलेख की तारीख से एक मास के भीतर प्रतिसंदाय नहीं करता है या यदि उधार लेने वाला उम्र अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या सरकारी सेवा छोड़ देता है या मर जाता है, तो उधार की सम्पूर्ण रकम और उस पर उद्भूत ब्याज तुरन्त शोध्य और प्रतिसंवेद्य हो जाएगा।

अनुसूची

मोटरगाड़ी का वर्णन

निर्माता का नाम

वर्णन

सिलिंडरों की संख्या

इंजन सं०

चेसिस सं०

लागत कीमत

जिसके साक्ष्यस्वरूप उधार लेने वाले ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और राष्ट्रपति के लिए और उनकी और से, मंत्रालय/कार्यालय में श्री..... ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में उक्त

*

द्वारा हस्ताक्षरित।

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदाभिधान)

(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में (भारत के

राष्ट्रपति के लिये और उनकी

और से)-----

----- (नाम और

पदाभिधान) द्वारा हस्ताक्षरित।

(आफिसर के हस्ताक्षर और पदाभिधान)

परिशिष्ट 11 अ

(विनियम 239 देखें)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मोटरगाड़ी उपलब्ध है और मैं चैक दिए जाने की तारीख से एक मास के भीतर मोटरगाड़ी खरीद लूंगा। यदि चैक दिए जाने की तारीख से एक मास के भीतर मोटरगाड़ी नहीं खरीदी गई, तो मैं उधार की गई पूरी रकम और साथ ही ब्याज एक मुश्त वापस कर दूंगा।

स्थान

तारीख

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदाभिधान)

*उधार लेने वाले का नाम और पदाभिधान।

परिशिष्ट 11 अ

(विनियम 242 देखें)

पुरानी मोटरगाड़ी के खरीदने के लिए सरकार द्वारा पहले मंजूर किए गए सम्पूर्ण उधार-धन और उस पर व्याज का प्रतिसंदाय करने के पूर्व उक्त मोटरगाड़ी के विक्रय-आगम से ऋण की गई मोटर गाड़ी के लिए बंधक-पत्र का प्ररूप।

एक पक्षकार के रूप में श्री का पुत्र श्री (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उधार लेने वाला" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत, जब तक कि विषय या संदर्भ से अपवर्जित या में विरुद्ध न हों उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक और विधिका प्रतिनिधि होंगे) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि विषय या संदर्भ से अपवर्जित या में विरुद्ध न हो; उनके पदांतरवर्ती और समनुदेशित होंगे; के बीच के/की के दिन किया गया करारनामा।

यतः बन्धक-विलेख, तारीख द्वारा, उसकी अनुसूची में वर्णित मोटरगाड़ी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पुरानी मोटरगाड़ी" कहा गया है) उधार लेने वाले द्वारा पुरानी मोटरगाड़ी के खरीदने के हेतु लिए गए रु० (शब्दों और अंकों दोनों में) के उधार और साथ ही उस पर उक्त बंधक-विलेख (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विलेख" कहा गया है) में वर्णित शर्तों और दर पर व्याज की प्रतिभूत करने के लिए राष्ट्रपति को बंधक की गई थी।

और यतः उधार लेने वाले को राष्ट्रपति द्वारा उधार दी गई उक्त रु० की राशि में से उधार लेने वाले ने आंशिक प्रतिसंदाय कर दिए हैं और मूलधन के रूप में रु० (शब्दों और अंकों दोनों में) की राशि और उस पर मूल विलेख के निबन्धनों के अनुसार व्याज उधार लेने वाले द्वारा राष्ट्रपति को अब भी शोध्य और देय है।

और यतः उधार लेने वाले ने जिसे नई मोटरगाड़ी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नई मोटरगाड़ी" कहा गया है) की आवश्यकता है अपनी पुरानी मोटर गाड़ी बेचने और नई मोटरगाड़ी खरीदने की अनुज्ञा के लिए राष्ट्रपति को आवेदन किया है और यतः नोसेना (बेतन और भत्ते) विनियम 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त विनियमों" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उस समय प्रयुक्त उसके कोई संशोधन या परिवर्धन होंगे) के विनियम 242 के निबन्धनों पर पुरानी मोटरगाड़ी बेचने और पुरानी मोटरगाड़ी के विक्रय आगम का नई मोटरगाड़ी खरीदने के लिए उपयोग करने के लिए उधार लेने वाले को इस शर्त पर अनुज्ञा दी गई है कि नई मोटरगाड़ी उधार लेने वाले से राष्ट्रपति को इस प्रकार देय और गेब रही राशि के प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रपति को बंधकित की जाएगी और यतः अब रु० की राशि उधार लेने वाले से मूलधन मध्ये देय और गेब है और यतः उधार लेने वाला उसके अतिरिक्त मूल विलेख के निबन्धनों के अनुसार व्याज देने का दायी है।

अतः अब यह करारनामा इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिभूति के लिए उधार लेने वाला इसके द्वारा यह प्रसंविदा करता है कि वह पूर्वोक्त रु० की राशि का प्रत्येक रु० के बराबर मासिक किस्तों में प्रत्येक मास के प्रथम दिन प्रतिसंदाय करेगा और मूल रूप से उसको उधार दी गई रु० की राशि (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूलधन" कहा गया है) पर मूल विलेख के निबन्धनों के अनुसार व्याज देगा तथा उधार लेने वाला इस बात के लिए सहमत है कि ऐसे संदाय उक्त विनियमों द्वारा उपबन्धित रीति में उसके बेतन से मासिक कटौतियों द्वारा

बनूँ कि मैं या सभे और उधार लेने वाला ऐसी कटौतियाँ करने के लिए राष्ट्रपति को इसके द्वारा प्राधिकृत करना है और उक्त करार के ही अनुसरण में उधार लेने वाला मोटरगाड़ी को जिसकी विनिश्चिष्टता नीचे लिखी अनुसूची में उपबर्णित है उक्त उधार और उस पर व्याज के लिए प्रतिभूति के तौर पर उक्त विनियमों द्वारा अपेक्षित रूप में राष्ट्रपति को इसके द्वारा समनुदेशित और अन्तरित करता है ?

और उधार लेने वाला इसके द्वारा करार करता है और यह घोषित करता है कि उसने उक्त मोटरगाड़ी को सम्पूर्ण ऋण कीमत और/या सम्यक रूप से संदेय समस्त रकम संदत्त कर दी है और वह पूर्ण रूप में उसकी सम्पत्ति है और उसने उसे गिरवी ग्राहमान या बंधक नहीं किया है और जब तक मूलधन के सम्बन्ध में कोई धन राष्ट्रपति को संदेय रहता है तब तक वह उक्त मोटरगाड़ी न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा, न ग्राहमान करेगा, न बन्धक करेगा और न उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ेगा। परन्तु संविदा यह और इसके द्वारा यह करार और घोषित किया जाता है कि यदि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त या व्याज देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रूप में संदत्त नहीं कर दिया जाता या वसूल नहीं कर लिया जाता या यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाए या वह किसी समय सरकारी सेवा में रहे अथवा यदि उधार लेने वाला उक्त मोटरगाड़ी को बेच दे या गिरवी रख दे या उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ दे अथवा बंदिवा लिया हो जाए या अपने लेनदारों के साथ कोई प्रशमन या ठहाराव करले अथवा यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के खिलाफ किसी डिक्री या निर्णय के निष्पादन कार्यवाहियों आरम्भ करे तो मूलधन का अतिशेष जो उस समय देय और असंदत्त हो तथा मूलधन पर पूर्वोक्त रूप में संगणित व्याज तुरन्त संदेय हो जाएंगे और इसके द्वारा यह करार और घोषित किया जाता है कि इसमें इसके पूर्व उल्लिखित घटनाओं में से किसी के होने पर राष्ट्रपति उक्त मोटरगाड़ी को अभिग्रहीत कर सकेंगे और उसका कब्जा ले सकेंगे तथा या तो उसके हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेंगे या उक्त मोटरगाड़ी को हटा सकेंगे और लोक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा उसे बेच सकेंगे तथा शुद्ध विक्रय आगम में से मूलधन का उस समय असंदत्त रहा अतिशेष और मूलधन पर पूर्वोक्त रूप में संगणित उस समय देय कोई व्याज और इसके अधीन अपने अधिकारों को बनाए रखने, उनकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से उपगत किए गए सब खर्च, प्रभार, व्यय और संदाय प्रतिधारित रख सकेंगे तथा यदि कोई अधिशेष बच रहे तो उसे उधार लेने वाले उसके निष्पादकों, प्रशासकों या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को संदत्त कर देंगे परन्तु यह और कि उक्त मोटरगाड़ी का कब्जा लेने या उसका विक्रय करने की पूर्वोक्त शक्ति से उधार लेने वाले पर या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त देय रह गए अतिशेष और व्याज के लिए अथवा मोटरगाड़ी बेच दिए जाने की दशा में उतनी रकम के लिए जितनी से शुद्ध विक्रय-आगम देय रकम से कम पड़े बाद लाने के राष्ट्रपति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उधार लेने वाला इसके द्वारा यह और करार करता है कि जब तक कोई धनराशि राष्ट्रपति को देय और शेष रहे तब तक वह अर्थात् उधार लेने वाला उक्त मोटरगाड़ी का अग्नि, चोरी या दुर्घटना से किसी हानि या नुकसान के खिलाफ किसी बीमा कम्पनी ने जो रक्षा लेखा नियंत्रक (नीसेना) द्वारा अनुमोदित की जाए उस मोटरगाड़ी के पूरे मूल्य के लिए बीमा कराएगा और बीमाकृत रखेगा तथा रक्षा लेखा नियंत्रक (नीसेना) को समाधान प्रद रूप में इस बात का साक्ष्य पेश करेगा कि उस कम्पनी को जिसमें उक्त मोटरगाड़ी का बीमा कराया गया है यह सूचना मिल चुकी है कि उस पालिसी में राष्ट्रपति हितबद्ध है और उधार लेने वाला उसके द्वारा यह और करार करता है कि वह उक्त मोटरगाड़ी को नष्ट या क्षति नहीं करने देगा या नहीं होने देगा अथवा उसे अपने से अधिक खराब नहीं होने देगा जितनी खराब वह सामान्य घिसाई से युक्तियुक्ततः हो सकती है तथा यह और कि उक्त मोटरगाड़ी को कोई नुकसान या दुर्घटना होने की दशा में उधार लेने वाला राष्ट्रपति को तुरन्त उसके बारे में सूचित करेगा तथा उसकी मरम्मत कराएगा और उसे ठीक करा लेगा ताकि उसे उसकी पहले वाली अवस्था में फिर से लाया जा सके।

अनुसूची

मोटरगाड़ी का वर्णन

निर्माता का नाम

वर्णन

सिलिंडरों की संख्या

इंजन सं०

चेसिस सं०

लागत कीमत

जिस के साक्ष्य स्वरूप उधार लेने वाले ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से _____
मंत्रालय/कार्यालय में श्री _____ ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

1. _____

2. _____

(साक्षियों के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में उक्त

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदाभिधान)

*_____

द्वारा हस्ताक्षरित ।

1. _____

2. _____

(साक्षियों के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में (भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनको ओर से)

_____(नाम और

पदाभिधान)

द्वारा हस्ताक्षरित ।

(आफिसर के हस्ताक्षर और पदाभिधान)

परिशिष्ट 11-ठ

(विनियम 243 देखें)

मोटरगाड़ी उधार के लिए अनुपूरक बंधक-पत्र का प्ररूप

एक पक्षकार के रूप में _____ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उधार लेने वाला" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उस के बारिस, प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि होंगे) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें

*उधार लेने वाले का नाम और पदाभिधान ।

इस के पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उन के उत्तराधिकारी और समनुदेशित होंगे) के बीच आज 19-के/को-के-दिन किया गया यह करार, उक्त पक्षकारों के बीच के आडमान विलेख, तारीख (जिसे इस में इस के पश्चात् उक्त "मूल विलेख" कहा गया है) का अनुसूचक है।

यतः उधार लेने वाले ने नौसेना (बेतन और भत्ते) विनियम, 1966 (जिसे इस में इस के पश्चात् "उक्त विनियमों" कहा गया है) के निबन्धनों पर मोटरगाड़ी खरीदने के लिए-रु० उधार देने के लिए आवेदन किया था और वह मंजूर कर दिया गया था।

और यतः उक्त उधार के निबन्धनों के अनुसरण में, उधार लेने वाले ने उन उक्त मूल विलेख के द्वारा यह प्रसंविदा किया था कि वह राष्ट्रपति को उक्त-रु० की राशि या असंदत रहे उस के अतिशेष को निम्नलिखित किस्तों में प्रतिसंदत करेगा, अर्थात् पहली-किस्तें प्रत्येक-रु० के हिसाब से अगली-किस्तें प्रत्येक-रु० के हिसाब से और अगली-किस्तें प्रत्येक-रु० के हिसाब से, और कि ऐसे संदायों के लिए, प्रतिभूति के रूप में, उधार लेने वाले द्वारा मोटरगाड़ी, जिसकी विनिष्टियां उक्त मूल विलेख की अनुसूची में उपवर्णित की गई है और जो इस के नीचे की अनुसूची में भी उपवर्णित है, प्रतिभूति के तौर पर इस में उपबन्धित रूप में राष्ट्रपति को उक्त मूल विलेख के द्वारा समनुदेशित और अन्तरित की गई थी।

और यतः उधार लेने वाले ने करार पाई गई किस्तों में हेरफेर करने और मूल रूप से नियत की गई-किस्तों के बदले प्रत्येक-रु० की-किस्तों में वसूली स्वीकार करने के लिए सरकार को आवेदन किया है।

और यतः-रु० की राशि उक्त उधार लेने वाले से सरकार को अब देय और शेष है।

और यतः सरकार इसमें इस के पश्चात् कथित निबन्धनों और शर्तों पर उक्त प्रस्ताव से सहमत हो गई है।

अतः अब यह करार इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और वचनों को ध्यान में रखते हुए, उधार लेने वाला इस के द्वारा यह प्रसंविदा करता है कि वह-रु० के कुल उधार में से बकाया-रु० की राशि राष्ट्रपति को प्रत्येक-रु० की किस्तों में संदत करेगा जो-से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक मास के प्रथम दिन को संदेह होगी और उस समय देय और शेष रही राशि पर उक्त विनियमों के अनुसार संगणित व्याज देगा।

और इस के द्वारा यह करार और घोषित किया जाता है कि उक्त मूल विलेख में अन्तर्विष्ट उक्त मूल विलेख के अधीन देय किस्तों संबंधी प्रसंविदा, शक्तियां और उपबन्ध इस विलेख के अधीन देय किस्तों को लागू होंगे और इस के द्वारा फेरफार किए जाने के सिवाय, उक्त मूल विलेख के सभी निबन्धन और शर्तें पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेंगी।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

जिस के माध्यमस्वरूप सर्व प्रथम ऊपर लिखे वर्ष, मास और दिन को, — — — — — उधार लेने वाले ने इस विलेख पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और राष्ट्रपति ने अपने लिए और अपनी ओर से — — — — — से इस विलेख पर हस्ताक्षर करा दिए हैं ।

1. —————

1. —————

2. —————

2. —————

की उपस्थिति में

की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए
और उन की ओर से —————

उधार लेने वाले द्वारा

द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त ।

हस्ताक्षरित और परिदत्त ।

केस नं० 80-1/69/1258/रक्षा (वेतन/सेवा)

म० ला० दवे,

संयुक्त मन्त्रि (पी० एण्ड डब्ल्यू०) ।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March 1974

S.R.O. 9-E.—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 1966, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 1-E, dated the 5th January, 1968, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Navy (Pay and Allowances) Amendment Regulations, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of regulation 15.—In the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 1966 (hereinafter referred to as the said Regulations), in regulation 15, in sub-regulation (3), the following Note shall be added at the end, namely:—

“Note.—Acting Sub-Lieutenant (Special Duty) (on probation) who, on satisfactory completion of probationary period and on being considered fit in all respects for promotion to Sub-Lieutenant (Special Duty) cannot be confirmed on account of non-availability of a vacancy in the stabilised cadre, shall be designated as Acting Sub-Lieutenant (Special Duty) (Temporary) and shall be entitled to increments in the scale of pay as laid down in Appendix VI.”

3. Amendment of the sub-heading of Chapter IV.—In Chapter IV of the said Regulations, for the sub-heading “Compensatory (City) Allowance”, the following sub-heading shall be substituted, namely:—

“Compensatory (City) Allowance, Compensatory (Local) Allowance and Hill (Compensatory) Allowance.”

4. Substitution of regulation 22.—For regulation 22 of the said Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"22. Admissibility Ashore.—Officers serving ashore shall be entitled to receive compensatory (city) allowance, compensatory (local) allowance and hill (compensatory) allowance in all cities or localities where these allowances are admissible to civilian Government servants paid from the Defence Services Estimates, at the same rates and under the same conditions as are applicable from time to time to the latter."

5. Amendment of regulation 23.—In regulation 23 of the said Regulations—

- (1) in sub-regulation (1), for the word 'allowance' appearing in the last line, the word 'allowances' shall be substituted;
- (2) in sub-regulation (2), for the words and brackets "Compensatory (city) allowance", the words and figures "The allowances referred to in regulation 22" shall be substituted.

6. Amendment of regulation 24.—In regulation 24 of the said Regulations—

- (1) in sub-regulation (1), for the words and brackets "Compensatory (city) allowance", the words "allowances referred to in regulation 22" shall be substituted;
- (2) in sub-regulation (2), for the words and brackets "Compensatory (city) allowance", the words "the allowances" shall be substituted.

7. Amendment of regulation 25.—In regulation 25 of the said Regulations,

- (1) in sub-regulation (1)—
 - (i) for the words and brackets "Compensatory (City) Allowance", the words and brackets "Compensatory (city) allowance, compensatory (local) allowance and hill (compensatory) allowance" shall be substituted.
 - (ii) in sub-clause (i) of clause (a), for the words "two months", the words "four months" shall be substituted;
- (2) in sub-regulations (2) and (3), for the word "allowance" wherever it occurs, the word "allowances" shall be substituted.

8. Amendment of regulations 26 and 28.—In regulations 26 and 28 of the said Regulations, for the word "allowance" wherever it occurs, the word "allowances" shall be substituted.

9. Omission of regulation 27.—Regulation 27 of the said regulations shall be omitted.

10. Amendment of regulation 29.—In regulation 29 of the said Regulations, for the words and brackets "compensatory (city) allowance", the word "allowances" shall be substituted.

11. Amendment of regulation 38.—In regulation 38 of the said Regulations, for the words, abbreviation and figures "Married officers shall be entitled to disturbance allowance of Rs. 135", the following words, abbreviations and figures shall be substituted, namely:—

"Married and single officers shall be entitled to disturbance allowance of Rs. 150 and Rs. 50 respectively."

12. Amendment of regulation 40.—In regulation 40 of the said Regulations, after sub-regulations (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"(3) Disturbance allowance shall be paid at full rate when families have to move out to another family station or in the case of officers whose families move to their homes situated elsewhere in the concessional area on account of family stations becoming a concessional area, subject to the family accommodation being vacated by the officer in that station and at 2/3rd of the rate where families move into a station in concessional area on its being declared as family station."

Explanation.—The admissibility of the disturbance allowance shall not be dependent upon the move of the family at Government expense".

13. Amendment of regulation 43.—In regulation 43 of the said Regulations—

- (1) for the expression "Rs. 400", the expression "Rs. 600" shall be substituted;

(2) the following Explanation shall be inserted at the end, namely:—

“Explanation.—All married officers who are transferred to India from abroad shall also be entitled to disturbance allowance of Rs. 600 if their families move to India with them at the expense of Government”.

14. **Amendment of regulation 45.**—In regulation 45 of the said Regulations, in sub-regulation (2), for expression “Rs. 400”, the expression “Rs. 600” shall be substituted.

15. **Amendment of regulation 46.**—In regulation 46 of the said Regulations, the following Explanation shall be added at the end, namely:—

“Explanation.—The conditions relating to the movement of the family and the restriction regarding the age shall not be applicable to single officers”.

16. **Insertion of new regulations 48-A.**—After regulation 48 of the said Regulations, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely:—

“DIVERS RETAINING FEE

48-A. **Admissibility.**—Divers retaining fee at the following rates and under the conditions laid down for sailors in sub-regulations (1) to (3) of regulation 149 shall be admissible to qualified officers of the categories of “Ship’s Divers” and “Deep Divers” as shown against each:—

Officers (General and S.D. List)

(i) Ship’s Divers	..	Rs. 40 p.m.
(ii) Deep Divers	..	Rs. 75 p.m.”

17. **Amendment of regulation 49.**—In regulation 49 of the said regulations, in the Table, the following items shall be added, at the end, namely:—

(c) Others

“(i) Vice Admiral	. . .	Flag Officer Commanding-in-Chief	300
(ii) Rear Admiral	. . .	Flag Officer Commanding Western Fleet	200
(iii) Rear Admiral	. . .	Flag Officer Commanding-in-Chief/ Flag Officer Commanding Naval Area	200
(iv) Commodore	. . .	Commodore Commanding/Incharge Naval Area	100

18. **Amendment of regulation 52.**—To regulation 52 of the said Regulations, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that expatriation allowance shall not be admissible to officers proceeding abroad or returning from abroad during the period of voyage by sea, air or land.”.

19. **Amendment of regulation 53.**—In regulation 53 of the said Regulations, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

“Explanation.—This allowance shall not be admissible to officers in receipt of daily allowance or foreign allowance ex-India.”.

20. **Amendment of regulation 56.**—In regulation 56 of the said regulations,—

(1) in sub-regulation (1), for expression “Rs. 75”, the expression “Rs. 100” shall be substituted;

(2) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) In cases where it becomes necessary to preserve the dead bodies of Naval officers in a mortuary awaiting arrival of the next of kin to take part in the funeral, mortuary charges incurred shall be reimbursed subject to a ceiling of Rs. 35 per day for a maximum period of three days.”.

21. **Substitution of regulations 58 and 59.**—For regulations 58 and 59 of the said Regulations, the following regulations shall be substituted, namely:—

“58. **Admissibility.**—(1) Hardlying money shall be payable to officers including those belonging to record parties at the rates and under the conditions hereinafter provided.

(2) Hardlying money shall also be admissible for the entire period for which an officer is borne on the ship concerned except during periods of leave, sickness, temporary duty and for periods of refit or repair of the ship during which the officers are required to stay ashore.

Explanation.—Officers qualified for the grant of hardlying money for 8 days or above in a month shall be allowed the prescribed monthly rate. However, those qualifying for lesser period shall not be entitled to hardlying money for that month.

59. **Rates.**—The rates of hardlying money shall be as given below:—

Rank	Monthly rates	
	Full rates	Half rates
Lieutenant and above	Rs. 42	Rs. 21
Sub-Lieutenant and below	Rs. 20	Rs. 15

22. **Amendment of regulation 60.**—In regulation 60 of the said Regulations—

(i) in sub-regulations (1), after clause (d), the following clause shall be added, namely:—

“(e) Submarines.—Hardlying money shall also be payable to officers serving on board the following Indian Naval Submarines at full rates, namely:—

KALVARI, KHANDERI, KARANJ and KURSURA”;

(ii) in sub-regulation (2), after the word “Fleet Minesweepers”, the following words shall be added, namely:—

“RAJPUT, RANJIT, RANA, GODAVARI, GOMATI, GANGA, KUTHAR, KIRPAN, TRISHUL, TALWAR, BRAHMAPUTRA, BEAS, BETWA, KRISHNA, TIR, KAVERI, SHAKTI, MAGAR, GHARIAL, GULDAR, SUTLEJ, JAMUNA, INVESTIGATOR, KAMORTA, KADMAT, KILTAN, KAVARATTI and KATCHALL.”.

23. **Omission of regulations 61 to 65.**—Regulations 61 to 65 of the said Regulations shall be omitted.

24. **Amendment of regulation 69.**—In regulation 69 of the said Regulations, in sub-regulation (1), for the expression “Rs. 1,000”, the expression “Rs. 1,400” shall be substituted.

25. **Amendment of regulation 71.**—In regulation 71 of the said Regulations, for the expression “Rs. 1,000”, the expression “Rs. 1,200” shall be substituted.

26. **Substitution of regulation 87.**—For regulation 87 of the said Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“87. **Rates.**—The various rates of qualification pay or grant are as follows:—

27. **Amendment of regulation 88.**—In regulation 88 of the said Regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(3) An officer, who within two years of having drawn the lower rate of qualification grant acquires a qualification entitling him to the higher rate of qualification pay, shall be allowed to draw the difference between the higher and the lower rate of qualification pay till the expiry of two years after the drawal of the qualification grant. He shall be allowed the higher rate of qualification pay thereafter.”.

28. Insertion of new Regulation 92-A.—After regulation 92 of the said Regulations, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely:—
“SEPARATION ALLOWANCE

92-A. Eligibility.—(1) All married officers serving on board Indian Naval Ships, when the ships are away from the base port, shall receive separation allowance at Rs. 70 per mensem. The allowance shall be admissible to officers on casual leave availed of when the ship is away from the base port, but not on any other leave.

(2) Separation allowance shall not be admissible in addition to daily allowance.

Explanation 1.—For the purpose of this allowance, the definition of the term “married officers” shall be as laid down in regulation 47.

Explanation 2.—The said allowance shall be calculated on a proportionate basis for periods of less than a month, but shall not be admissible for ships’ absence from the base port for a period of less than 12 hours. The period shall be calculated from the time a ship leaves the base port till its return or arrival in the base port.”

29. Amendment of regulation 94.—In regulation 94 of the said Regulations, for the existing Table, the following Table shall be substituted, namely:—

*Category of Officers	Survey Allowance Rs. per mensem	Survey Bounty Rs. per mensem
4th Class Assistant Surveyor .	50	850 minus survey allowance received during the period involved
3rd Class Assistant Surveyor .	60	950 minus survey allowance received during the period involved
2nd Class Assistant Surveyor .	85	1,350 minus survey allowance received during the period involved
1st Class Assistant Surveyor .	100	1,800 minus survey allowance received during the period involved
<i>Charge</i>		
Lieutenant Commander } Commander	100	1,800 minus survey allowance, received during the period involved.
Captain	Nil	1,800

30. Substitution of new regulation 100.—For Regulation 100 of the said Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“100. Rates.—The rates of flying bounty admissible to officers are as given below:—

	Rs. per annum
(i) Sub-Lieutenants to Commanders	4200
(ii) Captains and above	3600.”

31. Substitution of new regulation 101.—For regulation 101 of the said Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“101. Requirement of an Assurance Policy Coverage.—(1) An officer of the aviation Branch who has become qualified as pilot or observer on or after the 16th December, 1967 shall be required to take out, and keep alive, endowment assurance policy/policies, or alternatively convertible life policy/policies, with definite conversion into endowment, with the Life Insurance Corporation of India covering aviation risk also, for a period of at least 20 years, the sum assured being not less than Rs. 25,000 and the average monthly

premium payable for the first 20 years being not less than Rs. 150. His eligibility for flying bounty for the first 20 years of his commissioned service shall be subject to the fulfilment of this requirement. A Life Insurance Policy taken out by the officer or by his parent/guardian in his favour, during training as officer or cadet (including the period as a cadet in the National Defence Academy) which fulfils the above mentioned requirements will also be acceptable for this purpose. The fulfilment of the above requirement will be verified and certified by the authority prescribed by Naval Headquarters for the purpose when the policy is initially taken out or if it has already been taken out when the officer becomes eligible for flying bounty. Thereafter the authority prescribed by Naval Headquarters will verify and certify at the close of each financial year that the policy has remained alive and unencumbered. As and when any of those policies mature, the officer shall subscribe the difference between Rs. 150 p.m. and the monthly premium of the current policy if any to the D.S.O.P. Fund over and above compulsory minimum rate of subscription payable under the rule.

- (2) An officer of the Aviation Branch commissioned on or after the 1st December, 1959 but before the 16th December, 1967 shall be required to take out and keep alive, such additional endowment assurance policy or alternatively convertible life policy with definite conversion into endowment with the Life Insurance Corporation of India covering aviation risk also, which together with such policies already taken out by him with the Life Insurance Corporation of India and/or the Postal Life Insurance will give him a cover of Rs. 25,000 upto at least the expiry of 20 years from the date of commissioning in the aviation branch and the total average premium or premia payable for all would come to Rs. 150 p.m. or more. Therefore, as and when any of the policies mature, the officer shall subscribe the difference between Rs. 150 p.m. and the monthly premium of the current policy/policies, if any, to the D.S.O.P. Fund over and above the compulsory minimum rate of subscription payable under the rules.
- (3) An officer serving in the aviation branch from a date prior to 1st December, 1959 shall subscribe to the D.S.O.P. Fund, in addition to the compulsory minimum rate of subscription prescribed under the rules, a sum which when added to the insurance premium paid by him for the endowment assurance, or convertible life policy/policies with the definite conversion to endowment (Life Insurance Corporation of India as well as Postal Life Insurance Fund) total Rs. 150 p.m.
- (4) A Regular Officer Aircrew shall be required to subscribe to the D.S.O.P. Fund the difference between Rs. 150 p.m. and the amount of premia paid by him monthly for sustaining endowment assurance policy/policies or convertible life assurance policy/policies with definite conversion to endowment with Life Insurance Corporation of India and/or Postal Life Insurance Fund, in addition to the compulsory minimum rate of subscription payable under the normal rules."

32. Amendment of regulation 105.—In regulation 105 of the said Regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"(3) The allowance shall not be admissible in addition to submarine pay."

33. Insertion of new regulation 105A.—After regulation 105 of the said Regulations, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely:—

"SUBMARINE PAY

105-A. Admissibility and rates.—(1) Submarine pay at the following rates shall be admissible to officers qualified for service in submarine and appointed as part crew or spare crew and also to those officers who are otherwise qualified for submarine service and hold appointments

which require them as part of their normal duties to go to sea in submarine from time to time, namely:—

Rank	Amount per mensem
Captain.	Rs. 225
Commander	Rs. 225
Lieutenant Commander	Rs. 225
Lieutenant	Rs. 225
Sub-Lieutenant	Rs. 200

(2) Submarine pay shall be treated as pay for all purposes.

(3) Submarine pay shall not be admissible in addition to submarine allowance.

(4) Submarine pay shall cease to be admissible when an officer—

(a) remains medically unfit for service in submarines for a period exceeding three months;

(b) fails to maintain the requisite standard of efficiency for submarine service as determined by the Chief of the Naval Staff;

(c) is transferred to a General Service appointment.”

34. Insertion of new regulation 122-A.—After regulation 122 of the said Regulations, the following regulation shall be inserted, namely:—

“122-A. *Leave pending retirement.*—Officers shall be eligible to opt for leave pending retirement for (i) the period shown in regulation 122 or (ii) four months leave with full pay and allowances, which will include annual leave due for the year in which they proceed on leave pending retirement. If annual leave or a portion thereof is availed of earlier in the year, the leave pending retirement will be correspondingly reduced.”

35. Amendment of regulation 125.—In regulation 125 of the said Regulations, in Group ‘B’, for the words “Sick Berth Attendants”, the words “Medical Assistants” shall be substituted.

36. Amendment of regulation 133.—In regulation 133 of the said Regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) When a sailor has been tried and convicted by a criminal court, he shall forfeit one day's pay for each day or part of a day during which he is detained by the civil power as a part of the sentence. He shall also, as a general rule, forfeit pay in like manner for the time spent in custody pending his trial.”

37. Insertion of new regulation 134-A.—Under Chapter VII of the said Regulations, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely:—

“CHILDREN'S EDUCATION ALLOWANCE

134-A. Eligibility.—(1) Sailors excepting those serving in diplomatic missions abroad, who have rendered not less than three years' service and whose pay (including increments of pay, dearness pay, good conduct pay, acting allowance, flying bounty and element of pension admissible) does not exceed Rs. 459 per month shall be eligible to receive the children's education allowance at the rates and under the conditions prescribed in regulations 134B and 134C; sailors drawing pay between Rs. 460 and Rs. 509 per month being entitled to marginal adjustment as shown in the *Illustration* below regulation 134B.

(2) All service rendered under the Central Government in any Department or office may be taken into account for the purpose of reckoning three years' service for eligibility to the Children's Education Allowance:

Provided that in the case of re-employed pensioners, service rendered prior to retirement shall not be counted for the said purpose.

- (3) Reservists called up for regular service shall be eligible for the allowance if they have put in not less than three years' service before being transferred to the reserve. If a sailor is transferred to the reserve in the middle of a year, he shall be eligible for the allowance for the year in which he is transferred to the reserve if he fulfils other conditions.

Explanation.—The allowance referred to above is limited to education upto higher secondary classes in schools which are recognised by the Department of Education or educational authorities in whose jurisdiction the school is situated. Primary classes do not include Kindergarten and infant classes.

- (4) The allowance shall also be admissible in respect of—

- (a) children studying in pre-university classes or the 1st year class of an intermediate college;

Provided they have passed the secondary, but not the higher secondary examination as defined above;

- (b) children studying in junior technical school including an Industrial Training Institute and Vocational School;

- (c) children who after passing secondary (but not higher secondary) or equivalent examination joined a polytechnic diploma college. The allowance shall, however, be admissible only during 1st year class of each college.

134-B. Rate of allowance.—(1) The allowance referred to in regulation 134-A shall be admissible at the following rates subject to the condition that the total allowance admissible to a sailor at any one time shall not exceed Rs. 50 per month, namely:—

- | | |
|---|-------------------|
| (a) Primary classes (Classes I to V) | Rs. 10 per child; |
| (b) Secondary classes (Classes VI to X) | Rs. 15 per child; |
| (c) Higher secondary class (Class XI) | Rs. 15 per child. |

- (2) In the case of a sailor drawing pay between Rs. 460 and Rs. 509 per month, the maximum allowance in respect of all the children shall not exceed the difference between Rs. 459 plus the children's education allowance at the admissible rates and their pay as indicated in the *Illustration given below*:—

Illustration.—If 'A' gets a pay of Rs. 470 and has got liabilities which would entitle him to an allowance of Rs. 30 (had his pay been Rs. 459) he shall be given the difference between Rs. 459 plus Rs. 30 and Rs. 470, *viz.* Rs. 19 per month.

134-C. Conditions.—(1) The grant of children's education allowance shall be subject to the fulfilment of the following conditions, namely:—

- (a) the child is studying and staying in a school away from the station at which the sailor is posted and/or residing;

Illustration.—'A' has headquarters at Delhi and is residing at Ghaziabad. The allowance shall not be admissible if his children are studying in a school either at Delhi or at Ghaziabad.

- (b) The child is between the age of 5 years and 18 years;

NOTE.—The allowance shall commence from the month following that in which the child attains the age of 5 years and shall cease at the end of the academic year in which the child attains the age of 18 years.

NOTE. 2.—When a child is admitted to or withdrawn from a school during the course of a month, the allowance shall be admissible for the whole of a month subject to the fulfilment of the other conditions.

NOTE 3.—On the death, retirement, discharge or release of a sailor in the middle of an academic year, the allowance shall be admissible till

the end of the academic year, only when the other prescribed conditions are also satisfied. In the case of such a discharged or released sailor the conditions prescribed above shall have to be satisfied.

NOTE 4.—A sailor initially declared as missing and subsequently declared to be dead shall be eligible for the allowance for the academic year in which he is initially declared missing. A sailor who is reported to be initially missing but who rejoins subsequently shall be eligible for the allowance as in the case of prisoners of war provided arrears of pay and allowances are admitted to him under the existing rules on the subject.

NOTE 5.—The allowance shall not be allowed where a sailor is dismissed or removed from service as a disciplinary measure.

NOTE 6.—The allowance is admissible during a period of vacation even if the children stay with their parents during vacation provided they continue to be on the rolls.

NOTE 7.—The allowance, in the case of sailors, who are drafted at the end of a month and report to the new ship or establishment in the following month after availing any joining time, shall be discontinued or admitted from the beginning of the month following that in which the sailors are drafted away;

(c) the children are sailor's legitimate children including step children and adopted children (where adoption is recognised under the personal law of the individual) and they are wholly dependent on the sailor;

(d) the wife of a sailor, in Government service, is not drawing children's education allowance under the rules applicable to civilian Government employees;

(e) the children are not studying in a foreign country except in schools located in Nepal, Bhutan or Sikkim.

NOTE.—If both the husband and wife are Central Government employees and are posted at different stations, the allowance shall not be admissible if the children are staying and/or studying at a station at which either parent is working and/or residing."

38. Substitution of regulation 135.—In Chapter VII of the said Regulations, for the sub-heading "Compensatory Allowance" and regulation 135, the following sub-headings and regulations shall be substituted, namely:—

"ACTING ALLOWANCE

135. Eligibility.—(1) Suitable Master Chief Petty Officers I and II other than those holding honorary commissions, shall receive acting allowance at the following rates when appointed in officers' vacancies in ships and establishments other than Command Headquarters and Naval Headquarters, wherever they arise as a result of shortage of officers in both General and Special Duty Lists, but not due to vacancies caused by leave, temporary duty or courses of instructions, namely:—

	Rs. p.m.
(a) Master Chief Petty Officer I when officiating in a vacancy of Lieutenant Commander;	100
(b) Master Chief Petty Officers I and II when officiating in a vacancy of Lieutenant or Sub-Lieutenant	75
(2) The appointment of a Master Chief Petty Officer II in an officer's vacancy shall, however, be subject to the further following conditions, namely:—	
(a) he should have served for 3 years as Master Chief Petty Officer II;	
(b) Master Chief Petty Officer I of that Branch is not borne in that ship or establishment;	
(c) he shall only officiate in the vacancy of a Sub-Lieutenant or Lieutenant.	

- (3) Such appointments shall be made with the prior approval of the administrative authority. No consequential advancements shall be made in place of Master Chief Petty Officers I and II appointed in lieu of officers.
- (4) The appointment together with the rank, in which officiating arrangement is made, shall be specified by the Administrative authority for admitting the appropriate rate of acting allowance to Master Chief Officers I and II. The sanctioned cadre of Lieutenant Commanders for this purpose shall be reckoned as 25 per cent of the total sanctioned cadre of Lieutenant Commanders, Lieutenants and Sub-Lieutenants, in each Branch or such other percentage as may be fixed by the Central Government from time to time.

COMPENSATORY (CITY) ALLOWANCE, COMPENSATORY (LOCAL) ALLOWANCE AND HILL (COMPENSATORY) ALLOWANCE

135A. Admissibility ashore.—Sailors excluding boys, serving ashore at places where compensatory (city) allowance, compensatory (local) allowance and hill (compensatory) allowance are admissible to non-gazetted civilian Government servants paid from the Defence Services. Estimates shall receive such allowances under the conditions applicable to civilians, but at eighty per cent of the rates (including minima and maxima) admissible to the latter from time to time.”

39. Amendment of regulation 136.—In regulation 136 of the said Regulations,

- (1) in sub-regulation (1), for the expression “regulation 135”, the expression “regulation 135A” shall be substituted;
- (2) in sub-regulation (2), for the words and brackets “compensatory (city) allowance”, the words and brackets “compensatory (city) allowance, compensatory (local) allowance and Hill (compensatory) allowance” shall be substituted.

40. Amendment of regulation 137.—In regulation 137 of the said Regulations, in clause (c), the word “and” occurring at the end shall be omitted and after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

“(cc) acting allowance, and”

41. Amendment of regulation 138.—In regulation 138 of the said Regulations,—

- (1) In the Explanation appearing at the end of sub-regulation (3), for the words “this allowance” the words “these allowances” shall be substituted;
- (2) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) When a detachment is permanently located at a station other than that of its parent establishment or that of the base port of its parent ship, the individuals, drafted to the detachment shall be treated as on permanent duty and shall be paid compensatory allowances of the station at which the detachment is located from the date of their posting:

Provided that the individuals serving with the detachment on temporary duty at a station other than that of the parent establishment or base port of the parent ship shall receive the allowances admissible at that station under the provisions of sub-regulation (3).”

42. Amendment of regulation 142.—In regulation 142 of the said Regulations,—

- (1) in sub-regulation (2), for the expression “Rs. 9” and “Rs. 7”, the expression “Rs. 12” and “Rs. 10” shall respectively be substituted;
- (2) in sub-regulation (3), for the expression “Rs. 10” and “Rs. 8” the expression “Rs. 15” and “Rs. 12” shall respectively be substituted.

43. Substitution of regulation 145.—For regulation 145 of the said Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“145. *Admissibility and rates.*—(1) Sailors and apprentices (excluding boys) shall receive dearness allowance at eighty per cent of the rates

and under the conditions applicable to civilian Government servants, as specified for them in Government orders from time to time.

- (2) The amount of dearness allowance admissible to each sailor under sub-regulation (1) shall be rounded off to the nearest rupee.”

44. Amendment of regulation 146.—In regulation 146 of the said Regulations, in clause (iii), the word “and” occurring at the end shall be omitted and after clause (iii), the following clause shall be inserted namely:—

“(iiia) acting allowance; and”

45. Amendment of regulation 148.—In regulation 148 of the said Regulations,

- (i) in sub-regulation (1), for the existing Table, the following Table shall be substituted, namely:—

Depth		Rates for the time under water or compression	
Fathoms	Metres	Paise per minute	
(a) Upto 20	36·58	8	
(b) 20 to 30	36·58 to 54·86	13	
(c) 30 to 40	54·86 to 73·15	18	
(d) 40 to 50	73·15 to 91·44	25	
(e) 50 to 60	91·44 to 109·73	32	
(f) 60 to 75	109·73 to 137·16	45	
(g) 75 to 100	137·16 to 182·88	60.”	

- (ii) sub-regulation (11) shall be omitted.

46. Insertion of new regulation 148A.—After regulation 148 of the said Regulations, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely:—

“DIVING ALLOWANCE

148A. Admissibility and rates.—(1) Sailors belonging to the authorised cadre of clearance divers shall be entitled to diving allowance pertaining to the appropriate class of the respective category, as follows, namely:—

	Rs. p.m.
Clearance Divers 1st Class	70
Clearance Divers 2nd Class	60
Clearance Divers 3rd Class	50

- (2) Clearance Divers shall be entitled to dip money at double the rates specified in sub-regulation (1) of regulation 148.”

47. Amendment of regulation 149.—In regulation 149 of the said Regulations,—

- (1) in sub-regulation (1), for clause (ii) the following clauses shall be substituted, namely:—

“(ii) Ships Divers	Rs. 35 p.m.
“(iii) Deep Divers	Rs. 60 p.m.”

- (2) sub-regulation (4) shall be omitted.

48. Amendment of regulation 151.—In regulation 151 of the said Regulations,—

- (1) In sub-regulation (1)—

for the expression “Rs. 1,320”, the expression “Rs. 2,100” shall be substituted;

- (2) After sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(1A) The payment will be subject to the condition that the air crewman subscribes monthly the difference between Rs. 75 and monthly amount of the premia paid by him for sustaining endowment assurance policy/policies or endowment (Life Insurance Corporation of India or Postal Life Insurance Fund) covering aviation risk also, to the AFPP Fund in addition to the compulsory minimum rate of subscription payable under the normal rules. Such additional subscription in the AFPP Fund will commence from the pay of the month following that in which he qualifies for flying bounty,”;

- (3) in sub-regulation (2), in clause (c), for the expression “Rs. 1,320”, the expression “Rs. 2,100” shall be substituted.

49. Amendment of regulation 152.—In regulation 152 of the said Regulations,—

- (1) in sub-regulation (2), for the expression “Rs. 55”, the expression “Rs. 100” shall be substituted;

- (2) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) In cases where it becomes necessary to preserve the dead bodies of sailors in a mortuary awaiting arrival of the next of kin to take part in the funeral, mortuary charges incurred shall be reimbursed subject to a ceiling of Rs. 35 per day for a maximum period of three days.”.

50. Amendment of regulation 153.—In regulation 153 of the said Regulations,—

- (1) after the words “to sailors”, the words and brackets “(excluding Master Chief Petty Officers I and II)” shall be inserted;

- (2) for the existing Table, the following Table shall be substituted, namely:—

	Rs.	p.	m.
“For one Badge		5	
For two Badges		10	
For three Badges		15.”.	

51. Amendment of regulation 154.—In regulation 154 of the said Regulations,—

- (1) In sub-regulation (1), in the Table.

- (i) against item (a), for the figures “2.50”, the figures “8.75” shall be substituted;

- (ii) against item (b), for the figures “2.00”, the figures “7.00” shall be substituted;

- (2) in sub-regulation (2),

- (i) for the expression “Rs. 2” the expression “Rs. 7” shall be substituted.

- (ii) after the words “during absence without leave”, the words “or leave pending retirement or discharge” shall be inserted.

52. Substitution of regulation 155.—For regulation 155 of the said Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

‘155. *Admissibility and rates.*—(1) Hardly money shall be payable to sailors including those belonging to record parties under the conditions prescribed in sub-regulation (2) of regulation 58 and regulation 60.

(2) The rates of the hardlying money shall be as given below, namely:—

Sailors	Monthly rates	
	Full Rates	Half Rates
	Rs.	Rs.
Master Chief Petty Officers I and II	34	17
Chief Petty Officer	29	14.50
Petty Officer	24	12
Leading/Seaman I and Seaman II	19	9.50
Boys	14	7

Explanation.—Sailors qualified for the grant of hardlying money for 10 days or above in a month shall be allowed the prescribed monthly rates. However, those qualified for a lesser period shall not be entitled to hardlying money for that month."

53. **Omission of regulation 157.**—Regulation 157 of the said Regulations shall be omitted.

54. **Insertion of new regulation 157A.**—After regulation 157 of the said Regulations, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely:—

"HOSTEL SUBSIDY

157-A. *Conditions.*—Sailors who have rendered not less than one year's service and whose pay, including Rank or Appointment Pay and Good Conduct Pay, does not exceed Rs. 349 per month shall receive hostel subsidy at the rates and under the conditions notified from time to time in Government orders in respect of Central Civil Government servants paid from the Defence Services Estimates and also subject to the fulfilment of the following conditions, namely:—

- (1) The hostel subsidy shall be admissible to sailors in respect of their children studying in residential schools under the Central Schools Scheme.
- (2) In the case of sailors whose wives are Central Government servants, the hostel subsidy shall be admissible in respect of one of them only, but it shall not be admissible if the pay of either of them exceeds Rs. 349 per mensem.
- (3) The hostel subsidy shall be admissible while on duty, or on leave, including leave pending retirement, but shall not be allowed to deceased, retired or discharged sailors. If an individual dies or retires or is discharged during the academic session, the hostel subsidy shall be admissible till the end of that academic year. It shall not be admissible in cases of removal from service as a disciplinary measure.

NOTE.—The pay with reference to which the hostel subsidy shall be given, while an individual is on leave, shall be the pay admissible to him at the time he proceeded on leave.

- (4) The child is studying in a school away from the station at which the individual is posted and/or residing.
- (5) The hostel subsidy is admissible only for food charges in the hostel during the academic session and shall not be admissible in respect of lodging, electricity and water charges.
- (6) The hostel subsidy is admissible only to the sailor's legitimate children including step children and adopted children (where adoption is recognised under the personal law of the individual) who are wholly dependent on him.

- (7) The hostel subsidy is admissible for education upto Higher Secondary stage and shall not be paid for more than two academic years in the same class.
- (8) The hostel subsidy is admissible in respect of not more than three children at a time.
- (9) The hostel subsidy is not admissible in respect of a child who is in receipt of a scholarship. It may be allowed if the scholarship offered to the child is not accepted.
- (10) The hostel subsidy shall not be admissible to sailors serving in Missions abroad who receive educational assistance under the Handbook of Rules and Regulations relating to the Indian Foreign Service Rules.
- (11) The hostel subsidy shall not be admissible in respect of children for whom Children's Education Allowance is drawn. The total number of children for whom the hostel subsidy and the Children's Education Allowance is drawn should not exceed four in all.
- (12) Individuals drawing pay in excess of Rs. 349 shall be entitled to a hostel subsidy equal to the amount of hostel subsidy admissible to an individual drawing Rs. 349, reduced by the amount by which their pay is in excess of Rs. 349."

55. Omission of regulations 158 and 159.—Sub-heading "Mineral Water and Ice Allowance" and regulations 158 and 159 of the said Regulations shall be omitted.

56. Amendment of regulation 162.—In regulation 162 of the said Regulations,—

- (1) after clause (a), the sub-heading "Higher Rate" shall be inserted;
- (2) after clause (b), the sub-heading "High Rate" shall be omitted;
- (3) for clauses (d) to (l), the following clause shall be substituted, namely:—

"(d) when travelling by rail or road on leave;

(e) when travelling by rail or road on duty;

NOTE.—To meet unforeseen delays caused by late running and/or congested trains small parties of sailors (i.e. sailors proceeding in a batch on draft from one place to another or a party of sailors proceeding on escort duty) to whom ration allowance is issued in lieu of free rations for the period of the journey shall, in addition, be given a reserve of ration money in advance in the following scale, namely:—

- | | |
|---|--|
| (i) For a journey over 18 hours but not exceeding 24 hours with no change of trains, | One days' advance ration money. |
| (ii) For a journey as (i) above with a change of train | Two days' advance ration money |
| (iii) For a journey of between 24 and 48 hours with one or more changes. | Three days' advance ration money |
| (iv) For a journey of between 48 hours and 72 hours with one or more changes. | Four days' advance ration money |
| (v) For journeys over 72 hours with one or more changes | Five days' advance ration money |
| (f) when employed on movement control duties at a station where they are obliged to take their meals in a refreshment room; | |
| (g) When detained on temporary duty at an outstation or attending camps where rations cannot be supplied by Government | <p>(1) Actual expenses including charges, if any for Deck Bungalows, etc. as certified by the individuals Commanding Officer, subject to a maximum of special rate notified from time to time.</p> <p>(2) Claims for periods in excess of 10 days shall be countersigned by the Commanding Officer of the nearest Naval Establishment.</p> |

NOTE 1.—Advance of ration allowance at full rate per man per day shall be admissible to sailors detailed on temporary duty at an outstation for the anticipated number of days for which they are likely to be detained at outstation.

NOTE 2.—The above ration allowance shall not be admissible to I.N. provost sailors when they are paid out of pocket expenses incurred by them in service while on police duties involving investigations away from their ship or establishment;

(h) when employed on courier duty;

(i) when employed on secret equipment duty;

(j) when patients travel by ambulance convoy or ordinary train, provided free rations are not issued;

(k) when T.B. patients travel on transfer from one Military Hospital to another for further treatment on recommendation of the Medical Board after they have been invalided out of service, provided free rations are not issued;

(l) When on leave At the lower rate shown at clause (a) above;

NOTE 1.—Leave ration allowance shall be drawn in full prior to proceeding on leave.

NOTE 2.—Ration allowance due for any sanctioned period of extension of leave shall be drawn by the sailor on return to his duty station;

<p>(m) When travelling by sea between mainland and Andaman and Nicobar Islands on duty on ships other than Naval ships and when Government is not in a position to provide them passage with diet and Shipping Companies do not issue passage inclusive of diet</p>	<p>Actual expenses incurred and charged for by the Shipping Company for diet during the voyage period as certified by the sailor's Commanding Officer subject to the proviso that no daily allowance or messing allowance shall be admissible in addition."</p>
---	---

57. **Omission of regulation 167.**—Regulation 167 of the said Regulations shall be omitted.

58. **Insertion of new regulations 172A and 172B.**—After regulation 172 of the said Regulations, under the sub-heading 'Ration allowance', the following regulations shall be inserted, namely:—

"172A. Ration Allowance to pensioners or discharged sailors while appearing before a re-survey medical board.—Pensioners or discharged sailors when appearing before a re-survey medical board for re-assessment of their disability which is regarded as attributable to or aggravated by Naval service shall be entitled to free rations or an allowance at the rate of Rupees two per day for the period detained at the station where the medical board is held.

172-B. Ration allowance to pensioners or discharged sailors while attending hospitals etc. in certain cases.—Pensioners or discharged sailors whose disability has been regarded as attributable to or aggravated by Naval service while attending hospitals or centres for repair or renewal of artificial limbs, shall be entitled to free rations or an allowance in lieu thereof at the rate of Rupees two per day for the period detained in hospitals or centres."

59. Amendment of regulation 174.—In regulation 174 of the said Regulations, for the existing Table, the following Table shall be substituted, namely:—

Category	Rs. per annum
3rd Class Survey Recorder	2407
2nd Class Survey Recorder	330
1st Class Survey Recorder (Petty Officers and below)	390
1st Class Survey Recorder (Chief Petty Officer)	450
Master Chief Petty Officer II	510
Master Chief Petty Officer I	570"

60. Amendment of regulation 176.—In regulation 176 of the said Regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"(3) The allowance shall not be admissible in addition to submarine pay."

61. Insertion of new regulation 176A.—After regulation 176 of the said Regulations, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely:—

"SUBMARINE PAY

176-A. Admissibility and rates.—(1) Submarine pay at the following rates shall be admissible to sailors qualified for service in submarine and appointed as part crew or spare crew. It shall also be admissible to those sailors who are otherwise qualified for submarine service and hold appointments which require them as part of their normal duties to go to sea in submarine from time to time:—

Sailors	Rate of Amount per month
Master Chief Petty Officer I and II	Rs. 150
Chief Petty Officer	125
Petty Officer	100
Leading Seaman	90
Seaman I	75
Seaman II	65

(2) Submarine pay shall be treated as pay for all purposes.

(3) Submarine pay shall not be admissible in addition to submarine allowance.

(4) Submarine pay shall cease to be admissible when a sailor—

(a) remains medically unfit for service in submarines for a period exceeding three months;

(b) fails to maintain the requisite standard of efficiency for submarine service, as determined by the Chief of the Naval Staff;

(c) is transferred to a General Service appointment."

62. Insertion of new regulation 177A.—After regulation 177 of the said Regulations, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely:—

"SUBSISTENCE ALLOWANCE

177-A. Subsistence Allowance to Pensioners, Discharged sailors and Relatives of Deceased Sailors.—Subsistence allowance shall be granted to the sailors (serving/discharged pensioners) or the relatives of

deceased sailors at the rates and on the specified occasions as shown below, namely:—

- (a) Pensioners or discharged sailors when appearing before re-survey medical board for re-assessment of their disability which is regarded as attributable to or aggravated by Naval service:—

- | | | |
|---|---|--|
| (i) For the period detained at stations where medical boards are held, | } | Free rations or an allowance in lieu thereof under regulation 172-A; |
| (ii) For the period of transit between their homes and the stations where medical boards are held and <i>vice-versa</i> . | | |

- (b) Pensioners or discharged sailors whose disability has been regarded as attributable to or aggravated by Naval service while attending hospitals or centres for repair or renewal artificial limbs:—

- | | | |
|---|---|--|
| (i) For the period detained in hospitals or centres | } | Free rations or an allowance in lieu thereof under regulation 172-B; |
| (ii) Subsistence allowance for the period of transit from and to their homes and hospitals or centres | | |
| (c) (i) Subsistence allowance to discharged or released sailors while attending investitures held by civil officials for the presentation of medals and decorations | } | Rs. 2/—per day both for the period of transit and halt. |
| (ii) Subsistence allowance to one relative of deceased sailor attending investitures held by civil officials for the presentation of medals and decorations | | |

NOTE.—Grant of allowance in respect of sub-clause (i) and (ii) of clause (c) shall be restricted to a maximum of five days only. The allowance shall not be admissible if the individuals reside at the station where presentation takes place."

63. Amendment of regulation 178.—In regulation 178 of the said Regulations,—

- (1) in sub-regulation (1), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(a) Unit certificate allowance—

- (i) Lower rate—at Rs. 25 per mensem;
(ii) Higher rate—at Rs. 50 per mensem.

(b) Charge certificate allowance—

- (i) Lower rate—at Rs. 50 per mensem;
(ii) Higher rate—at Rs. 75 per mensem;
(iii) Special rate—at Rs. 90 per mensem."

- (2) in sub-regulation (2), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) The special rate shall be admissible for periods of re-engagement beyond fifteen years provided the higher rate has been drawn for a period of two years."

64. Insertion of new regulation 178A.—After regulation 178 of the said Regulations, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely:—

"CASH ALLOWANCE IN LIEU OF SOAP TOILET"

178-A. Sailors (including boys and apprentices), who are authorised to get soap toilet for bathing purpose but are not provided with the same in kind, shall be granted a cash allowance in lieu thereof at the rate of eighty-seven paise per month."

65. Substitution of regulation 187.—For regulation 187 of the said Regulations, the following sub-headings and regulations shall be substituted, namely:—

"ANNUAL RETAINING FEE-OFFICERS

187. Retaining Fee.—Retaining fee at the following rates shall be allowed to the undermentioned categories of officers, namely:—

(1) Short Service Commissioned Officers :—

For each year they are placed on the Emergency List on expiry of their short service contract

Rs. 200/-
per annum.

(2) Indian Naval Reserve/Indian Naval Volunteer Reserve officers :—

For each year of reserve liability.

Rs. 400/-
per annum.

RETAINING FEE FOR FLEET RESERVISTS

137-A. Retaining Fee.—Fleet Reservists or all categories shall be entitled to a retaining fee of Rs. 20 per mensem under the conditions as laid down in Government orders issued from time to time."

66. Insertion of new regulation 191A.—After regulation 191 of the said Regulations, the following regulation shall be inserted, namely:—

"191-A. Monetary rewards.—(1) Gorkha Commissioned officers and sailors of Nepalese domicile in the Navy, who are awarded the gallantry decorations shall receive special lump sum monetary rewards as specified below, namely:—

(a) Param Vir Chakra	Rs. 10,000
(b) Maha Vir Chakra	Rs. 7,500
(c) Vir Chakra	Rs. 3,000

(2) The award of a bar to the medal will not entitle the recipient of the same to a further reward

(3) In the case of posthumous awardees and awardees who died before the receipt of the reward, the lump sum monetary reward shall be paid to their heirs in the order mentioned below, namely:—

- (i) the widow of the deceased;
- (ii) the male lineal descendent of the deceased in the male line of descendent;
- (iii) the unmarried daughters of the deceased;
- (iv) the parents of the deceased."

67. Amendment of regulations 194 to 197.—In regulations 194, 195, 196 and 197 of the said Regulations, for the word "rent" wherever it occurs, the words "Licence fee" shall be substituted.

68. Amendment of regulation 201.—In regulation 201 of the said Regulations, in the Table, before the words "Chief Petty Officer" in the first column and the entries relating thereto in the second and third columns, the following entries shall respectively be inserted, namely:—

	Ordinary	Special
"Master Chief Petty Officer I and II	48.00	61.00."

69. Amendment of regulation 204.—In regulation 204 of the said Regulations, before the words "Chief Petty Officers" wherever they occur, the words "Master Chief Petty Officers and" shall be inserted.

70. Amendment of regulation 208.—In regulation 208 of the said Regulations, in sub-clause (iii) of clause (a), before the words "Chief Petty Officer", the words "Master Chief Petty Officer and" shall be inserted.

71. Amendment of regulation 225.—In regulation 225 of the said Regulations, in clause (a), the following shall be inserted, at the end, namely:—

"If the first day (irrespective of whether it is Sunday) of a month is a public holiday, disbursement of pay and allowances to sailors may be authorised on the last working day before the holiday, by the administrative authorities at their discretion. The administrative authorities may also authorise disbursement of pay and allowances on the last working day of the previous month, if there is no common working day for ships offices and treasuries/bank during the first two days of a month:

Provided that earlier disbursement of pay and allowances is not to be authorised in March, even if the first day of April is a public holiday."

72. Amendment of regulation 232.—In regulation 232 of the said Regulations, in the third proviso, for the portion commencing with the words "Provided also that for a period of 14 years" and ending with the words "the value of the estate permits [including clauses (a) and (b)]", the following shall be substituted, namely:—

"Provided also that for a further period of 10 years commencing from the 1st January, 1966, no recovery of over issue of pay and allowances, advances or other public debts, shall, however, be made from surplus of the estates of a deceased officer except in the following circumstances when such recovery shall be made from the estates or the beneficiary of the estate:—

- (i) if the deceased officer has either left behind a widow and one or more children or was a widower with two or more children and total assets worth more than Rs. 25,000; or
- (ii) if the deceased officer has either left a widow without any child or was a widower with one child only and total assets worth more than Rs. 20,000; or
- (iii) if the deceased officer was unmarried with dependants and total assets worth more than Rs. 15,000; or
- (iv) if the deceased officer was unmarried and has left behind no dependants, irrespective of the value of the estate; subject to the proviso that recovery shall be made only upto the extent of difference between the net value of the assets and the ceilings stipulated in clauses (i), (ii) and (iii) above."

73. Amendment of regulation 233.—In regulation 233 of the said Regulations, in sub-regulation (1), for the words "two rupees" and "four rupees", the words "five rupees" and "ten rupees" shall respectively be substituted.

74. Amendment of regulation 236.—In regulation 236 of the said Regulations,—

- (1) in sub-regulation (1), for the existing Explanation, the following Explanations shall be substituted, namely:—

"Explanation 1.—An advance for the purchase of a conveyance shall not, except with the concurrence of the Ministry of Finance (Defence), be sanctioned unless the outstanding balance in respect of an advance previously granted for the same purpose, together with interest thereon has been fully repaid,

Explanation 2.—Officers likely to proceed or be sent abroad on temporary duty, for courses of instructions, on leave deputation or training etc., shall in no circumstances be granted advance for the purchase of motor cars.

Explanation 3.—Officers serving in operational areas shall not be entitled to advance for the purchase of motor cars";

- (2) In sub-regulation (4), the following Explanations shall be inserted, at the end, namely:—

"Explanation 1.—'Actual price' means the price paid by the officer as cost of the car and the price of such items, which have necessarily to be purchased along with the car (or in other words on the purchase of which the purchaser has no choice, e.g. spare wheel, tyre and tube)

Where, however, certain accessories (e.g. radio in a car, plastic covers) are purchased, which are not essential and which the customer purchases of his own volition, the term 'actual price' shall not cover their cost. Insurance and registration charges shall also not be included in the 'actual price' as these are incurred for running the motor vehicle.

Explanation II—'Actual price' shall also cover the following items in the case of the first purchase:—

(a) the cost of transportation of the conveyance upto the place of duty of the officer concerned at the time of purchase, irrespective of whether the transport is arranged by the distributors or by the officer himself;

(b) the octroi charges actually paid."

75. Amendment of regulation 237.—In regulation 237 of the said Regulations—

(1) in sub-regulation (1), for the existing Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"To whom admissible	Sanctifying authority	Amount admissible
1	2	3
(a) (i) Chief of the Naval Staff (ii) Officers serving with Indian Missions abroad	Government of India	(i) Rs. 16,000, or 16 month pay or the anticipated price of the car, whichever is least ;
(b) Flag officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command Flag Officer Commanding in-Chief, Eastern Naval Command Flag Officer Commanding, Southern Naval Area All Naval Officers (Other than Chief of the Naval Staff.)	Chief of the Naval Staff	(ii) Rs. 13,500, ceiling for officers making purchases of motor cars from countries like U. K. etc. and those who have devalued their currency along with U.K. ; (iii) Rs. 15,750 ceiling in case of purchases of cars from countries who did not devalue their currency along with the U.K. ;
(c) All Naval Officers serving ashore under the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command.	Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command	
(d) All Naval Officers serving ashore under the Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command	Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command	
(e) All Naval Officers Serving ashore under Flag Officer Commanding, Southern Naval Area	Flag Officer Commanding, Southern Naval Area	
(f) Instructional Staff and Student Officers, Defence Services, Staff College, Wellington	Commandant Defence Services Staff College, Wellington.	

1	2	3
(g) Staff and student Officers paid from Defence Services Estimates, National Defence College, NEW DELHI.	} Commandant National Defence College, NEW DELHI	
(h) All Naval Officers serving in Naval Project, VISHAKHAPATNAM		} Director General, Naval Project, VISHAKHAPATNAM

(2) in sub-regulation (2), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

“(c) The grant of advance to officers referred to at item (a) (ii) of the Table to sub-regulation (1), shall be subject to the condition that the advance is applied for by an officer within 12 months of his arrival at the station abroad.”

76. Amendment of regulation 239.—In regulation 239 of the said Regulations, for sub-regulations (4), (5) and (6), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(4) The sanctioning authority shall forward blank forms of agreement and mortgage bond (specimen at Appendices XIB, XIC and XIH) to the officer.

(5) The officer shall complete the form of agreement in the presence of the Commanding Officer of the ship or establishment or other similar authority and forward it along with a certificate as shown in Appendix XI-I and his claim for drawal of advance to the authority who sanctioned the advance. The agreement form and the claim shall be forwarded by the sanctioning authority to the Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay, only on receipt of the certificate from the officer as shown in Appendix XI-I.

(6) The officer shall complete the mortgage bond (vide Appendix XI-C) within one month from the date of drawal of advance in the presence of the Commanding Officer of the ship or Establishment or other similar authority and another officer, hypothecating the vehicle to the President of India as security for the advance and forward the same accompanied by a cash receipt and the bill for the purchase of a conveyance to the Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay, for scrutiny that the advance has been utilised for the purchase of conveyance within the prescribed period and that the ‘actual price’ as defined in regulation 239(4) is not less than the amount of the advance. The cash receipt and the bill shall be returned to the borrower through the Commanding Officer of the Ship or Establishment.

(7) As regards officers serving at Naval Headquarters and Inter-Services Organisations, Commanding Officer, I.N.S. INDIA shall forward all such documents to the Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay.”

77. Amendment of regulation 240.—In sub-regulation (2) of regulation 240 of the said Regulations, for the words “and this time limit of one month shall be strictly adhered to in all cases”, the following words shall be substituted, namely:—

“and the vehicle should be fully insured as prescribed in the succeeding regulations from the date of its purchase. The prescribed time-limit of one month should be strictly adhered to in all cases. This will also apply in the case of second hand vehicles.”

78. Amendment of regulation 241.—In regulation 241 of the said Regulations,—

(1) in sub-regulation (3), in clause (a) of the proviso, for the expression “Rs. 50”, the expression “Rs. 270” shall be substituted:

(2) for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(4) The insurance policies shall bear an endorsement on the forms specified in Appendix XI-E. After purchase of the conveyance the Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay, shall obtain from the officer drawing the advance a letter in the form prescribed in Appendix XI-E addressed to the Insurance Company with which conveyance is insured notifying it that the Government is interested in the insurance policy secured. He shall himself forward this letter to the Insurance Company and obtain the acknowledgment. In case of insurance effected on annual basis, this procedure shall be repeated every year until the advance has been fully repaid to the Government. In cases where the Insurance Company does not issue fresh policy every year and the original policy in which the clauses as in Appendix XI-E already stand inserted is renewed, the Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay, shall ensure that the original policy has been renewed by the Company and the relevant clauses in Appendix XI-E already stand included in the original policy and that the vehicle has been insured for an amount not less than the outstanding amount of the advance plus interest thereon.

(5) Failure to comply with the provisions regarding the execution of mortgage bond and insurance of vehicle as mentioned in this regulation shall render the officer drawing the advance liable to refund forthwith the whole of the amount advanced with interest accrued thereon unless good and sufficient reason is shown to the contrary and the competent authority waives the fulfilment of any of the conditions prescribed above by issue of specific order in writing. The competent authority for the purpose shall be the authority competent to sanction the advance.”.

79. Amendment of regulation 242.—In regulation 242 of the said Regulations,—

(1) for sub-regulations, (1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(1) An officer shall not sell or transfer a motor car for so long as the amount of advance together with interest on such amount is not completely repaid, except with the permission of the sanctioning authority in writing.

(2) If an officer seeks permission to transfer a motor car to another officer who should use a motor car in the discharge of his duties, the sanctioning authority may permit to transfer the liability attached to the car to the latter, provided that the transferee records a declaration that he is aware that the motor car transferred to him remains subject to the mortgage bond and that he is bound by its terms and provisions. The application for sale of a vehicle shall be forwarded to the sanctioning authority through proper channel”.

(2) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(4) A fresh advance shall not be sanctioned to an officer who is permitted to sell his old car in order to purchase a new one. A fresh advance can be sanctioned only when the outstanding balance of the advance in respect of the first car together with interest thereon has been fully repaid.

Explanation 1.—An officer who is permitted by the sanctioning authority to sell his car purchased out of Government advance shall intimate the date of sale to the sanctioning authority and the Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay, as soon as the sale is effected.

Explanation 2.—A specimen of Mortgage Bond for motor vehicle purchased with sale proceeds of an old one before the repayment of the entire advance of money with interest thereon sanctioned by the Government earlier for the purchase of the latter vehicle required under sub-regulation (2) of regulation 242 is given as Appendix XI-J. The fresh Mortgage Bond shall be for the amount then due and not for the amount originally advanced.”.

60. Amendment of regulation 243.—In regulation 243 of the said Regulations,—

(1) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) Advances for motor car shall be recovered as under:—

(a) From officers holding permanent commission. In 1/30th part of the amount advanced. Provided that the recovery of the advance from an officer who is due to retire within 5 or 6 years, as the case may be, from the first issue of pay after the drawal of the advance by him, will be made in such number of instalments as would enable recovery of the advance and interest thereon being completed by the time of the issue of the last pay to him before retirement.

(b) From those holding temporary commissions. Within three years or before the termination of their engagement, whichever is earlier.”

(2) in sub-regulation (4), the following shall be inserted at the end, namely:—

“The fact whether it is possible or advisable to recover the amount by other methods, shall also be considered.”;

(3) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(5A) In case of an officer who is due to retire within maximum period prescribed for its payment, the sanctioning authority may increase the number of instalments if the date of retirement changes after the sanction of the advance consequent on his promotion or grant of substantive rank or grant of another tenure etc., subject to the provisions of sub-regulation (1) of regulation 243. In such cases the officer shall execute a supplementary mortgage deed as prescribed in Appendix XI-K.

(5B) An officer, who is sent on deputation for a period exceeding 12 months out of India or is transferred to a post abroad before an advance drawn by him in India for the purchase of a motor car is completely repaid by him, may, at his option, be allowed by the sanctioning authority to repay the remaining instalments in rupees in India. The officer should arrange to remit the amount due by bank draft, by the 15th of every month in favour of the Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay, in whose book the accounts of the advance in question are kept. A written undertaking shall be obtained from the officer to this effect and from the office to which he is attached abroad. If the draft is not received by the Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay, before the end of the month, he should immediately report the matter for further necessary action to the administrative officer concerned and also to the office abroad where the officer is working. Failure on the part of the officer concerned to remit the bank draft by the due date shall constitute default and render him liable to pay penal rate of compound interest in terms of rule 161 of the General Financial Rules, 1963. On return of the officer to India any amount left unrecovered shall be deducted as before from his monthly pay bills by the Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay.”

(4) in sub-regulation (6), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

“(d) the penal rate of interest shall be the compound rate of interest and it would be merged with the principal at monthly intervals for the purpose of calculation of future rate of interest for the subsequent periods.”.

61. Amendment of regulation 244.—In regulation 244 of the said Regulations, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(g) The date on which an officer on permanent engagement is due to retire or date of expiry of the present engagement in respect of those holding temporary commission.

(h) A certificate from the officer that he is not under orders of transfer or is likely to proceed abroad on temporary duty, courses of instructions or leave."

82. **Substitution of regulation 248.**—For regulation 248 of the said Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"248. **Sanctioning authorities and the amount of advance admissible.**—Officers to whom advances for the purchase of motor cycles are admissible, the authorities empowered to sanction them and the extent of such advances are given in the Table below:—

TABLE

To whom admissible	Sanctioning authority	Amount admissible
(a) All Naval Officer (other than the Chief of the Naval Staff serving at Naval Headquarters.	The Chief of the Naval Staff.	Up to Rs. 3,000 or 10 months' pay or the anticipated price of the motor cycle whichever is the least.
(b) All Naval Officers serving in Naval Shore Establishments outside Naval Headquarters.	(i) the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Bombay; (ii) The Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, Vishakhapatnam; (iii) The Flag Officer Commanding, Southern Naval Area, Cochin; as the case may be	Do.
(c) Naval Officers serving in afloat appointments.	(i) The Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, BOMBAY; (ii) The Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, VISHAKHA-PATNAM; (iii) The Flag Officer Commanding Southern Naval Area, COCHIN as the case may be,	Do.
(d) Instructional staff and student officers, Defence Services Staff College, Wellington.	The Commandant, Defence Services Staff College, Wellington.	
(e) Staff and student officers, paid from Defence Services Estimates, National Defence College, New Delhi.	The Commandant, National Defence College, New Delhi.	

83. **Amendment of regulation 249.**—In regulation 249 of the said Regulations, for the figures and word "48 instalments", the figures and word "60 instalments" shall be substituted,

84. **Substitution of regulation 251.**—For regulation 251 of the said Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"251. **Eligibility.**—Advance for the purchase of bicycles may be granted to all continuous service sailors."

35. Amendment of regulation 253.—In regulation 253 of the said Regulations, for the existing clauses (a) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:—

- “(a) The Chief of the Naval Staff or such officer to whom he may delegate his powers in case of sailors serving at Indian Naval Ship ‘INDIA’.
- (b) The Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Bombay.
- (c) The Flag Officer Commanding, Western Fleet.
- (d) The Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, Vishakhapatnam.
- (e) The Flag Officer Commanding, Southern Naval Area, Cochin.
- (f) The Naval Officer-in-Charge, Goa.”.

36. Amendment of regulation 254.—In regulation 254 of the said Regulations, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

- “(5A) The cash receipt along with details of the conveyance purchased may be submitted to the authorities concerned within one month of the drawal of the advance. If the cash receipt is not produced within the stipulated period of one month, the full amount of the advance together with interest thereon for one month shall be refunded forthwith.”.

37. Insertion of new regulation 257A.—After regulation 257 of the said Regulations, the following sub-headings and regulations shall be inserted, namely:—

ADVANCE OF PAY TO SAILORS AFFECTED BY FLOODS, CYCLONES AND OTHER NATURAL CALAMITIES OF EXCEPTIONAL SEVERITY

257A. Advance of Pay.—All sailors on regular engagement may be granted interest-free advance upto three months' pay (without allowance but including rank/appointment pay and good conduct pay, where applicable) or Rs. 500 whichever is less, in the case of each event when they are affected by floods, cyclones and other natural calamities of exceptional severity which are declared as qualifying for the grant of these concessions by the Central Government subject to the conditions specified below:—

- (i) The advance shall be sanctioned by the Commanding Officers or administrative heads only to those individuals affected by the natural calamity.
- (ii) The amount of advance shall be recoverable in not more than 12 monthly instalments commencing from the second issue of pay after the drawal of the advance. In cases where an individual is not likely to remain in service for 12 months, the sanctioning authority shall direct that the advance be repaid during the anticipated period of effective service. Where the recovery has to be made in shorter time than 12 months, the sanctioning authority may, at its discretion, allow only an amount smaller than is otherwise admissible so that recoveries may not cause undue inconvenience to the recipient of the advance.
- (iii) A second advance on this account shall not normally be sanctioned if an earlier advance for the same purpose remains unadjusted. If, however, the grant of a second advance becomes necessary, the quantum of the second advance plus the outstanding balance of the first advance shall not exceed the limit prescribed above.
- (iv) The advance shall be granted only to those individuals who apply for the relief within 3 months of the issue of the Government orders declaring a natural calamity as qualifying for the grant of the said advance.

ADVANCE OF PAY TO SAILORS, BOYS AND APPRENTICES ON THE EVE OF IMPORTANT FESTIVALS

257B. Eligibility, Drawal of Advances, Conditions, Recovery etc.—(1) All sailors on regular engagement, Boys and Apprentices may be granted advances of pay on the eve of important festivals.

- (2) The amount of the advance shall be Rs. 100 or one month's pay (including Good Conduct Pay, Acting Allowance and Dearness Pay), whichever is less.

- (3) (a) The advance shall be drawn before the festival concerned. It shall be admissible only to those on duty and whose I.R.L. As do not show debtor balance at the time the advance is drawn.
- (b) The advance shall be admissible only on one occasion in a calendar year for members of each community serving in a ship or establishment, even if a festival falls twice in that year. This shall be sanctioned only if the festival advance sanctioned on a previous occasion has been recovered in full.
- (4) The advance shall be recovered in not more than five equal monthly instalments commencing from next month's regular payment. The amount of each instalment shall be rounded off to the nearest rupee, the balance being recovered in the last instalment.
- (5) The Commanding Officer of the ship or establishment shall be authorised to grant advance of pay on such occasions. He shall at his discretion sanction such advances to sailors not serving on a regular engagement who have completed three years service and are likely to continue in service till the adjustment of the advance.
- (6) The occasion for each community shall be determined by the Commanding Officers of the ships and establishments. More than one occasion may, however, be fixed for a community, if in their opinion it is desirable to do so taking into consideration the staff composition of the ship or establishment. The Republic Day and Independence Day may be treated as festival occasions for the purpose of advance of pay."

88. Omission of regulations 259 and 260.—The sub-heading and regulations 259 and 260 of the said Regulations, shall be omitted.

89. Amendment of regulation 261.—In regulation 261 of the said Regulations—

- (1) in the sub-heading appearing above it, for the word "RENT", the words "LICENCE FEE" shall be substituted.
- (2) for the word "rent", the words "licence fee" shall be substituted.

90. Insertion of new Chapter XIII and new regulations 266—272.—After regulation 265 of the said Regulations, the following Chapter and regulations shall be inserted, namely:—

Chapter XIII—Pay and Allowances of Master Chief Petty Officers granted Honorary Commission in the Special Duties List.

Subject	Regulation No.
Rates of Pay	266
Compensatory Allowance	267
Dearness Allowance	268
Outfit Allowance	269
Leave Allowance	270
Other Allowances	271
Advance of Pay	272

266. Rates of Pay.—Honorary Commissioned Officers shall receive the following rates of pay:—

Honorary Sub-Lieutenant (SD)	Rs. 470
Honorary Lieutenant (SD)	Rs. 570

267. Compensatory (City) Allowance.—The Honorary Commissioned Officers shall be entitled to compensatory (city) allowance at stations where it is admissible to sailors, at the full rates admissible to civilians, from time to time.

268. Dearness Allowance.—The Honorary Commissioned Officers shall be entitled to dearness allowance at the rates and under the conditions applicable from time to time to civilian Government servants paid from Defence Service Estimates.

- 269. Outfit Allowance.**—An Honorary Commissioned Officer on the active list shall be granted an outfit allowance equal to the actual cost of the kit, with which he is required to provide himself, subject to a maximum of Rs. 720 provided that vouchers are produced in support of the purchase and his Commanding Officer certifies that the kit is suitable and was purchased under his instructions.
- 270. Leave Allowances.**—The Honorary Commissioned Officers shall in respect of leave allowance be governed by the regulations applicable to sailors.
- 271. Other Allowances.**—The Honorary Commissioned Officers shall not be entitled to any other concessions or allowances in lieu thereof admissible to sailors, e.g., free rations (except where admissible under similar circumstances to commissioned officers while serving afloat), free clothing, kit upkeep allowance, conservancy allowance, hair cutting/hair cleaning and washing allowance.
- 272. Advance of Pay.**—For purpose of advance of pay, the Honorary Commissioned Officers shall be governed by the rules applicable to commissioned officers of the Navy.
- 91. Amendment of Appendix I.**—In Appendix I of the said Regulations, in rule (1),
- (i) in clause (a) for the words "allowances and the like", the words "non-practicing allowance and such other allowances" shall be substituted;
 - (ii) in clause (c), after sub-clause (vi), the following sub-clause shall be inserted, namely:—
 "(vii) Submarine Allowance."
- 92. Amendment of Appendix IV.**—In Appendix IV of the said Regulations,—
- (1) after item (i), the following Note shall be inserted, namely:—
 "NOTE.—Officers substantively promoted to the rank of Commander by time scale who are not held against authorised appointments shall draw a fixed pay of Rs. 1,400 per month:
 Provided that if such officers are appointed to officiate in the vacancies tenable by Commanders (Selective) for a period not exceeding six months at a time, they shall draw the pay admissible to the latter."
 - (2) for item (ii), the following item shall be substituted, namely:—
 "(ii) Captain (Acting or Substantive)—
 Rs. 1550—1610—1670—1730—1850—1950—2050—2150."
- 93. Amendment of Appendix VI.**—In Appendix VI of the said Regulations, in the 1st column of the Tables for the entry "Acting Sub-Lieutenant (SD)", the following entry shall be substituted, namely:—
 "Acting Sub-Lieutenant (SD)
 while on probation/Temporary".
- 94. Amendment of Appendix VIII.**—In Appendix VIII of the said Regulations,—
- (i) in section I,—
 - (a) in the heading, for the expression "Rs. 75 p.m.", the expression "Rs. 100 p.m." shall be substituted;
 - (b) under the sub-heading, "Executive Officers", for items 3 and 4 the following items shall be substituted, namely:—
 "3. Long Torpedo Anti-Submarine Course (TAS)
 4. Long Navigation and Direction Course (ND)"
 - (c) Under the sub-heading "Electrical Officers" after item 9, the following item shall be inserted, namely:—
 "9A. Advanced Ordnance Engineering Course U.K."
 - (d) under the sub-heading "Instructor Officers" after entry 13, the following entries shall be inserted, namely:—
 "13A. Navigation and Direction Course (ND)
 13B. Long Communication Course (C)"

- (e) under the sub-heading "Naval Aviation Officers", after item 18, the following items shall be inserted, namely:—
 "11A. Qualified Navigation Instructors category A and A.2".
- (f) in entry 24, after item (c), the following items shall be inserted, namely:—
 "(d) Institution of Telecommunication Engineers (India), if obtained after passing the Graduateship Examination held by that Institution. (For officers other than those of the Engineering Branch and of the Civil Engineering Directorate);
 (e) Institution of Electronics and Radio Engineers, London (for officers of the Electrical Branch only).".
- (ii) in Section II—
 (a) in the heading, for the expression "Rs. 50 p.m.", the expression "Rs. 70 p.m." shall be substituted;
 (b) under the sub-heading "Naval Aviation Officers", after item 2, the following item shall be inserted, namely:—
 "2A. Navigation Instructors Category 'B'".
 (c) for entry 9, the following entries shall be substituted, namely:—
 "9. A pass of Sections 'A' and 'B' of the Associate Membership Examination of the Institution of Engineers (India) or any Engineering Degree or qualification which the Institution of Engineers (India) recognises for exemption from Sections 'A' and 'B' of its Associate Membership Examination.
 9A. A pass in Graduate Membership examination of the Institution of Telecommunication Engineers (India) (for officers other than those of the Engineering Branch and of Civil Engineering Directorate).
 (d) for the sub-heading "Instructor Officers" above item 13, the sub-heading "Education Officer" shall be substituted.
- (iii) in the heading to Section III, for the expression "Rs. 1,800", the expression "Rs. 2,400" shall be substituted;
- (iv) in the heading to Section IV, for the expression "Rs. 1,200" the expression "Rs. 1,600" shall be substituted.
- 95. Amendment of Appendix IX.**—In Appendix IX of the said Regulations,—
 (i) under the heading "Group 'A', in the Table, after existing entries, the following entries shall be inserted, namely:—
 "Master Chief Artificer II Master Chief Mechanician II—227—10—307
 Master Chief Artificer I Master Chief Mechanician I—317—10—347".
- (ii) under the heading "Group 'B' (Matriculate Entry)—
 in the Table,
 (a) in the first column, for the words "Sick Berth Attendants", the words "Medical Assistants" shall be substituted.
 (b) under the second and third columns, after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely:—
 "Master Chief Petty Officer II—190—10—210.
 Master Chief Petty Officer I—220—10—250".
 (c) the following Note shall be inserted at the end, namely:—
 "NOTE.—On acquiring any of the specialist qualifications given below, Medical Assistants shall, for the purpose of pay, be upgraded from Group 'B' to rates of pay admissible to corresponding categories of Naval Aviation Sailors:—

Name and specialist qualification Courses	Class
1	2
1. Advanced Nursing	I & II
2. Medical Stores	I & II

I	2
3. Laboratory Assistant and Laboratory Technician	I & II
4. Operating Room Technician	I & II
5. Radiography (X-Ray) assistants and/or Technician	I & II
6. Special Diseases	I & II
7. Physiotherapy	I & II
8. Hygiene	I & II
9. Psychiatric Nursing	I & II
10. Dental Operating Room Assistant	I & II
11. Blood Transfusion Assistant	I & II
12. Dispenser	I & II
13. Dental Technician and/or Dental Hygienist	I & II."

(iii) under the heading "Group 'C'", in the Table, under the second and third columns, after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely:—

Master Chief Petty Officer II	190—10—210
Master Chief Petty Officer I	220—10—250'.

(iv) under the heading "NAVAL AVIATION SAILORS", under entry (b), in the Table, under the second and third columns, after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely:—

"Master Chief Petty Officer II	252—10—282
Master Chief Petty Officer I	292—10—322."

56. **Amendment of Appendix XI-B.**—In Appendix XI-B of the said Regulations, for paragraph 2 of the form, the following para shall be substituted, namely:—

"2. In witness whereof the Borrower has hereunto set his hand and Shri _____ (Designation) _____ in the Ministry/Office of _____ for and on behalf of the President has hereunto set his hand."

97. After Appendix XI-G of the said Regulations, the following Appendices shall be inserted, namely:—

Case No. 80-1/69/1238/D (Pay/Services) Ministry of Finance (Defence) 1932-NA/1973.

M. L. DAVE,

JS (P&W)

"APPENDIX XI-H (See regulation 239)

Form of Agreement to be executed at the time of drawing an advance for the purchase of a motor vehicle (to be used only when purchase is made before receiving the advance by raising a private loan in accordance with Regulation 239 in other cases Appendix XI 'B' will be used)

AN AGREEMENT made on _____ day of _____ one thousand nine hundred and _____ between _____ (hereinafter called the Borrower, which expression shall include his heirs, executors, administrators and legal representatives) of the one part and the President of India (hereinafter called the President, which expression shall include his successors and assignees) of the other part.

WHEREAS the Borrower has purchased/agreed to purchase the motor vehicle described in the Schedule hereunder written (hereinafter referred to as the "said motor vehicle").

AND WHEREAS the Borrower has under the provisions of the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 1966 (hereinafter referred to as the said regulations, which expression shall include any amendments thereof for the time being in

force) applied to the President for a loan of Rs. for the purchase of a motor vehicle.

AND WHEREAS the President has agreed to lend the said amount to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained.

NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto that in consideration of the sum of Rs. paid by the President to the Borrower (the receipt of which the Borrower hereby admits and acknowledges), the Borrower hereby agrees with the President (1) to repay to the President the said amount with interest calculated according to the said regulations by monthly deductions from his salary as provided for by the said regulations and hereby authorises the President to make such deductions and (2) within one month from the date of these presents to expend the full amount of the said loan in the repayment of loan obtained by him from a private party/the (Bank) for the purchase of the said motor vehicle or if the actual price paid or private loan taken is less than the loan, to repay the difference to the President forthwith and (3) to execute a document hypothecating the said motor vehicle to the President as security for the amount lent to the Borrower as aforesaid and interest in the form provided by the said regulations and IT IS HEREBY LASTLY AGREED AND DECLARED THAT IF THE MOTOR VEHICLE has not been purchased and hypothecated as aforesaid within one month from the date of these presents or if the Borrower fails to repay the amount of the loan obtained by him from a Private party/..... Bank for the express purpose of purchasing the said motor vehicle within one month from the date of these presents or if the Borrower within that period becomes insolvent or quits the service of the Government or dies the whole amount of the loan and interest accrued thereon shall immediately become due and repayable.

THE SCHEDULE

Description of motor vehicle.

Maker's Name.

Description.

No. of Cylinders.

Engine No.

Chassis No.

Cost Price.

IN WITNESS WHEREOF the Borrower has hereunto set his hand and Shri _____ in the Ministry/Office of _____ for and on behalf of the President has hereunto set his hands.

*Signed by the said in the presence of

(Signature of Witness)

(Signature and designation of the Borrower)

Signed by (Name and designation)

(For and on behalf of the President of India) in the presence of

(Signature of Witness)

(Signature and designation of the officer)

APPENDIX XI-I

(See Regulation 239)

I hereby certify that the vehicle is available and I shall be able to purchase the vehicle within one month of the date of issue of the cheque. In case the purchase of vehicle is not made within one month of the date of issue of the cheque I shall refund the full amount of the advance together with interest in one lump sum.

Place _____
Date _____

(Signature and designation of the Borrower).

*Name and designation of the Borrower.

APPENDIX XI-J

(See regulation 242)

Form of Mortgage Bond for Motor Vehicle purchased with sale proceeds of an old one before the repayment of the entire advance of money with interest thereon sanctioned by Government earlier for the purchase of the latter vehicle

THIS INDENTURE made this _____ day of _____ BETWEEN Shri _____ son of _____ (herein after called 'the Borrower' which expression shall, unless excluded by or repugnant to the subject or context, include his heirs, administrators, executors and legal representatives) of the ONE PART and the President of India (hereinafter called 'the President' which expression shall, unless excluded by or repugnant to the subject or context, include his successors in office and assignee) of the OTHER PART.

WHEREAS by a Deed of Mortgage, dated the _____ day of _____ the Borrower mortgaged to the President the Motor Vehicle described in the Schedule thereto (hereinafter referred to as 'the old Motor Vehicle') to secure the advance of Rs. _____ (in words as well as in figures) taken for purchase of the old motor vehicle with interest thereon at the rate and on condition mentioned in the said Deed of Mortgage (hereinafter referred to as the 'Principal Deed').

AND WHEREAS out of the said sum of Rs. _____ advanced to the Borrower by the President, the Borrower has made part repayments and a sum of Rs. _____ (in words as well as in figures) towards principal plus interest thereon as per the terms of the Principal Deed still remain due and payable by the Borrower to the President.

AND WHEREAS the Borrower being in need of a new Motor Vehicle (hereinafter referred to as the new Motor Vehicle) applied to the President for permission to sell his old Motor Vehicle and purchase a new one AND WHEREAS the Borrower has been permitted to sell the old Motor Vehicle and utilise the sale proceeds of the old motor vehicle in terms of Regulation 242 of the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 1968 (hereinafter referred to as "the said regulations" which expression shall include any amendment thereof or addition thereto for the time being in force) towards the purchase of the new Motor Vehicle on condition that the new Motor Vehicle shall be mortgaged to the President by way of security for the repayment of the sum thus due and owing from the Borrower to the President AND WHEREAS the sum of Rs. _____ is now due and owing from the Borrower for principal AND WHEREAS the Borrower is liable in addition to pay interest as per the terms of the Principal Deed.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and for the consideration aforesaid the Borrower doth hereby covenant to repay to the President the sum of Rs. _____ aforesaid by equal monthly instalments of Rs. _____ each on the first day of every month and will pay interest on the sum of Rs. _____ originally advanced to him (hereinafter referred to as Principal) according to the terms of the Principal Deed and the Borrower doth agree that such payments may be recovered by monthly deductions from his salary in the manner provided by the said regulations, and the Borrower doth hereby authorise the President to make such deductions and in further pursuance of the said agreements, the Borrower doth hereby assign and transfer unto the President the Motor Vehicle the particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written by way of security for the said advance and the interest thereon as required by the said regulations.

AND the Borrower doth hereby agree and declare that he has paid in full the purchase price of the said Motor Vehicle and/or the entire amounts duly payable and that the same is his absolute property and that he has not pledged, hypothecated or mortgaged and so long as any money remain payable to the President in respect of the principal will not sell or pledge or hypothecated or mortgage or part with the property in or possession of the said Motor Vehicle. PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed and declared that if any of the said instalments of the principal or interest shall not be paid or recovered in manner aforesaid within 10 days after the same are due or if the Borrower shall die or at any time cease to be in Government service or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or possession of the said Motor Vehicle or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgment against the Borrower the balance of the principal which shall then

be remaining due and unpaid together with interest on principal calculated as aforesaid shall forthwith become payable AND IT IS HEREBY AGREED and declared that the President may on the happening of any of the events herein-before mentioned seize and take possession of the said Motor Vehicle and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove and sell the said Motor Vehicle either by public auction or private contract and may out of the net sale proceeds retain the balance of the principal amount then remaining unpaid and any interest still due, the principal calculated as aforesaid and all costs, charges, expenses and payments properly incurred or made in maintaining, defending or realising his rights hereunder and shall pay over the surplus, if any, to the Borrower, his executors, administrators or personal representatives PROVIDED FURTHER that the aforesaid power of taking possession or selling of the said Motor Vehicle shall not prejudice the right of the President to sue the Borrower or his personal representatives for the said balance remaining due and interest or in the case of Motor Vehicle being sold the amount by which the net sale proceeds fall short of the amount owing AND the Borrower hereby further agrees that so long as any moneys are remaining due and owing to the President he, the Borrower will insure and keep insured the said Motor Vehicle for the full value of the Motor Vehicle against any loss or damage by fire, theft or accident with one of the Insurance Companies to be approved by the Controller of Defence Accounts (Navy) and will produce evidence to the satisfaction of the Controller of Defence Accounts (Navy) that the Company with whom the said Motor Vehicle is insured have received notice that the President is interested in the Policy AND the Borrower hereby further agrees that he will not permit or suffer the said Motor Vehicle to be destroyed or injured or to deteriorate in a greater degree than it would deteriorate by reasonable wear and tear thereof AND further that in the event of any damage or accident happening to the said Motor Vehicle, the Borrower will forthwith keep the President informed and have the same repaired and made good so as to restore the same in its previous condition.

THE SCHEDULE

Description of Motor Vehicle

Maker's Name

Description

No. of Cylinders

Engine Number

Chassis No.

Cost Price

IN WITNESS WHEREOF THE Borrower has hereunto set his hand and Shri _____ in the Ministry/Office of _____ for and on behalf of the said President has hereunto set his hand.

*Signed by the said in the presence of

1. _____

2. _____

(Signature of Witnesses)

Signature and designation of the
Borrower)

Signed by (Name and designation)

(For and on behalf of the President of India)
in presence of

1. _____

2. _____

(Signature of Witnesses)

(Signature and designation of the
Officer)

*Name and designation of the Borrower.

APPENDIX XI-K

(See regulation 243)

Form of Supplementary Mortgage Bond for Motor Vehicle Advance

THIS AGREEMENT made this _____ day of _____ 19____ between _____ (hereinafter called 'the Borrower' which expression shall include his heirs, administrators, executors and legal representatives) of the ONE PART and the President of India (hereinafter called 'the President' which expression shall include his successors and assignees) of the OTHER PART is supplemental to the deed of hypothecation dated the _____ between the said parties (hereinafter referred to as the said 'original deed').

WHEREAS the Borrower applied for and was granted an advance of Rs. _____ to purchase a motor vehicle on the terms of Navv (Pay and Allowances) Regulations 1960 (hereinafter referred to as the said regulations).

AND WHEREAS pursuant to the terms of the said advance the Borrower by the said original deed covenanted to repay to the President the said sum of Rs. _____ or the balance thereof remaining unpaid by instalments as mentioned below, namely the first -- -- instalment at Rs. _____ each, the next -- -- instalments at Rs. _____ each and the next instalments at Rs. _____ each, AND THAT as security for such payments, the Borrower by the said original deed assigned and transferred unto the President the motor vehicle the particulars whereof are set out in the Schedule to the said original deed and also in the Schedule hereunder by way of security as therein and provided.

AND WHEREAS the Borrower has applied to the Government for variation in the instalments agreed to and accepting recovery by _____ instalments of Rs. _____ each instead of _____ instalments as originally fixed.

AND WHEREAS a sum of Rs. _____ is now due and owing from the said Borrower to the Government.

AND WHEREAS the Government has agreed to the said proposal on terms and conditions hereinafter stated.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and in consideration of the promises the Borrower doth hereby covenant to pay to the President the outstanding sum of Rs. _____ out of the total loan of Rs. _____ by instalments of Rs. _____ each payable on the first day of every month commencing from _____ and will pay interest on the sum for the time being remaining due and owing calculated according to the said regulations.

AND IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED that the covenant, powers and provisions contained in the said original deed in regard to the instalments payable under the said original deed shall apply to the instalments payable under these presents and except as varied hereby all the terms and conditions of the said original deed shall remain in full force and effect.

SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

IN WITNESS WHEREOF _____ the Borrower has signed these presents and the President has caused _____ to sign these presents for and on his behalf the day/month and year first above written.

Signed and delivered by _____ Signed and delivered by _____
for and on behalf of the President of India in the
presence of
the Borrower in the
presence of

1. _____

1. _____

2. _____

2. _____

M. L. DAVE,
Jt. Secy. (P&W).